

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वर्ष 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति कायम रही और वैश्विक व्यापार के लिए संभावनाएं अब सकारात्मक होती जा रही हैं। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होने के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोष (ट्रेजरी) प्रतिफल और बंधक (मॉर्गेज) दरें बढ़ रही हैं। भारत में, मजबूत निवेश मांग और उत्साहित व्यापार और उपभोक्ता भावनाओं द्वारा समर्थित वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में रुझान में तेजी के लिए स्थितियां बन रही हैं। पिछले दो महीनों में औसतन 5.1 प्रतिशत के बाद मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हालांकि, निकट भविष्य में, चरम मौसम की घटनाएं मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं और साथ ही लंबी अवधि का तक भू-राजनीतिक तनाव कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर कर सकते हैं।

I. भूमिका

वर्ष 2024 के वसंत में कुछ गर्मी है। वैश्विक मौसम एजेंसियाँ इस बात पर सहमत हैं कि मार्च 2024, 1850 में अभिलेखीकरण के बाद से सबसे गर्म मार्च था - वैश्विक सतह का तापमान 1880-1899 की अवधि से 1.6 डिग्री सेल्सियस (3.01 डिग्री फ़ारेनहाइट) अधिक था। मौसम के बारे में बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी, लेकिन दुनिया भर में आर्थिक गतिविधि भी तेज़ होती दिख रही है। 2023 की अंतिम तिमाही में उछाल के बाद, 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति कायम है; यहाँ तक कि अगले भाग में प्रस्तुत हमारा तात्कालिक अनुमान भी केवल एक मामूली मंदी का सुझाव देता है। यू.के. में तकनीकी मंदी को छोड़कर हर जगह, जीडीपी शुरुआती आँकड़ों और आधिकारिक लक्ष्यों से ऊपर आ रहा है। एक संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद, आप्रवासन कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, विश्वजीत मोहंती, सत्यम कुमार, शशि कांत, कुणाल प्रियदर्शी, गरिमा वाही, थांगजासोन सोना, पंकज कुमार, हरेन्द्र बेहरा, जेसिका मारिया एंथनी, ऋषभ कुमार, सत्येन्द्र कुमार, खुशी सिन्हा, आकाश राज, ऐडम अभिन्नु यादव, प्रतिभा केडिया, साई धीरज वायुगुंडला चेंचू, युवराज कश्यप, आरती सिन्हा, सौरज्योति सरदार, अरानिका कुंडू, श्रेया गुप्ता, अक्षरा अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(ईई) में गतिविधि को बनाए रखने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और कार्यबल का विस्तार करने में मदद कर रहा है। अप्रैल वैश्विक पूर्वानुमान अपडेट का महीना है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रतिष्ठित पूर्वानुमानकर्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती से चकित हैं। शायद 2024 के नतीजे उन्हें झुठलाएंगे, जैसा कि 2023 में हुआ था। जैसा कि अगले भाग में बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) के अनुसार, वैश्विक व्यापार के लिए संभावनाएं सकारात्मक हो रही हैं, जो 2023 में देखे गए संकुचन को उलट देगा, हालांकि रसद और परिवहन व्यवधानों से व्यापक जोखिमों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अपने अक्टूबर 2023 के पूर्वानुमान से 2024 के लिए अपने व्यापारिक व्यापार की मात्रा वृद्धि को संशोधित किया, लेकिन मुद्रास्फीति के दबाव कम होने और वास्तविक परिवार (हाउसहोल्ड) आय में सुधार होने पर मांग में उछाल आने की उम्मीद है। वाणिज्यिक सेवाओं में व्यापार की संभावनाएँ 2023 में देखी गई मजबूती को बनाए रखने और व्यापारिक व्यापार दृष्टिकोण से जुड़े कुछ जोखिम कारकों को ऑफसेट करने के लिए तैयार हैं।

केंद्रीय बैंक ब्याज दर की उलझन से निपटने के दौरान 2024 में संवृद्धि की संभावनाओं के बारे में सतर्क लहजे में बात करते हैं, लेकिन 'फ्रायडियन स्लिप्स' की तरह, कभी-कभी उनके कार्यों से अंतर्निहित वैश्विक स्थिति का उनका आकलन झलक जाता है। ऋणात्मक ब्याज दरों और उनके अनपेक्षित परिणामों से बाहर निकलने के लिए अभिशासन (रेजीम) में बदलाव हो रहे हैं। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें उन स्थानों पर कम की जा रही हैं, जहां अभी तक कटौती शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यह जोखिम है कि यदि मुद्रास्फीति में तेजी के कारण आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से इसमें फिर से वृद्धि होती है, तो यह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है और विध्वंसकारी हो सकती है। स्विटजरलैंड ब्याज दरों में कटौती करने वाला पहला ईई बन गया, जो मुद्रा के मूल्य वर्धन के प्रति सतर्कता और संवृद्धि गुट में शामिल होने की उत्सुकता को दर्शाता है, यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति सहन-दायरा के भीतर है।

उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, जिन्हें लंबे समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है, ने हाल के वर्षों की उथल-पुथल का सामना किया है। महामारी के बाद

आर्थिक बहाली में उनकी सफलता के लिए बाज़ार उन्हें लाभ देना शुरू कर रहे हैं। इनमें सिर्फ़ इंडोनेशिया और भारत जैसे उभरते हुए पावरहाउस ही नहीं शामिल हैं, बल्कि वे भी शामिल हैं जो 2022 तक उच्च मुद्रास्फीति, ऋण, राजकोषीय घाटे और पूंजी के पलायन से त्रस्त थे, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया और उनकी मुद्राएँ उगमगाने लगीं। शायद यह उनकी ताकत ही है जो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता को मजबूत कर रही है। निष्क्रिय निवेशकों की बढ़ती संख्या उभरते बाज़ारों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में फिर से निवेश कर रही है - मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ईएम एक्स-चाइना इंडेक्स अपने समकक्ष उप-सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ़्लो प्रॉक्सी इंडेक्स पहले ही अपने दस साल के औसत से 150 अंक ऊपर है। जैसे-जैसे पूंजी प्रवाह वापस आ रहा है, बॉण्ड प्रीमियम में गिरावट आ रही है और उभरती दुनिया में मुद्रा डिस्काउंट कम हो रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत महसूस कर रही है।

वित्तीय बाजारों में, ट्रेजरी प्रतिफल और मॉर्गेज दरें बढ़ रही हैं क्योंकि बाजारों को एहसास हो रहा है कि कटौती पर उनके दांव समय के साथ पीछे धकेले जा रहे हैं। कॉरपोरेट, कई वर्षों के उच्चतम प्रतिफल और तंग स्प्रेड का लाभ उठाने के लिए बॉण्ड जारी करने की जल्दी कर रहे हैं, जिसमें जंक पेपर भी शामिल है जो कई वर्षों के निचले स्तर पर है - मतलब मौका देखकर चौका मारना। भले ही कुछ कमोडिटी की कीमतें - खाद्य तेल एक उल्लेखनीय अपवाद हैं - कम हो रही हैं, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और ओपेक+ द्वारा वर्ष की पहली छमाही के लिए आपूर्ति में कटौती के साथ बने रहने के कारण कच्चे तेल की कीमतें मजबूत हुई हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ओपेक+ ने बाजार पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ईंधन की मांग आश्चर्यजनक रूप से लचीली बनी हुई है, जिससे 2024 में विश्व तेल की मांग 2.25 मिलियन बैरल प्रति दिन पर बनी रहने की उम्मीद है। यह मौद्रिक नीति को सहज बनाने में एक और बाधा है। तदनुसार, सुरक्षित आश्रय की मांग के कारण अमेरिकी डॉलर में उछाल आया है। चार्ट पर, इसका निकट-अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स (डीएक्सवाई)

के लिए 104 के समर्थन से ऊपर की ओर खुला है। जबकि अन्य मुद्राएं इस उछाल से उबरने के लिए संघर्ष कर रही हैं, स्वर्ण की कीमतों में चमक वापस आ गई है। 2024 में, वैश्विक शेयर बाजारों ने पांच वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ पहली तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया है, जो जाहिर तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बूम द्वारा प्रेरित है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण चिप डिजाइनर एनवीडिया के स्टॉक हैं, और आर्थिक प्रदर्शन में बढ़ते विश्वास से है। एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स पहले ही 10 प्रतिशत के करीब बढ़ चुका है, जो 2020 के बाद से किसी भी तिमाही में सबसे बड़े अंतर से बॉण्ड से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट "स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023" में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस बात की काफी संभावना है कि 2024, 2023 में निर्धारित सबसे गर्म वर्ष की सीमा को पार कर जाएगा, जबकि दुनिया मीठे पानी की कमी के संकट की ओर बढ़ रही है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार, "भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़े चरम मौसमी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को दर्शाते हैं, जिसके लिए तत्काल और सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।" इन भयावह पूर्वानुमानों के बीच उम्मीद भी है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो और यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फियर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, ला नीना - जिसके परिणामस्वरूप भारत में भारी वर्षा होती है - की संभावना जून के बाद उभर रही है, जबकि अल नीनो खत्म हो रहा है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, अगले पाँच वर्षों में वैश्विक बिजली विस्तार में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 90 प्रतिशत होने की संभावना है, जबकि 2025 तक वैश्विक बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। भारत इस बदलाव में अग्रणी रहा है, जिसने 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा में 2014 और 2021 के बीच अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 250 प्रतिशत की वृद्धि की है। भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर रहा है ताकि आर्थिक संवृद्धि से उत्सर्जन

को अलग किया जा सके। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में क्षेत्रीय विविधताओं का दोहन करने के लिए प्रत्येक राज्य की विशिष्ट विशेषताओं और क्षमता के अनुरूप रणनीतियों को तैयार करना शामिल होगा। कई पहलों में से, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और हरित ऊर्जा गलियारा अंतर-राज्यीय संचरण प्रणाली भारत के ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन में सबसे आगे हैं। एक प्रभावशाली दृष्टिकोण से, जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सबसे बड़े संकटों में से एक है, लेकिन यह विकास प्रतिमान को बदलने का सबसे बड़ा अवसर भी है।¹

भारत में, रुझान में तेजी के लिए स्थितियां बन रही हैं, जिसने 2021-24 के दौरान औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8 प्रतिशत से ऊपर पहुंचा दिया। अगले तीन दशकों में अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले दशक में 8-10 प्रति वर्ष की दर से बढ़ना चाहिए ताकि 2018 से शुरू होने वाले जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके और, जैसा कि गणना से पता चलता है, यह 2055 तक चलेगा। अब तक, पूंजी गहनता संवृद्धि पथ में कदम बढ़ाने को शक्ति प्रदान कर रही है, जिसका नेतृत्व निरंतर सार्वजनिक निवेश और उत्पादकता में सुधार द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार, निजी निवेश में पुनरुत्थान दिखाई देने लगा है, जो निजी पूंजी के लिए जगह का विस्तार करने के लिए अपनी निवेश रणनीति बदल रहा है।² स्थितियाँ उपयुक्त हैं, भारतीय कॉर्पोरेट्स की क्रेडिट गुणवत्ता डेलेवरेज्ड बैलेंस शीट, निरंतर घरेलू मांग और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के बल पर मजबूत हुई है - रेटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड से आगे निकल गए हैं।³ भारत के क्लेम्स⁴ वृद्धि लेखांकन ढांचे के भीतर विश्लेषण से पता चलता है कि

भारत में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि में स्थिर पूंजी स्टॉक का योगदान उस निम्न से सुधरना शुरू हो गया है, जो महामारी के दौरान घट गया था। 2021-22 तक, जीवीए की वृद्धि में इसका योगदान 32 प्रतिशत तक बढ़ गया था, हालाँकि महामारी-पूर्व स्तरों की तुलना में इसे प्राप्त करने के लिए अभी भी पकड़ बनानी है। कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) 2018-21 के दौरान गिरावट के बाद महामारी के बाद की अवधि में जीवीए वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण चालक बन गया है। 2021-22 तक, इसने जीवीए की वृद्धि का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा लिया। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में टीएफपी वृद्धि में सुधार हुआ, जिसमें सेवाओं में सबसे तेज़ वृद्धि देखी गई।

मध्यम आय अवरोध को तोड़ने के लिए आवश्यक पलायन वेग प्राप्त करने के लिए, अगले कुछ दशकों में विकासात्मक रणनीति को जीवीए की वृद्धि में अपने युवा और बढ़ते श्रम बल के अधिकतम संभव योगदान को निकालने के इर्द-गिर्द केंद्रित होना चाहिए। रोजगार क्षमता बढ़ाना - कौशल का वह समूह जो किसी व्यक्ति को व्यक्ति, कार्यबल, समुदाय और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए चुने गए व्यवसाय में रोजगार पाने की अधिक संभावना बनाता है - युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों के मूर्त रूप देने पर ध्यान केंद्रित करना रणनीति की पहचान बनी रहनी चाहिए। 2021-31 के दौरान लगभग 9.7 मिलियन प्रति वर्ष और 2031-41 के दौरान 4.2 मिलियन प्रति वर्ष की दर से कार्यशील आयु की आबादी का विस्तार होने वाला है, विकास रणनीति की अत्याधुनिकता श्रम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके प्रदान की जाएगी। जबकि पिछले वर्षों में श्रम गुणवत्ता में धीमी वृद्धि हुई है, यानी 1980 और 2021 के बीच प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत की दर से, इस बात के बढ़ते प्रमाण हैं कि 2017-18 से कुल श्रम गुणवत्ता की वृद्धि दर में सुधार हुआ है। सेवा क्षेत्र इस सुधार को आगे बढ़ा रहा है, हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में श्रम गुणवत्ता ने 2019-20 में वृद्धि के बाद धीमापन के उपरांत वृद्धि को बनाए रखा है। दोनों क्षेत्रों में, लगभग हर शैक्षणिक श्रेणी में वेतन आय (शिक्षा पर प्रतिफल के रूप में देखा जाता है) में वृद्धि से इसका समर्थन किया गया है, लेकिन विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा और उससे उच्च

¹ मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक, आईएमडी, और कैटलिन विसेन, निवासी प्रतिनिधि, यूएनडीपी, भारत।

² एडीबी, एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) अप्रैल 2024।

³ क्रिसिल रेटिंग क्रेडिट अनुपात।

⁴ पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं।

की शिक्षा वाले लोगों के बीच वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) तेजी से भारत के प्रतिभा पूल में निहित राजस्व अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस लाभ को नवाचारों, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं और समाधानों और दुनिया भर में डेटा-संचालित व्यापार मॉडल के रूप में असाधारण मूल्य प्रदान करने में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नतीजतन, जीसीसी द्वारा भर्ती ने सकारात्मक रुझान बनाए रखा है।

भारत की संवृद्धि-महत्वाकांक्षाओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण विकास हाल के प्रिंटों में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का विकास है। जनवरी 2024 से शुरू होकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी विकास आवेगों को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि खंड III इंगित करेगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 5.7 प्रतिशत के हालिया शिखर के बाद पिछले दो महीनों में औसतन 5.1 प्रतिशत के बाद मार्च में 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह प्रक्षेपवक्र प्रत्याशित रेखाओं के अनुरूप था, जिसमें ति4: 2023-24 मुद्रास्फीति परिणाम अनुमानों के अनुरूप 5.0 प्रतिशत था। मार्च में कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर नरम होने, जो वस्तुओं और सेवाओं के घटकों में नरमी द्वारा संचालित है, मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति के संचालन को विश्वसनीयता प्रदान करता है। अंततः 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति के साथ, अब अधिक विश्वास है कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य तक पहुँचना आसन्न है। कुछ हद तक नरमी के संकेतों के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और मुद्रास्फीति के प्रक्षेप पथ के लिए जोखिम का एक संभावित स्रोत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वानुमानित इस वर्ष सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले, खाद्य मूल्य के दबाव को कम करने में सक्षम होने से पहले, गर्मियों के दौरान सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि खाद्य मूल्य के दबाव को कम करने में सक्षम होने से पहले, ओवरलैपिंग खाद्य मूल्य झटके होते हैं। हालांकि, निकट भविष्य में, चरम मौसम की घटनाएं मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, साथ ही लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव भी हो सकता है जो कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर रख सकता है। कुल

मिलाकर, अनुमान आने वाले महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में और कमी का संकेत देता है, इससे पहले कि वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान प्रतिकूल आधार प्रभाव शुरू हो जाए, जिसे दूर करना होगा। जबकि मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ संरेखण धीरे-धीरे हो रहा है, आने वाले डेटा मुद्रास्फीति के मार्ग पर अधिक स्पष्टता और विश्वास प्रदान करेंगे।

01 अप्रैल, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने 90वें वर्ष की शुरुआत का जश्न मनाएगा। एक निजी संयुक्त स्टॉक संस्थान के रूप में इसकी शुरुआत से लेकर आज के आधुनिक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक तक का यह सफर बहुत ही घटनापूर्ण रहा है। इसके विकास के कई विशिष्ट पहलुओं पर पहले ही सार्वजनिक चर्चा में चर्चा हो चुकी है। शायद इस आलेख में दो पहलुओं का उल्लेख किया जाना चाहिए।

भारत के वित्तीय क्षेत्र की संस्थागत मजबूती में आरबीआई की विकासात्मक भूमिका का बहुत बड़ा योगदान है। देश के हर कोने में बैंकिंग सेवाओं के तेजी से विस्तार को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के अलावा, आरबीआई के भीतर कई राष्ट्रीय स्तर के विकास वित्तीय संस्थानों को इसके विभागों या सहायक कंपनियों के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें आरबीआई की बड़ी हिस्सेदारी रही है; उन्हें पोषित करने और अंततः आरबीआई से अलग करने से उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना है। राज्य स्तर पर उद्योग की दीर्घकालिक वित्तीय मध्यस्थता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य वित्त निगम (एसएफसी) की स्थापना की गई थी। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) अस्तित्व में आया, जिसे आरबीआई द्वारा प्रायोजित किया गया था ताकि पूंजी बाजार में भाग लेने के लिए खुदरा निवेशकों के लिए एक चैनल प्रदान किया जा सके। आरबीआई ने क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी स्थापना की, जो बाद में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बन गया। संस्था निर्माण की यह भूमिका वित्तीय बाजारों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्षों के विकास, वित्तीय बेंचमार्क निर्धारण, बैंक नोट मुद्रण, बैंकिंग उद्योग की आईटी और साइबर सुरक्षा लचीलापन, वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध

सेवाएं, फिनटेक क्षेत्र⁵ के लिए कई संस्थानों और हाल ही में एक नवाचार केंद्र के रूप में जारी है।

एक अन्य क्षेत्र जो आरबीआई के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है, वह है वित्तीय बाजारों के स्पेक्ट्रम का विकास और विनियमन। आरंभिक सक्षम स्थितियां अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दरों के विनियमन, राजकोषीय घाटे के स्वतः मुद्रीकरण के साधन के रूप में तदर्थ राजकोषीय बिलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, आरक्षित आवश्यकताओं के माध्यम से वैधानिक पूर्व-अधिकारों में भारी कमी, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण के लिए नीलामी की शुरुआत, नए बाजार साधनों की शुरुआत और एक आधुनिक तरलता प्रबंधन ढांचे और टूलकिट की स्थापना के माध्यम से स्थापित की गईं। विदेशी मुद्रा बाजार में, विनिमय दर व्यवस्था एकल मुद्रा निश्चित-विनिमय दर प्रणाली से मुद्राओं की बास्केट व्यवस्था और अंततः बाजार-निर्धारित अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में विकसित हुई। रुपये को चालू खाता लेनदेन के लिए पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया है और रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूंजी खाते का पर्याप्त उदारीकरण एक सतत प्रक्रिया के रूप में किया गया है। गवर्नर, श्री शक्तिकान्त दास ने भविष्यवाणी की कि "जैसे-जैसे हम आरबीआई@100 की ओर बढ़ रहे हैं, आने वाला दशक परिवर्तनकारी होने जा रहा है"।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

⁵ इन संस्थानों में शामिल हैं: (i) 1996 में बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) की स्थापना, जो भारतीय बैंकिंग उद्योग के डिजिटल परिवर्तन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है; (ii) 2008 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (एनपीसीआई) का निर्माण, जो भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरा है; (iii) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा (आईएफटीएस) की स्थापना, जो आवश्यक आईटी से संबंधित सेवाओं के लिए डिजाइन तैयार करने, उसे लागू करने और सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक संस्थान है; (iv) रिजर्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के साइबर सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए 2016 में रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरबीआईटी) की स्थापना; (v) वित्तीय सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक नवोन्मेष हब (आरबीआईएच) की स्थापना।

II. वैश्विक पृष्ठभूमि

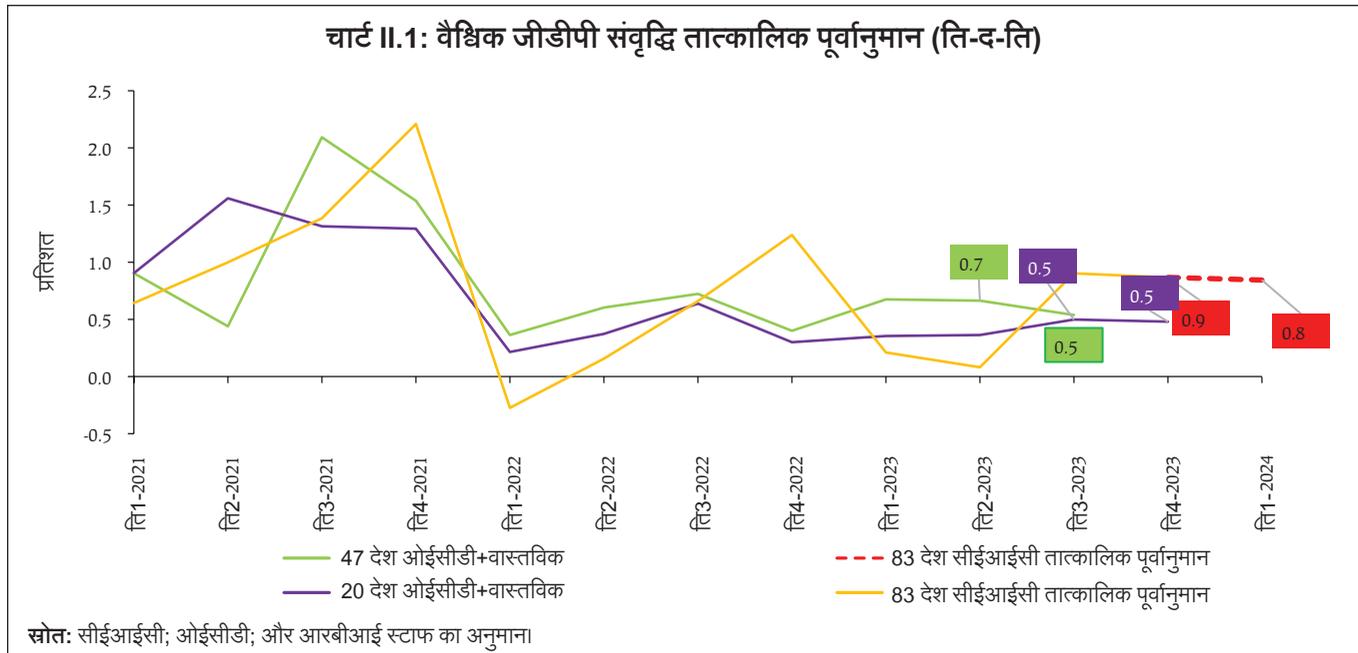
के बावजूद मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और रोजगार की कड़ी परिस्थितियों के साथ वैश्विक विकास लचीला बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ अप्रैल 2024) में 2024 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया है, जो जनवरी 2024 के अपडेट से 10 बीपीएस अधिक है और उम्मीद है कि 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था इसी गति से बढ़ेगी (सारणी II.1)।⁶ आई के लिए, यूएस संवृद्धि पूर्वानुमान में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण 2024 के लिए संवृद्धि पूर्वानुमान को 20 बीपीएस से बढ़ाकर 1.7 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए, पूर्वानुमान को 10 बीपीएस से बढ़ाकर 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में 6.8 प्रतिशत के वार्षिक औसत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत

सारणी II.1: सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा आई और ईएमई

(प्रतिशत)

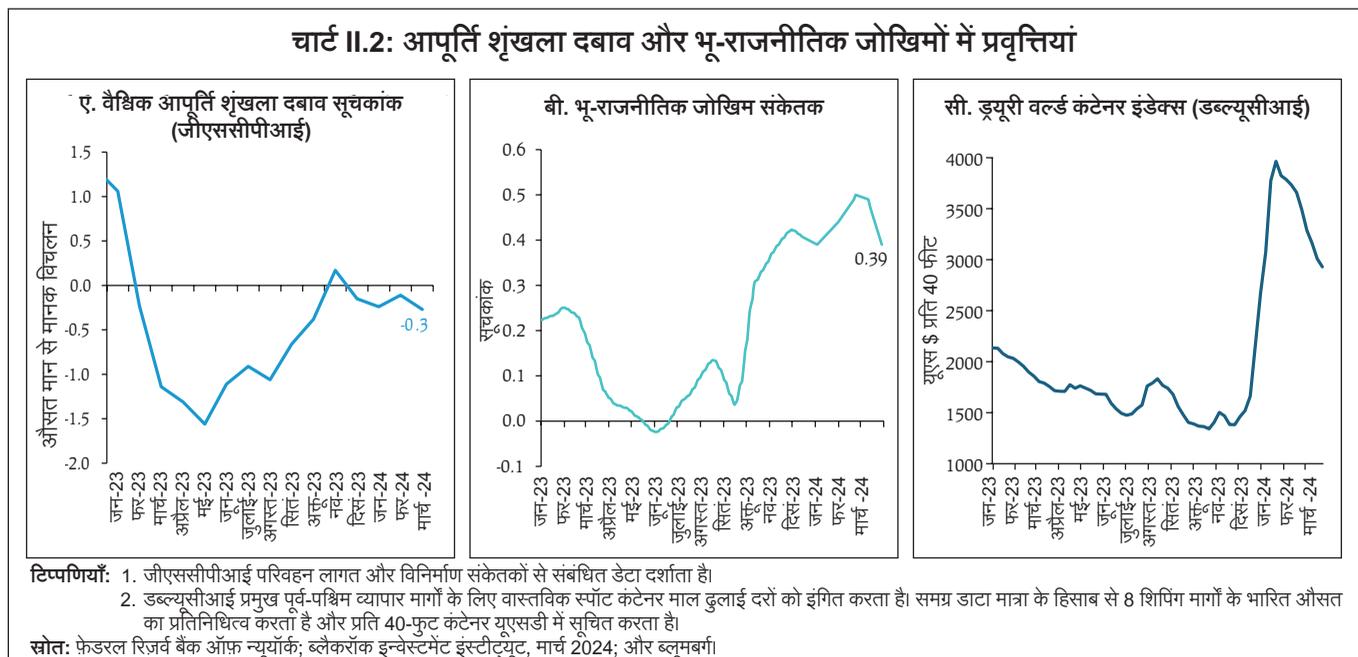
के लिए अनुमान	2024		2025	
	अप्रैल 2024	जनवरी 2024	अप्रैल 2024	जनवरी 2024
 विश्व	3.2	3.1	3.2	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (आई)				
 यूएस	2.7	2.1	1.9	1.7
 यूके	0.5	0.6	1.5	1.6
 यूरो क्षेत्र	0.8	0.9	1.5	1.7
 जापान	0.9	0.9	1.0	0.8
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)				
 ब्राजील	2.2	1.7	2.1	1.9
 रूस	3.2	2.6	1.8	1.1
 भारत [#]	6.8	6.5	6.5	6.5
 चीन	4.6	4.6	4.1	4.1
 दक्षिण अफ्रीका	0.9	1.0	1.2	1.3

[#] ऑकड़े राजकोषीय वर्षों पर आधारित हैं।
स्रोत: आईएमएफ।



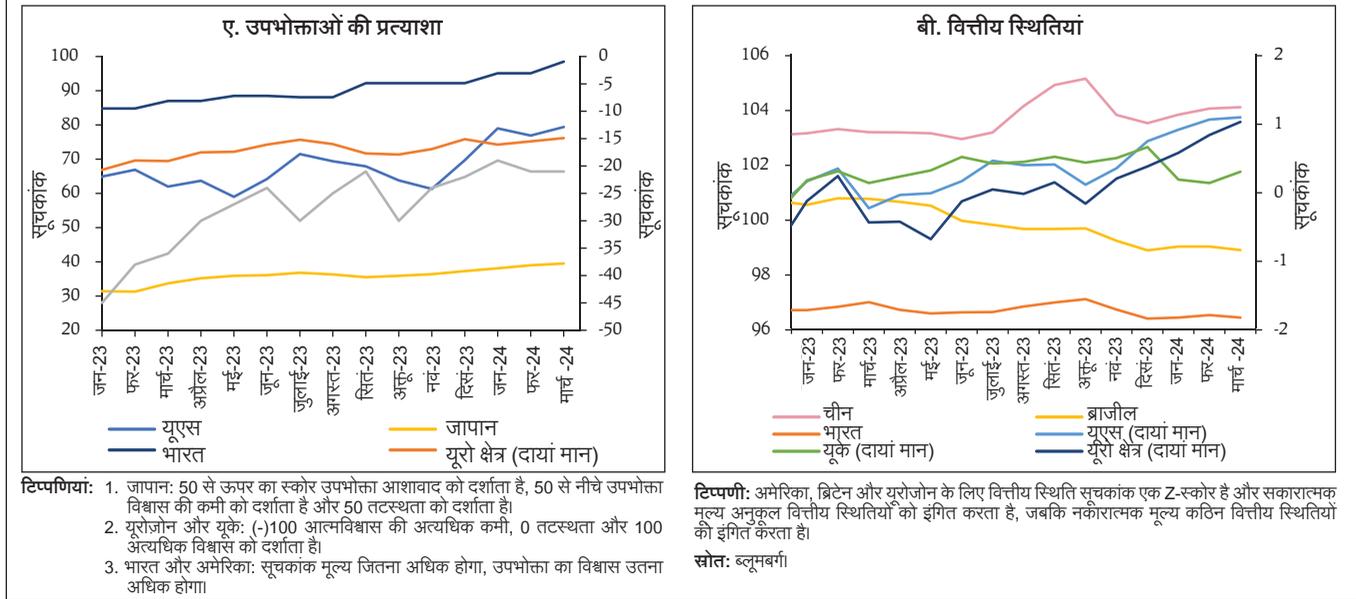
और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है (दोनों को पिछले अनुमानों से 0.1 प्रतिशत अंक तक संशोधित किया गया है), एई ईएमडीई की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी लौट आएं। हमारा मॉडल-आधारित नाउकास्ट ति1:2024 के दौरान वैश्विक संवृद्धि की निरंतर गति की ओर इशारा करता है, हालांकि क्रमिक रूप से मामूली गिरावट हुई है (चार्ट II.1)।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे आ गया और भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक मार्च 2024 में गिर गया (चार्ट II.2 ए और बी)⁶। लाल सागर में चल रही शत्रुता के कारण कंटेनर शिपिंग की लागत बढ़ गई है और फरवरी से देखे गए सुधार के बावजूद मार्च में ऊंची बनी रही (चार्ट II.2 सी)।



⁶ ब्लैकरॉक जियोपॉलिटिकल रिस्क डैशबोर्ड, 29 मार्च, 2024।

चार्ट II.3: उपभोक्ता प्रत्याशा और वित्तीय स्थितियां



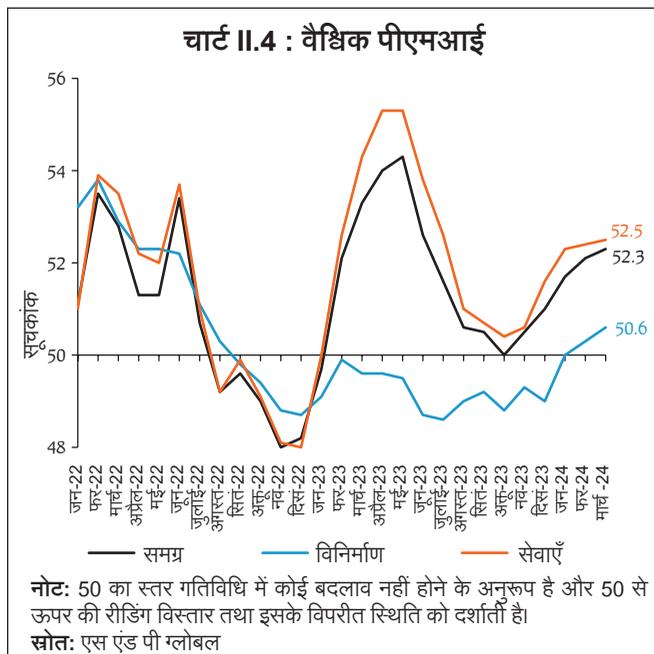
उपभोक्ता भावनाएँ भौगोलिक क्षेत्रों में बेहतर होती रहीं क्योंकि मुद्रास्फीति दबाव पिछले वर्ष के उच्चतम स्तर से कम हो गया, जिसे मोटे तौर पर स्थिर रोजगार संभावनाओं से समर्थन मिला (चार्ट II.3ए)। मजबूत इक्विटी बाजार प्रदर्शन के कारण वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल बनी रहीं (चार्ट II.3बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने मार्च 2024 में क्रमिक वृद्धि दर्ज की, जिसे सेवाओं और विनिर्माण

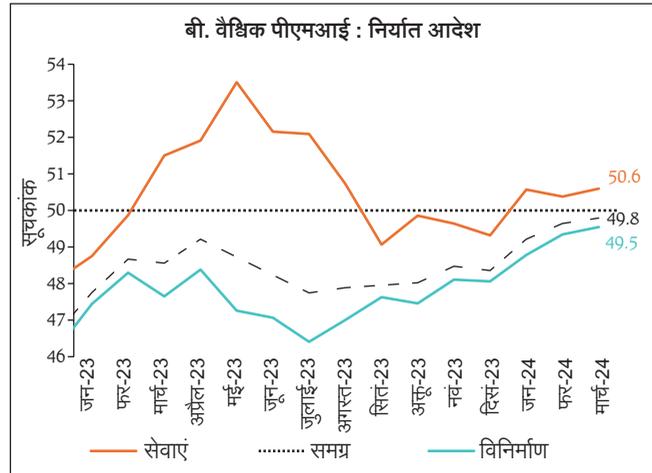
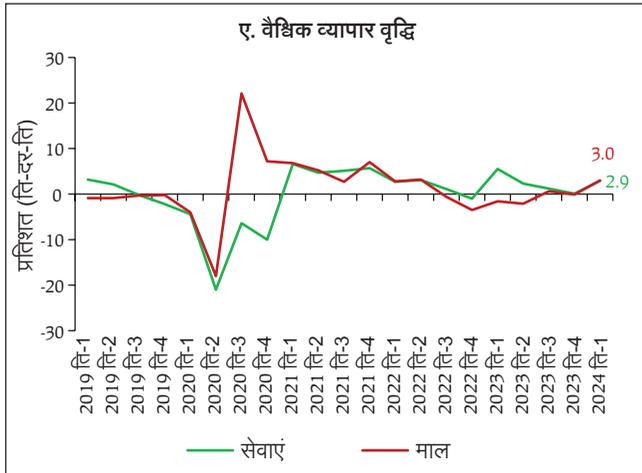
गतिविधि (चार्ट II.4) दोनों में निरंतर विस्तार द्वारा समर्थित किया गया। नए व्यवसायों और निर्यात में वृद्धि के कारण मार्च में सेवा पीएमआई आठ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नए ऑर्डर, आउटपुट और रोजगार के विस्तार के कारण वैश्विक विनिर्माण पीएमआई जुलाई 2022 के बाद से अपने उच्चतम रीडिंग पर पहुंच गया।

मार्च 2024 के अंकटाड ग्लोबल ट्रेड अपडेट के अनुसार, 2023 में 3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2024 में वैश्विक व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है (चार्ट II.5ए)। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा निरंतर वैश्विक संवृद्धि और पर्यावरणीय वस्तुओं की बढ़ती मांग से मिलने की उम्मीद है, हालांकि भू-राजनीतिक तनाव और शिपिंग व्यवधान प्रमुख जोखिम बने हुए हैं। डब्ल्यूटीओ ने अपने वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी - अप्रैल 2024 में अनुमान लगाया है कि 2023 में -1.2 की अपेक्षा से अधिक गिरावट के बाद, 2024 में विश्व माल व्यापार की मात्रा 2.6 प्रतिशत और 2025 में 3.3 प्रतिशत बढ़ेगी। इस दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, निर्यात आदेशों के लिए समग्र पीएमआई ने मार्च में अपनी तेजी को बनाए रखा (चार्ट II.5बी)। विनिर्माण घटक 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया; जनवरी 2024 से सेवा निर्यात आदेश सूचकांक विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है।

चार्ट II.4 : वैश्विक पीएमआई



चार्ट II.5 : वैश्विक व्यापार वृद्धि और पीएमआई निर्यात आदेश



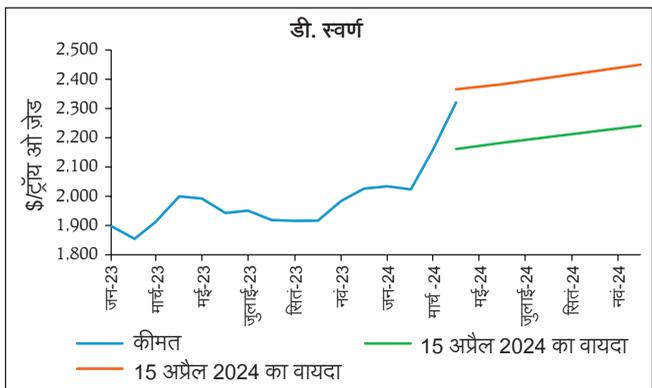
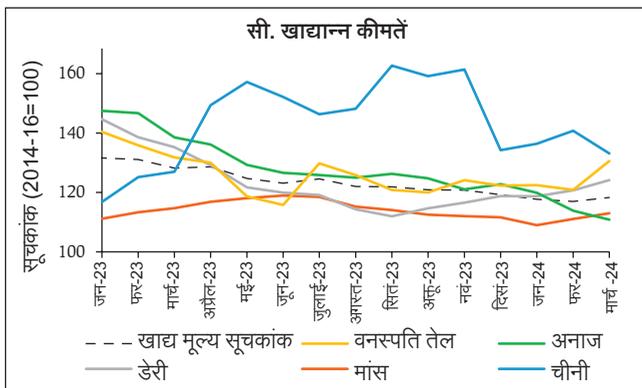
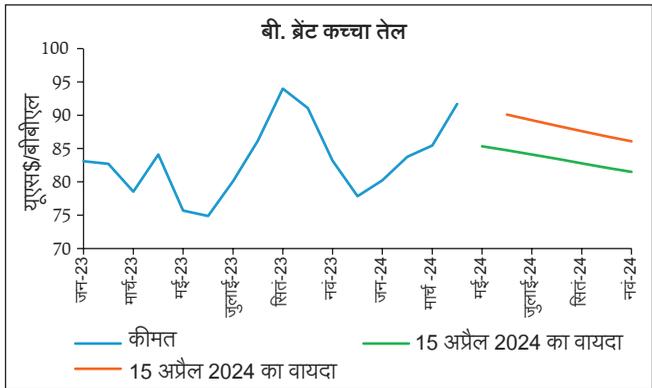
नोट: 1. तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि मौसमी रूप से समायोजित मूल्यों पर आधारित है। ति4:2023 के लिए मूल्य अनुमान हैं और ति1:2024 एक तात्कालिक अनुमान है।
2. 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार तथा इसके विपरीत स्थिति को दर्शाती है।

स्रोत: अंकटाड और एस एंड पी ग्लोबला

मार्च में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया, जिसकी वजह कच्चे तेल और धातुएँ थीं। नतीजतन, ब्लूमबर्ग

कमोडिटी मूल्य सूचकांक में 2.9 प्रतिशत (माह दर माह) की वृद्धि हुई [चार्ट II.6ए]। कच्चे तेल और सोने की कीमतों में और

चार्ट II.6: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें



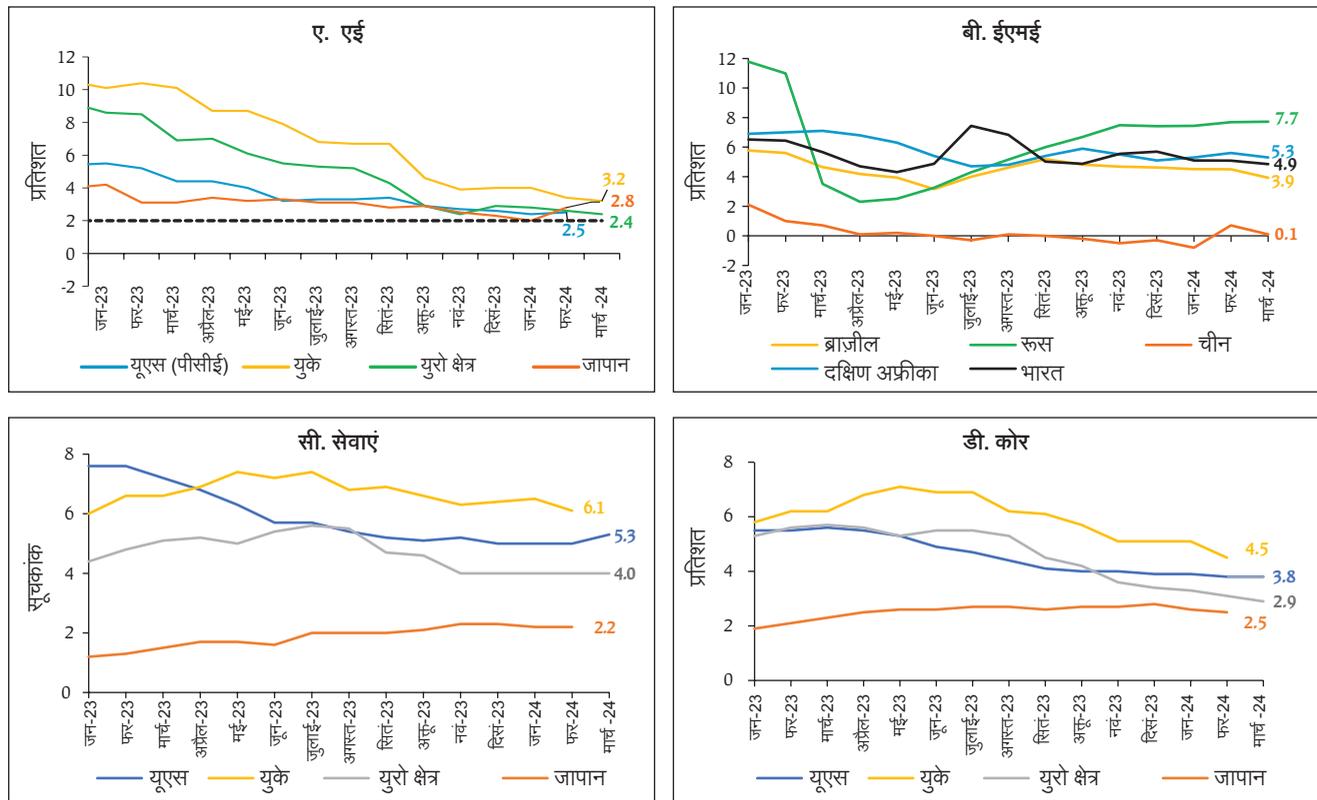
स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; और एफएओ

उछाल आने के कारण अप्रैल में कमोडिटी की कीमतों में उछाल जारी रहा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और 2024 में ओपेक+ सदस्यों द्वारा अपेक्षित स्वैच्छिक कटौती के कारण तेल बाजार घाटे की भविष्यवाणियों के बीच मार्च में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 11.6बी)। सीरिया और इजराइल में नए भू-राजनीतिक संघर्षों में बाजार की कीमतों के कारण अप्रैल में कीमतें और बढ़ गईं। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च 2024 में 1.1 प्रतिशत (माह दर माह) बढ़ा, जो जुलाई 2023 के बाद पहली वृद्धि थी। यह मुख्य रूप से वनस्पति तेलों की कीमतों में वृद्धि (8.0 प्रतिशत) के कारण हुआ, जो आंशिक रूप से चीनी की कीमतों में गिरावट (-5.4 प्रतिशत) [चार्ट 11.6सी] द्वारा ऑफसेट किया गया। मार्च में सोने की कीमतें बढ़ गईं, जो फरवरी की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक रहीं और अप्रैल में सुरक्षित आश्रय मांग के कारण इनमें वृद्धि जारी रही (चार्ट 11.6डी)।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति एक साल पहले दर्ज किए गए स्तरों से काफी कम हो गई, हालांकि यह लक्ष्यों से ऊपर रही। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 3.5 प्रतिशत हो गई, जबकि हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति फरवरी में 2.6 प्रतिशत से मार्च में 2.4 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट 11.7ए)। यूके में, सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च में नरम होकर 3.2 प्रतिशत हो गई। जापान की मुद्रास्फीति (ताजे खाद्य को छोड़कर सीपीआई) फरवरी में 2.8 प्रतिशत से मार्च में 2.6 प्रतिशत पर आ गई।

ईएमई में, मार्च में ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति कम हुई (चार्ट 11.7बी)। रूस में मुद्रास्फीति मार्च में लगातार दूसरे महीने स्थिर रही। प्रमुख आई में कोर और सेवा

चार्ट 11.7: मुद्रास्फीति - आई और ईएमई



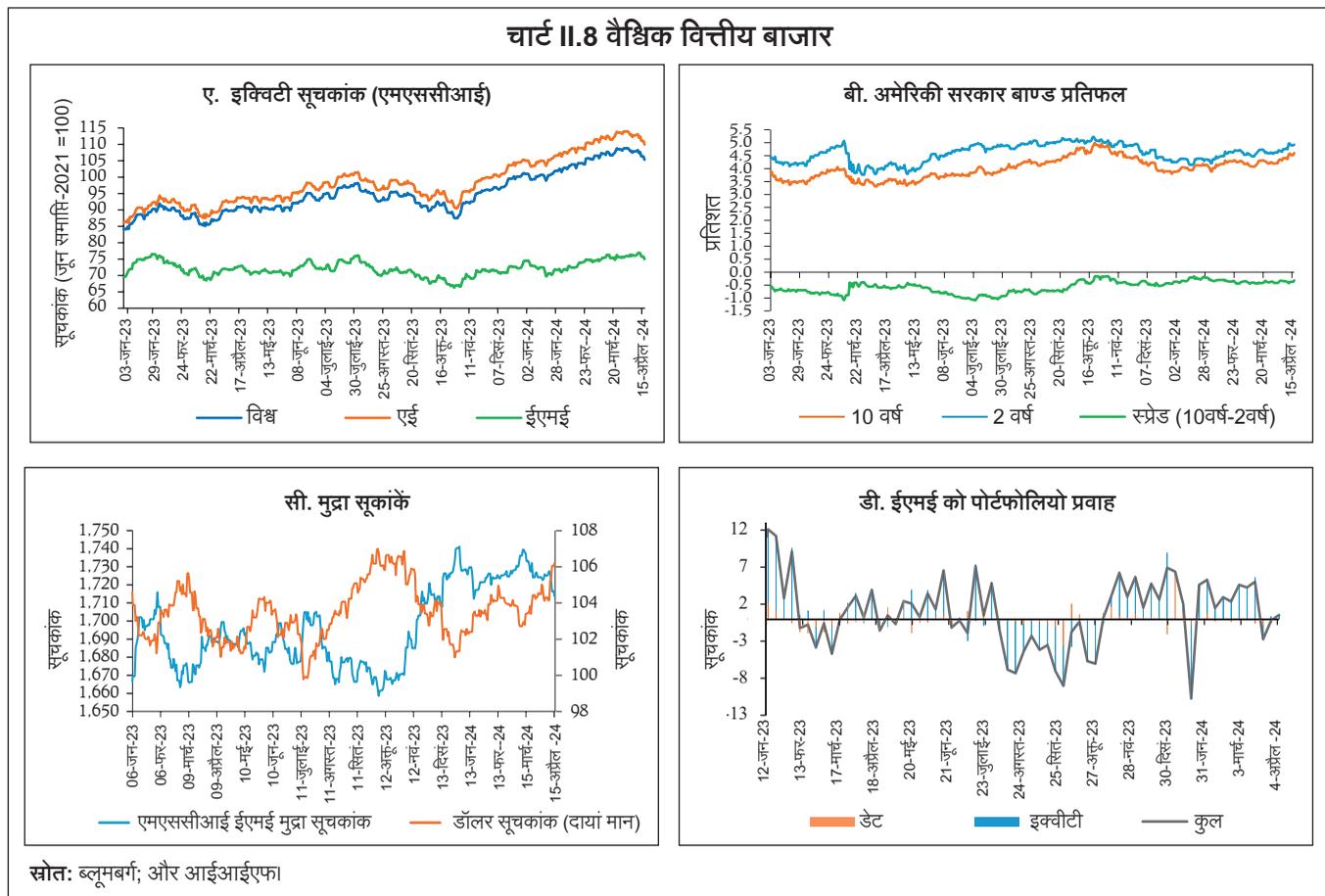
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

मुद्रास्फीति भी कम हुई, लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति से अधिक रही (चार्ट 11.7सी और 11.7डी)।

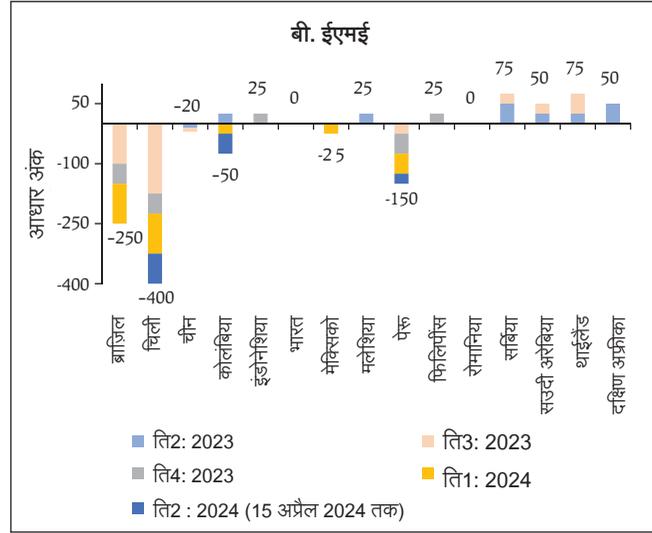
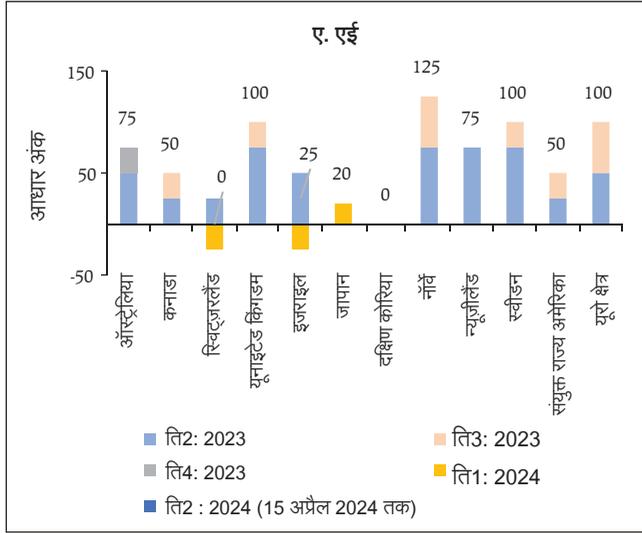
संभावनाओं पर आशावाद, यूरो क्षेत्र में उज्ज्वल संवृद्धि की संभावनाएं और चीन में विदेशी प्रवाह की वापसी के कारण उछाल आया। मार्च में एमएससीआई विश्व इक्विटी सूचकांक में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आई और ईएमई में क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट 11.8ए)। हालांकि, अप्रैल में गैर-कृषि पेट्रोल डेटा की अपेक्षा से अधिक रिलीज, यूएस सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि और भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने के बाद इक्विटी बाजारों ने ये लाभ खो दिया।

अमेरिकी सरकार की प्रतिभूति (जी-सेक) का प्रतिफल - 10 साल और 2 साल दोनों मार्च में सीमित दायरे में रहीं, लेकिन अप्रैल में बढ़ती मुद्रास्फीति और इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाय मैनेजमेंट (आईएसएम) के पीएमआई विनिर्माण सूचकांक के विस्तार क्षेत्र में जाने के बीच मजबूत हुई (चार्ट 11.8बी)। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर सूचकांक मार्च के मध्य से मजबूत हुआ, क्योंकि सीपीआई डेटा उम्मीद से अधिक उच्च था, जिससे फेड द्वारा दरों में कटौती की संभावना कम हो गई और अप्रैल में भी इसकी कीमत बढ़ती रही। ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक ने ग्रीनबैक की चाल को प्रतिबिंबित किया। ईएमई ने मार्च की शुरुआत में पूंजी प्रवाह देखा, लेकिन मार्च के अंत और अप्रैल में डॉलर के मजबूत होने के कारण रुझान उलट गया (चार्ट 11.8सी और 11.8डी)।

चार्ट 11.8 वैश्विक वित्तीय बाजार



चार्ट II.9: नीति दरों में परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

प्रमुख केंद्रीय बैंक, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, सतर्क बने रहे, बहुत जल्द कटौती के जोखिम को बहुत लंबे समय तक प्रतिबंधात्मक रुख बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के साथ आर्थिक गतिविधि को नुकसान पहुंचाने के बीच संतुलन बनाते रहे। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरें स्थिर रखीं (चार्ट II.9ए)। चेक गणराज्य और स्विटजरलैंड ने अपनी नीतिगत दरों में क्रमशः 50 बीपीएस और 25 बीपीएस की कमी की। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चिली और हंगरी ने अप्रैल और मार्च की बैठकों में अपनी बेंचमार्क दरों में 75 बीपीएस की कटौती की; ब्राजील और कोलंबिया ने मार्च में 50 बीपीएस की दर कटौती के साथ ढील जारी रखी; और मैक्सिको ने मार्च में 50 बीपीएस की दर कटौती के साथ अपना ढील चक्र शुरू किया (चार्ट II.9बी)।

III. घरेलू घटनाक्रम

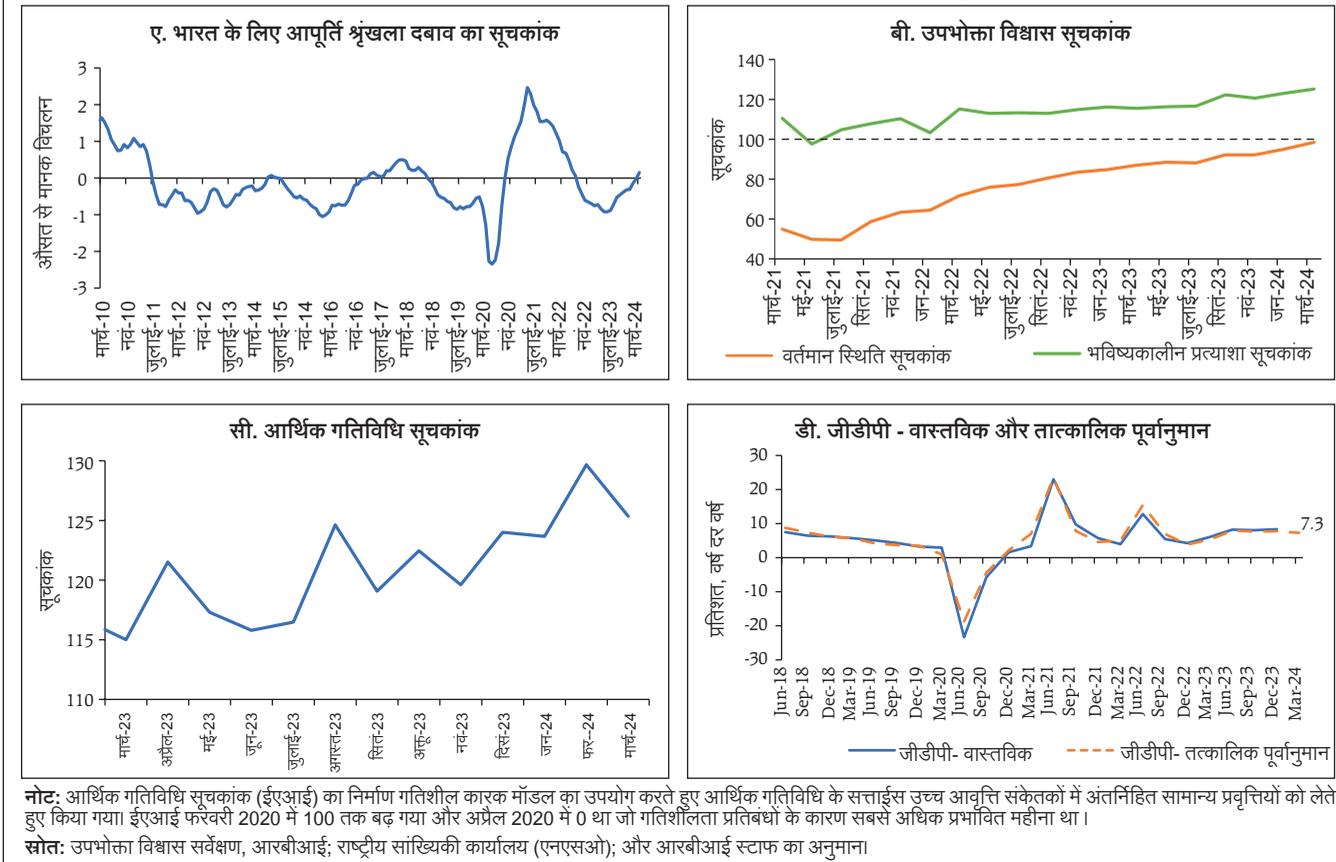
भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी लचीलापन दिखाना जारी रखा, जिसके कारण आपूर्ति शृंखला पर दबाव बढ़ा (चार्ट III.1ए)। आरबीआई के नवीनतम घरेलू सर्वेक्षण (चार्ट III.1बी) में निर्धारित मापदंडों

पर उपभोक्ता विश्वास मजबूत हुआ। उद्यम सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि व्यावसायिक मूल्यांकन और अपेक्षाएँ सकारात्मक बनी हुई हैं - उत्पादन, क्षमता उपयोग (सीयू), ऑर्डर बुक, रोजगार और समग्र व्यावसायिक स्थितियों पर आशावाद के साथ (अनुलग्नक 1)। आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) के अनुसार, ति4:2023-24 में आर्थिक गतिविधि लचीली बनी रही, हालाँकि उपलब्ध डेटा मौसमी रूप से समायोजित आधार पर पिछले महीने की तुलना में मार्च में कुछ नरमी दर्शाता है (चार्ट III.1सी)। ईएआई का उपयोग करते हुए, ति4:2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत अनुमानित रखी गई है (चार्ट III.1डी)।

कुल मांग

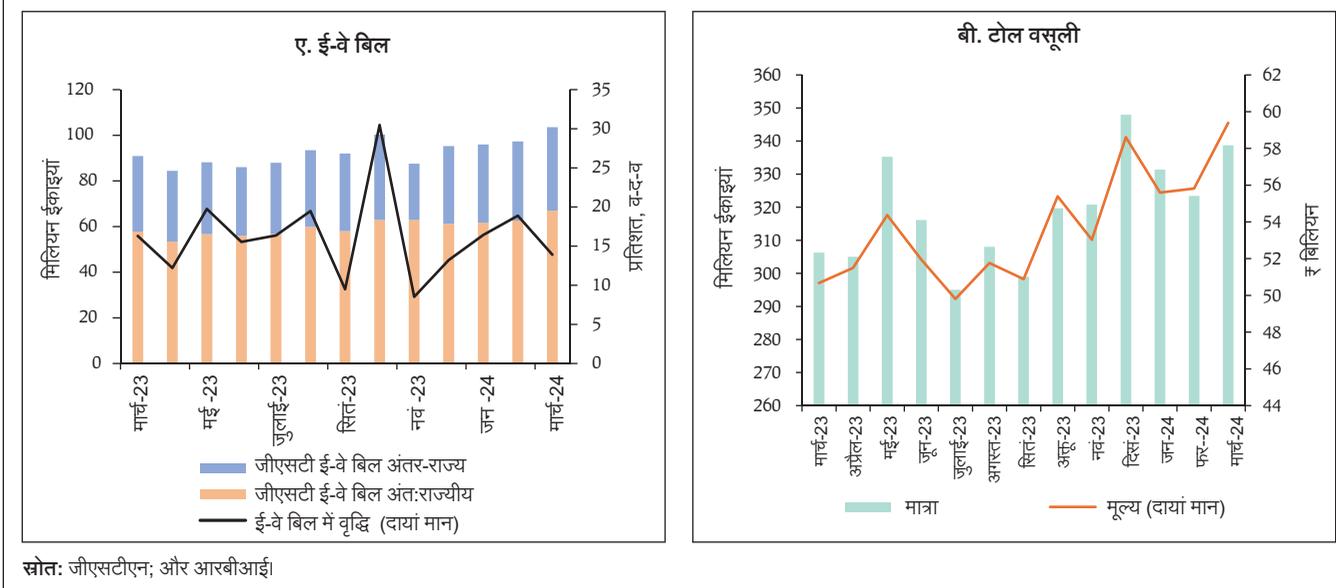
उच्च आवृत्ति संकेतक मार्च 2024 में घरेलू मांग की स्थिति में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। मार्च 2024 में ई-वे बिल 10.35 करोड़ (13.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि) के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए (चार्ट III.2ए)। मार्च 2024 में टोल संग्रह में 17.2 प्रतिशत (वार्षिक) की वृद्धि हुई (चार्ट III.2बी)।

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान

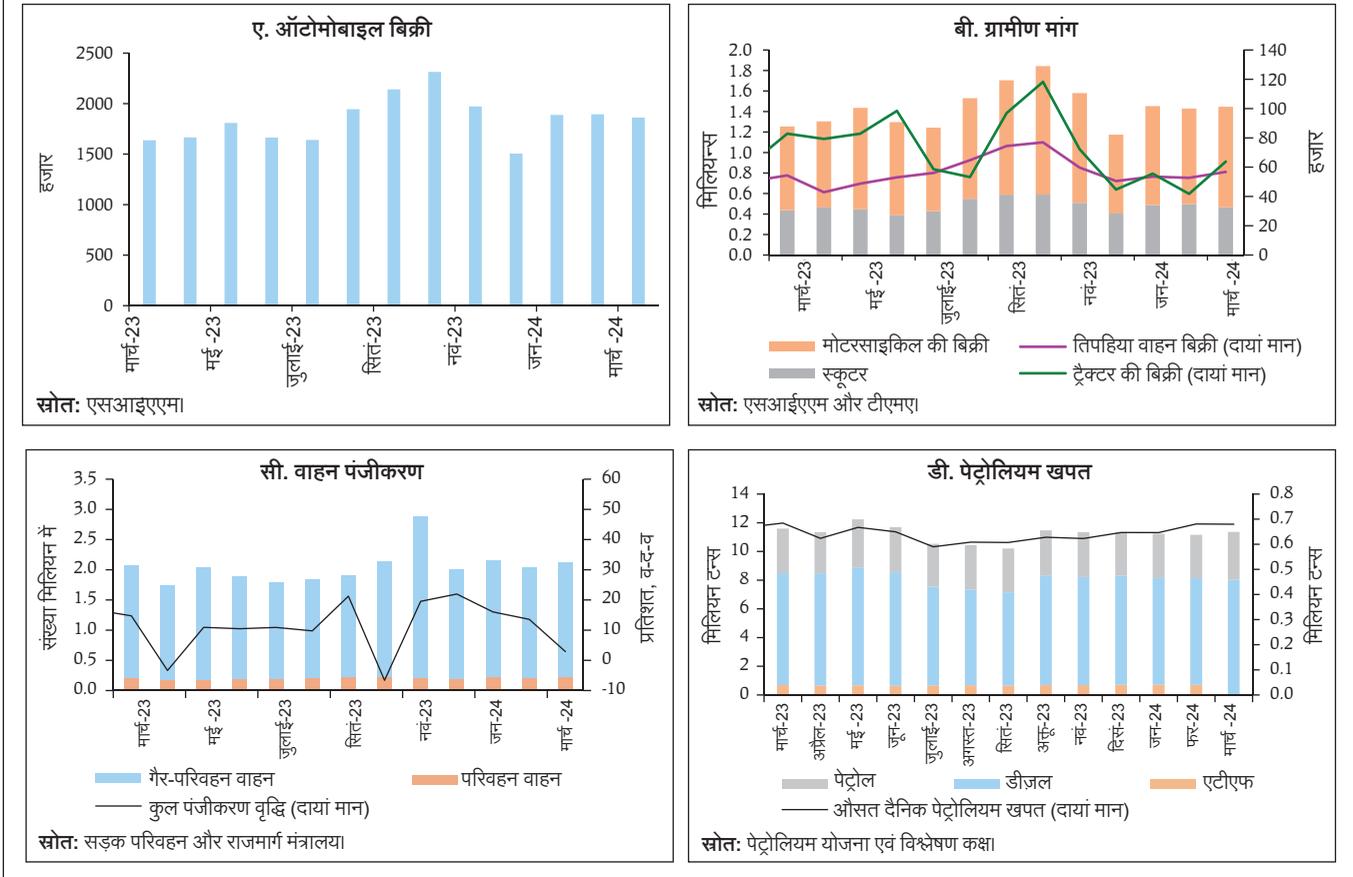


मार्च 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 13.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री ने किया। ट्रैक्टर निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि घरेलू बिक्री में

चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल वसूली



चार्ट III.3 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक



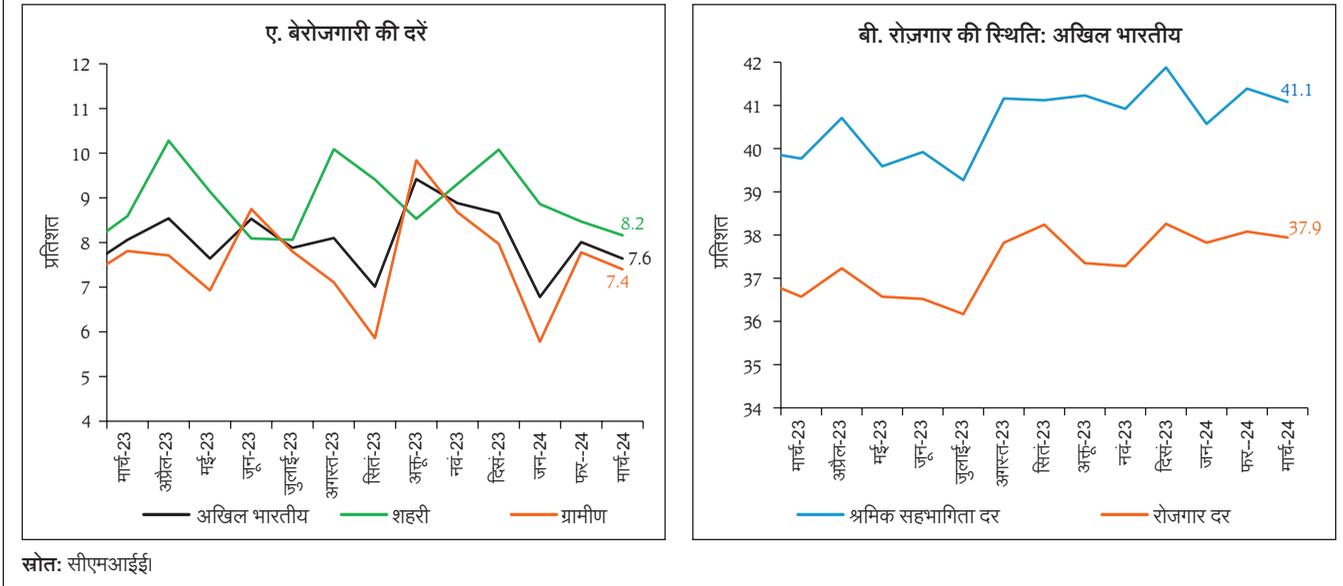
कुछ सुधार हुआ (चार्ट III.3ए और III.3बी)। मार्च 2024 में वाहन पंजीकरण में वृद्धि जारी रही, जो गैर-परिवहन वाहन खंड (चार्ट III.3सी) द्वारा संचालित थी। हालांकि, मार्च में औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में 0.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट III.3डी)।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (यूआर) मार्च में गिरकर 7.6 प्रतिशत हो गई, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घटी (चार्ट III.4ए)। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और रोजगार दर (ईआर) में पिछले महीने की तुलना में मामूली गिरावट आई (चार्ट III.4बी)।

विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित क्षेत्र में रोजगार के दृष्टिकोण में मार्च 2024 में सुधार हुआ है। जबकि विनिर्माण रोजगार में दो महीने के संकुचन के बाद विस्तार दर्ज किया गया, सेवा रोजगार सृजन सात महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.5)।

रबी की कटाई शुरू होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग क्रमिक आधार पर कम हो गई, जो ग्रामीण कृषि बाजार में रोजगार के अवसरों में विस्तार का संकेत है (चार्ट III.6ए)।

चार्ट III.4 : श्रम बाजार स्थितियां



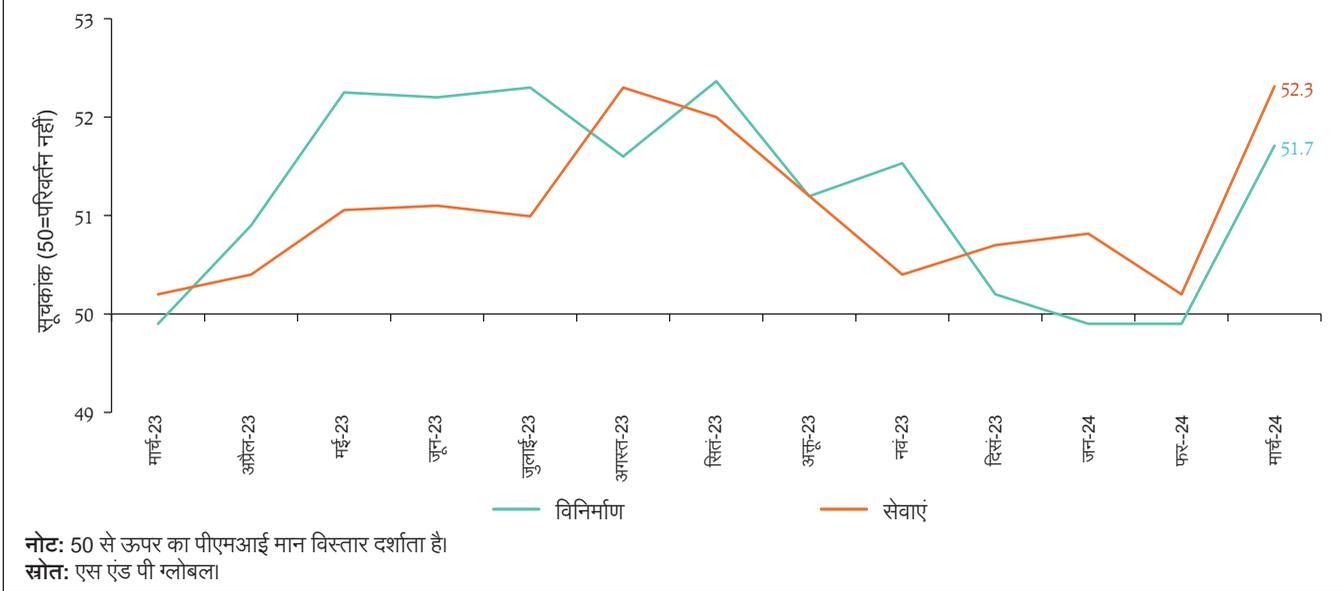
01 अप्रैल, 2024 से एमजीएनआरईजीएस के तहत दैनिक मजदूरी राज्यों में 3 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत (₹7 - ₹34/दिन) के बीच बढ़ा दी गई है (चार्ट III.6बी)।

मार्च 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 41.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023-24 में किसी भी महीने में सबसे अधिक था। लगभग 1.0 प्रतिशत की सकारात्मक गति के

बावजूद, प्रतिकूल आधार प्रभाव (चार्ट III.7) के कारण निर्यात में सालाना आधार पर 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई। क्रमिक रूप से, जबकि पेट्रोलियम निर्यात में एक तिहाई से अधिक की कमी आई, गैर-पीओएल निर्यात में वृद्धि हुई।

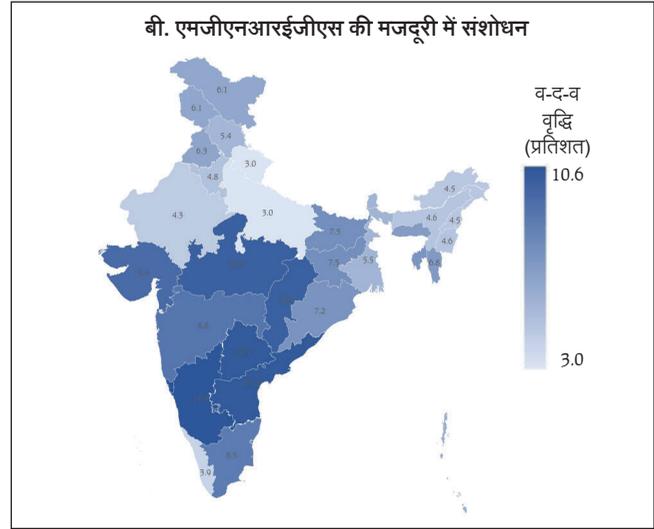
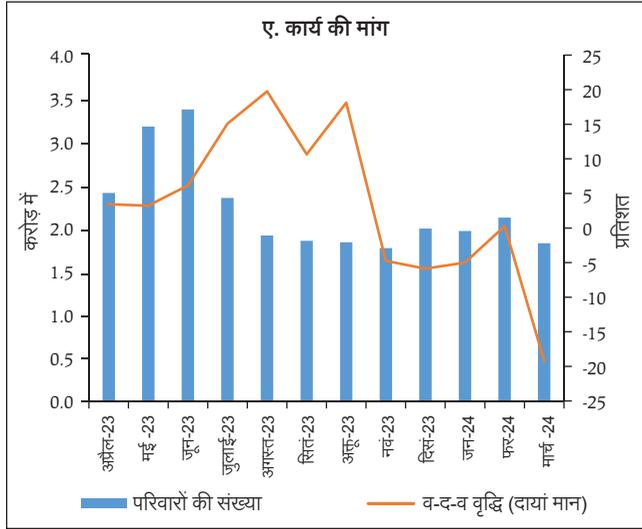
वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 30 प्रमुख निर्यात वस्तुओं में से, निर्यात बास्केट⁷ में 35.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली

चार्ट III.5 : पी एम आई रोजगार सूचकांक



⁷ 2023-24 में हिस्सेदारी।

चार्ट III.6 : एमजीएनआरईजीएस के तहत कार्य की मांग और वेतन संशोधन



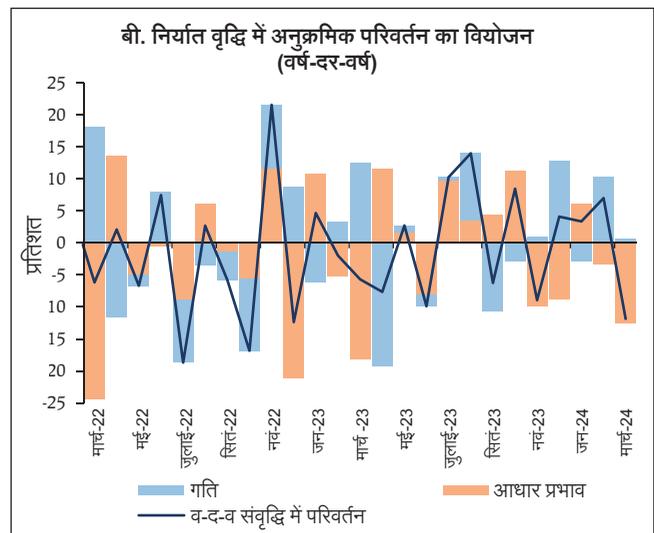
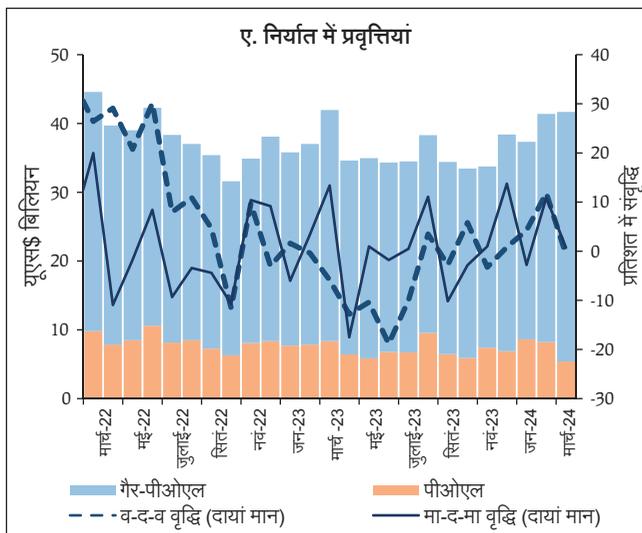
स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

13 वस्तुओं में मार्च में संकुचन दर्ज किया गया। पेट्रोलियम उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, तेल के भोजन और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे खींच लिया, जबकि इंजीनियरिंग सामान, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स और मसालों ने निर्यात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट III.8)।

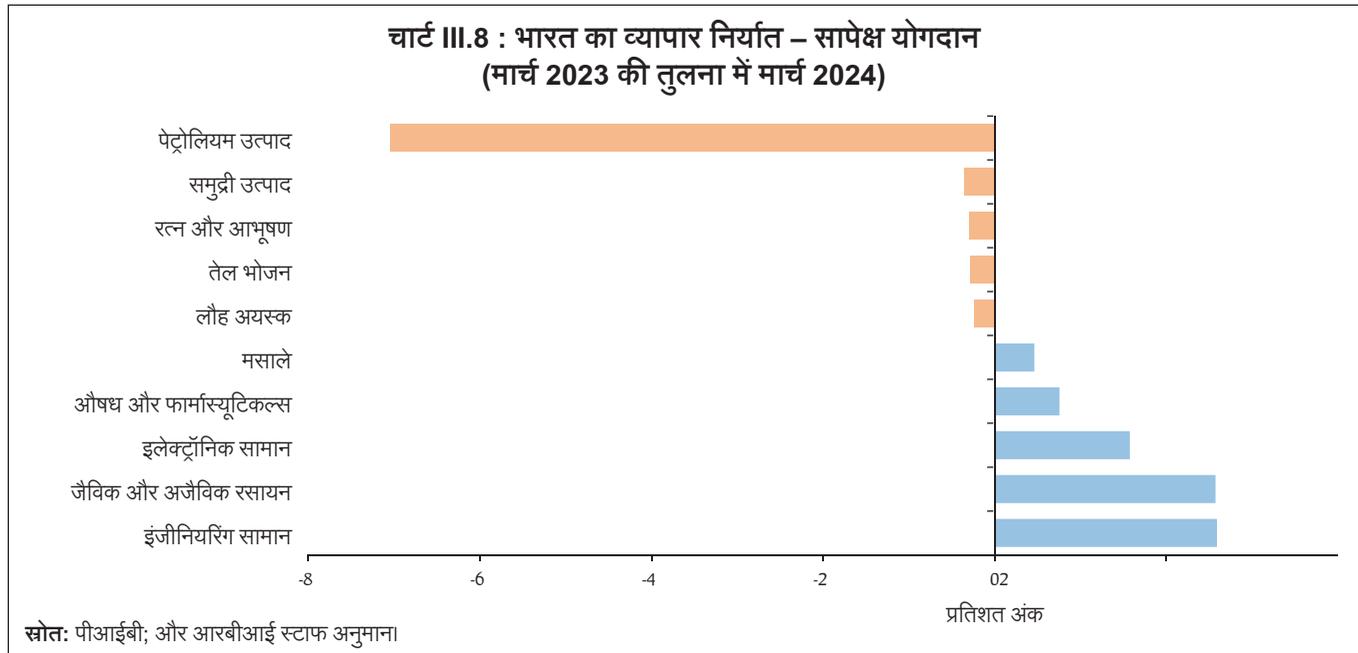
मार्च 2024 में नकारात्मक गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव दोनों के कारण व्यापारिक आयात 6.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) घटकर 57.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया (चार्ट III.9)।

30 प्रमुख आयात वस्तुओं में से, आयात बास्केट में 67 प्रतिशत हिस्सा रखने वाली 18 वस्तुओं में मार्च में साल दर

चार्ट III.7 : भारत का व्यापार निर्यात



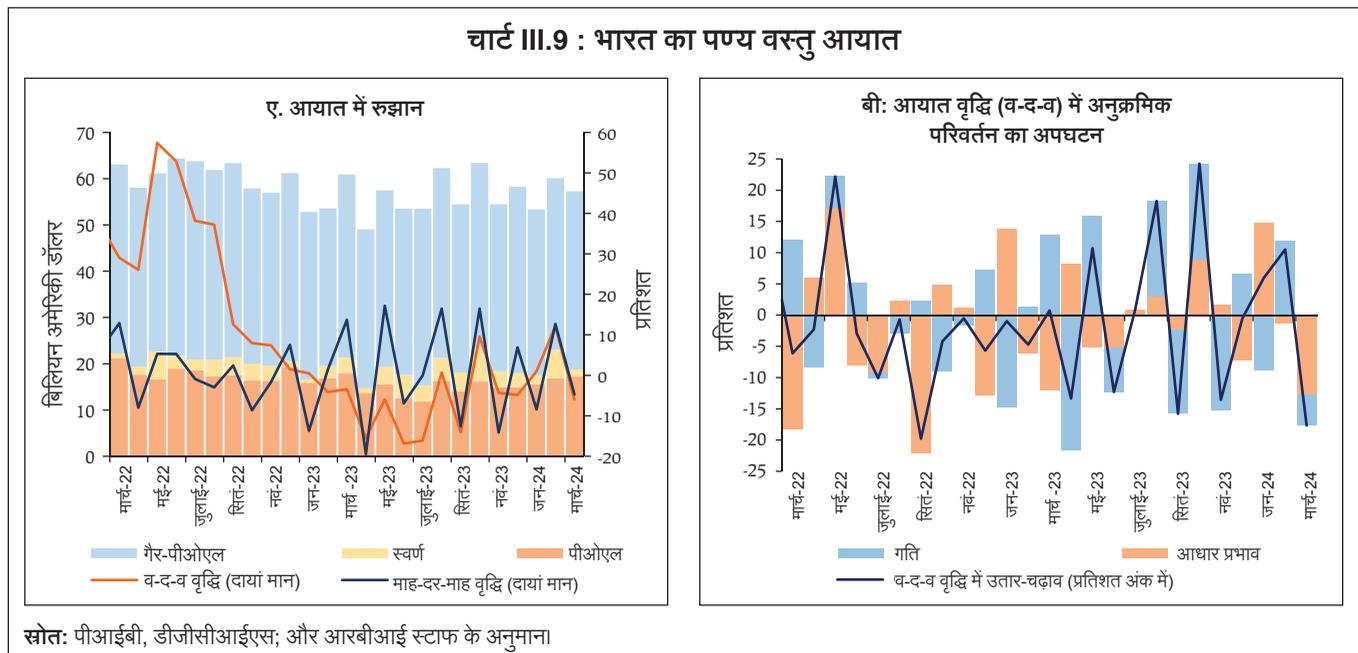
टिप्पणी: पीओएल, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
 स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

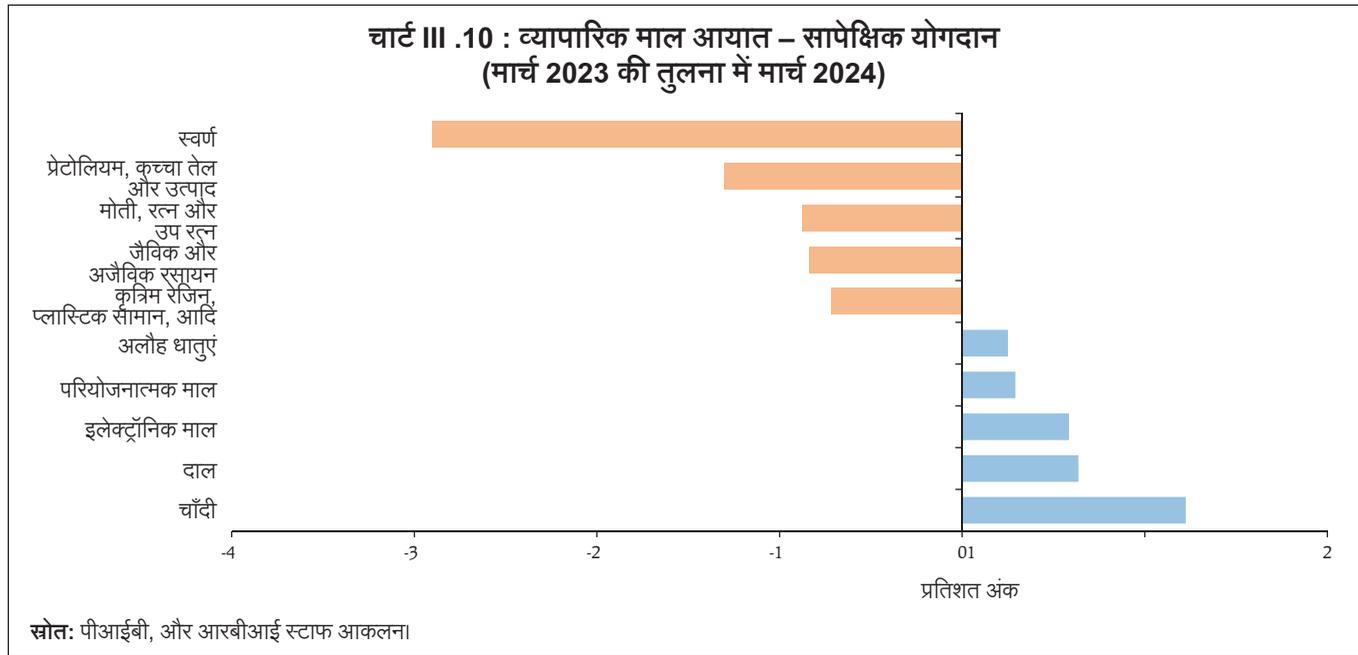


साल आधार पर संकुचन दर्ज किया गया। सोना, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, तथा कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों ने आयात को कम किया, जबकि चांदी, दालें और इलेक्ट्रॉनिक सामान ने वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट III.10)।

आयात में तीव्र कमी के कारण, मार्च 2024 में व्यापारिक

व्यापार घाटा 11 महीने के निचले स्तर 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था। गैर-तेल घाटा फरवरी में 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर मार्च 2024 में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इसके विपरीत, तेल घाटा एक महीने पहले 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च में 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसके साथ ही, कुल व्यापारिक

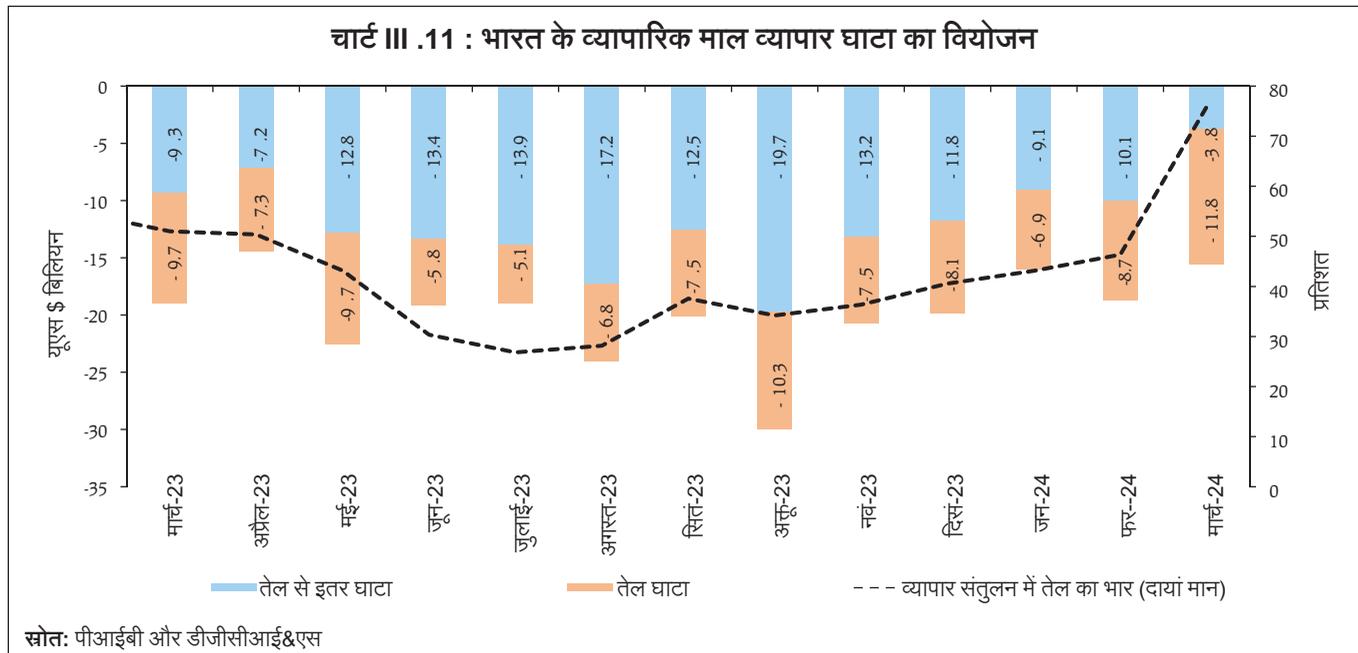


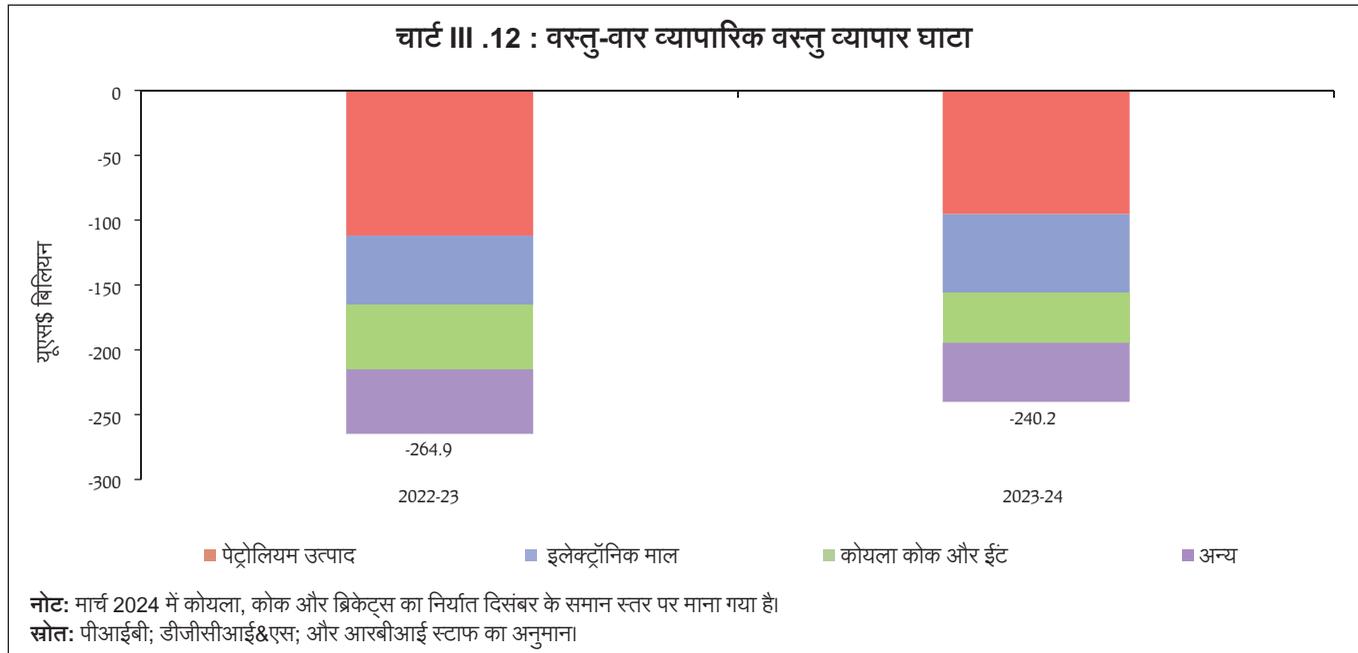


व्यापार घाटे में तेल घाटे का हिस्सा बढ़कर 75.9 प्रतिशत हो गया (चार्ट III.11)।

2023-24 के दौरान, भारत का माल निर्यात 3.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि माल आयात 5.4 प्रतिशत घटकर 677.2 बिलियन

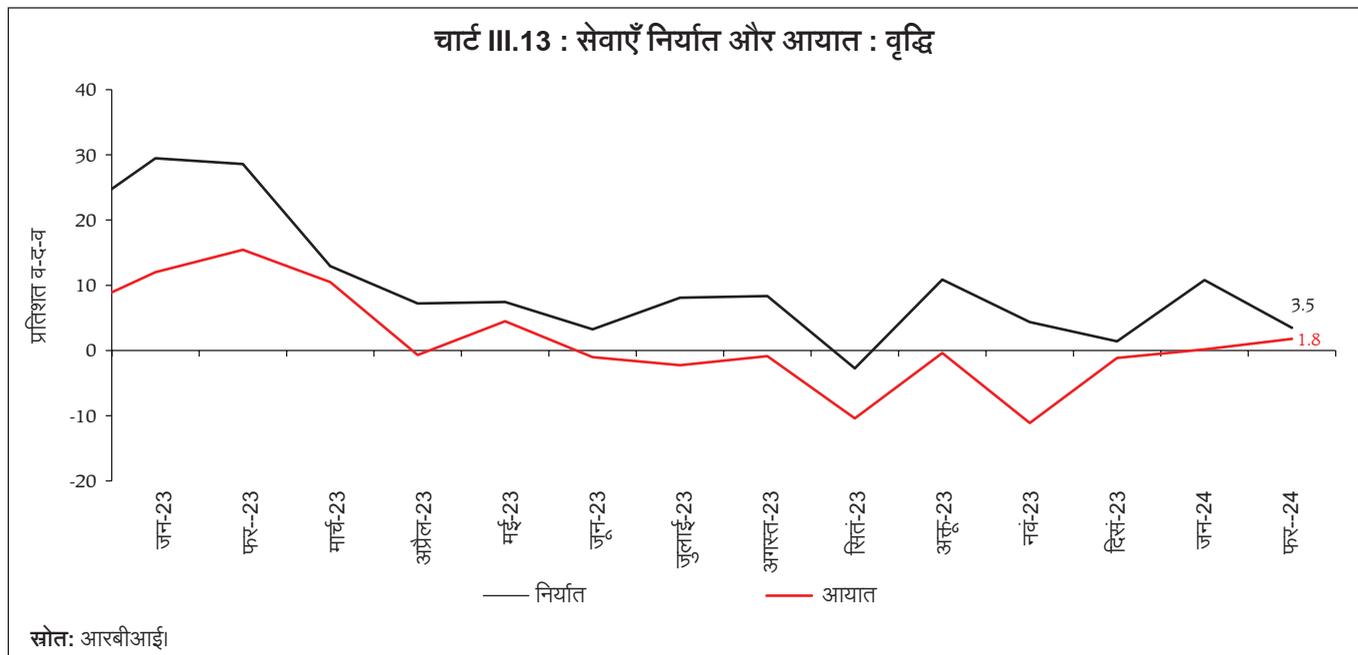
अमेरिकी डॉलर रह गया। 2023-24 में माल व्यापार घाटा घटकर 240.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले यह 264.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान (चार्ट III.12) थे।



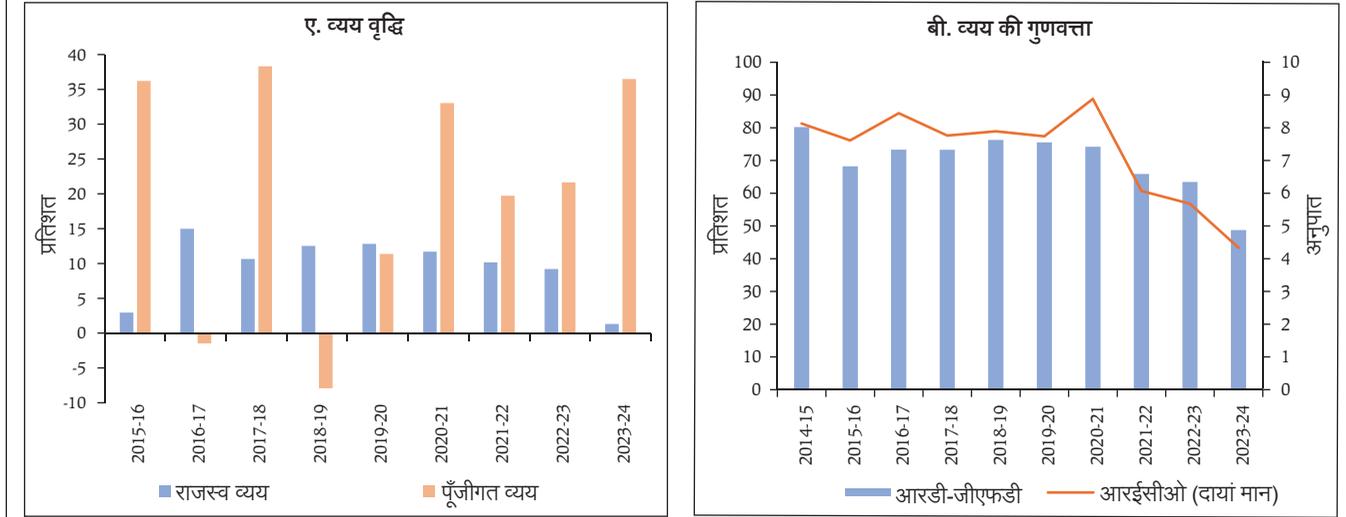


फरवरी 2024 में, सेवाओं का निर्यात 3.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 28.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक सेवाओं, यात्रा और परिवहन में वृद्धि के कारण हुआ। 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर सेवा आयात में 1.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि

दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण व्यवसाय, सॉफ्टवेयर, यात्रा और परिवहन आयात में वृद्धि थी (चार्ट III.13)। परिणामस्वरूप, फरवरी 2024 में शुद्ध सेवा निर्यात आय 5.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।



चार्ट III.14 : सरकारी व्यय (अप्रैल - फरवरी)



टिप्पणी: आरडी-जीएफडी: राजस्व घाटा से सकल राजकोषीय घाटा अनुपात; आरईसीओ: राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय अनुपात।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) संशोधित अनुमानों (आरई) का 86.5 प्रतिशत रहा। व्यय पक्ष पर, पूंजीगत व्यय में 36.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राजस्व व्यय वृद्धि 1.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर सीमित रही [चार्ट III.14ए]। पूंजीगत व्यय (अर्थात्, ऋण और अग्रिम को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ (चार्ट III.14बी)।

प्राप्तियों के मामले में, प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान 21.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा, जिसमें आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह क्रमशः 25.8 प्रतिशत और 17.3 प्रतिशत बढ़े। प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि बढ़ी हुई अनुपालन, उच्च अग्रिम कर संग्रह और कर आधार के विस्तार के कारण है^{8,9,10} अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.8

प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और सीमा शुल्क राजस्व में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, उत्पाद शुल्क में 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि ने किया (चार्ट III.15)।

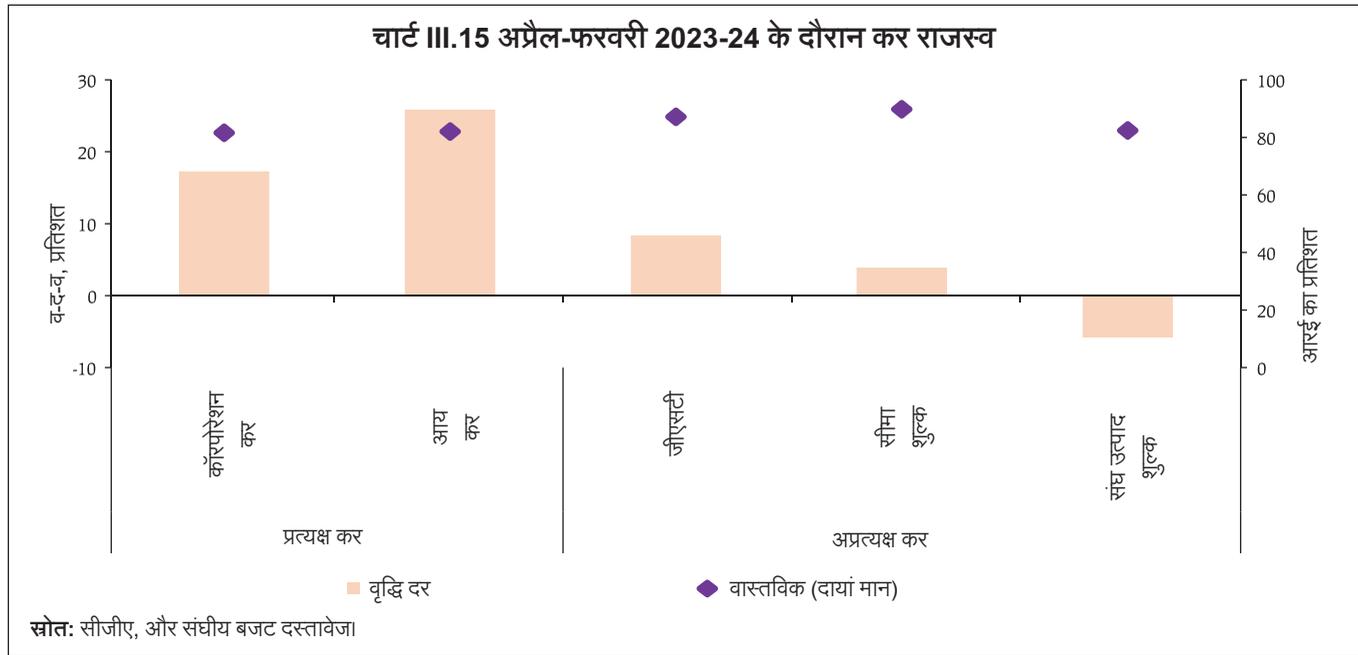
अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान गैर-कर राजस्व संग्रह में 44.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आरबीआई¹¹ से बजट से अधिक अधिशेष हस्तांतरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश (चार्ट III.16) था। दूसरी ओर, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 38.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई। केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों सहित) में 10.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

⁸ प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), वित्त मंत्रालय, 19 मार्च, 2024।

⁹ पीआईबी, वित्त मंत्रालय, 1 जनवरी, 2024।

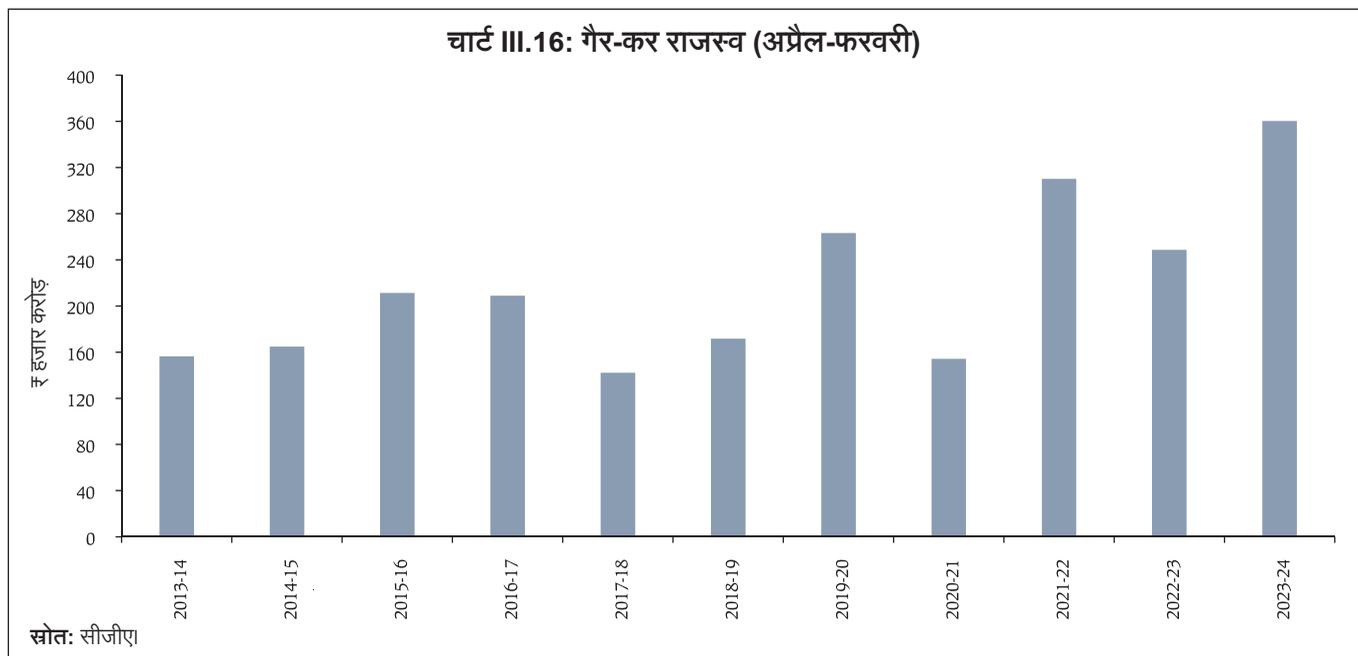
¹⁰ पीआईबी, वित्त मंत्रालय, 26 अक्टूबर, 2023।

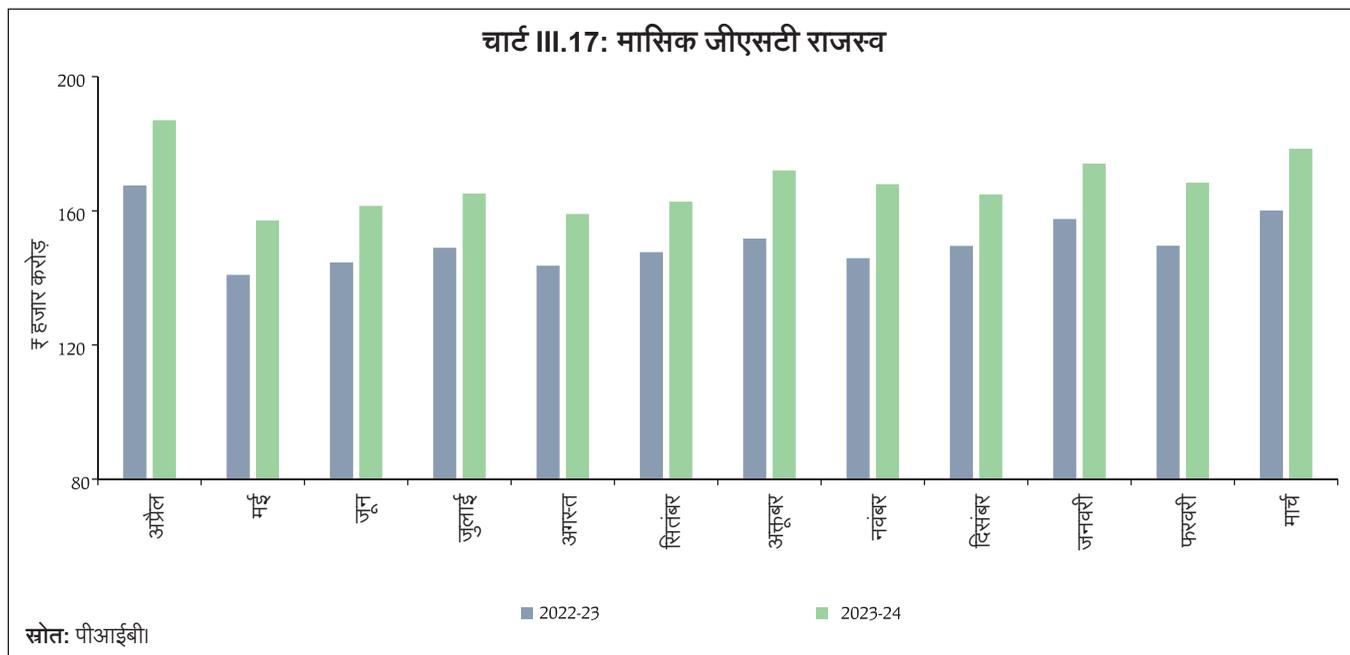
¹¹ वर्ष 2023-24 के दौरान, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को ₹87,416.22 करोड़ का अधिशेष अंतरित किया, जो पिछले वर्ष अंतरित राशि (₹30,307.45 करोड़) और केंद्रीय बजट 2023-24 में आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लाभांश/ अधिशेष हस्तांतरण के तहत बजटीय राशि (₹48,000 करोड़) दोनों से अधिक था।



मार्च 2024 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹1.78 लाख करोड़ होगा, जो 2017 में इसकी स्थापना के बाद से दूसरी सबसे अधिक मासिक राशि दर्ज की गई। 2023-24 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 2022-23 की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक था (चार्ट III.17)।

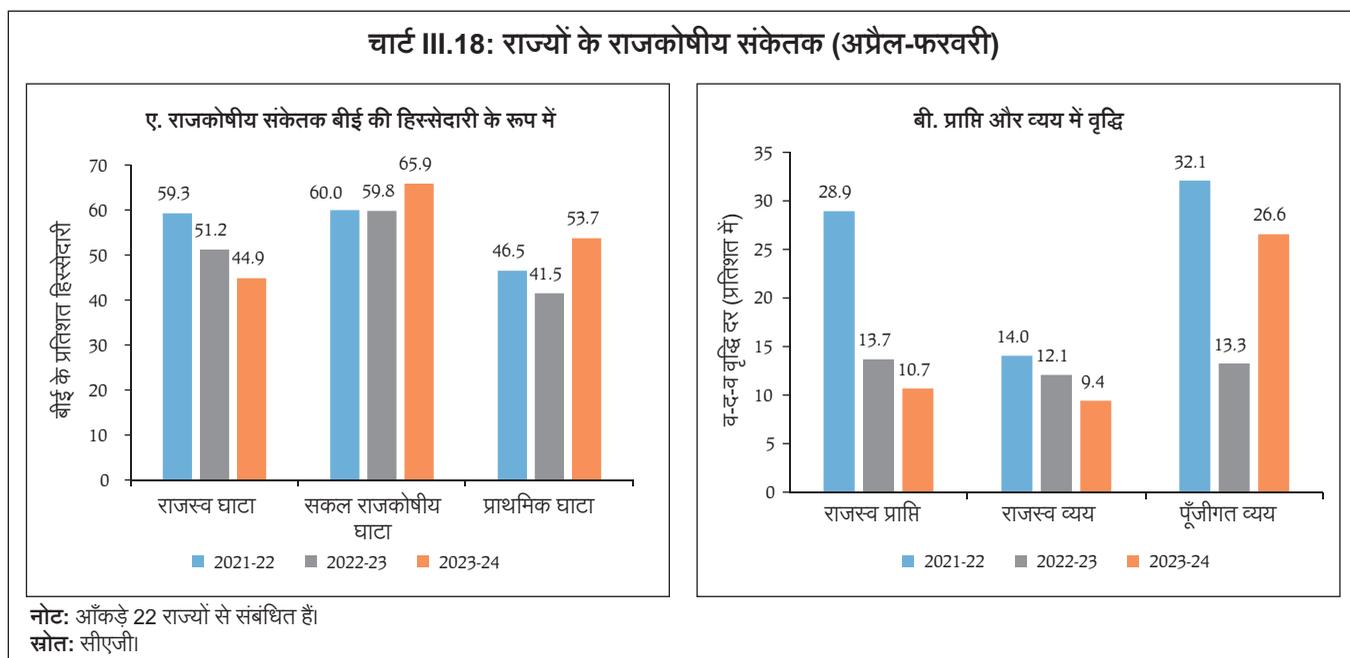
अप्रैल-फरवरी 2024 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का संयुक्त जीएफडी बजट अनुमानों (बीई) का 65.9 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.18 ए)। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में मंदी और



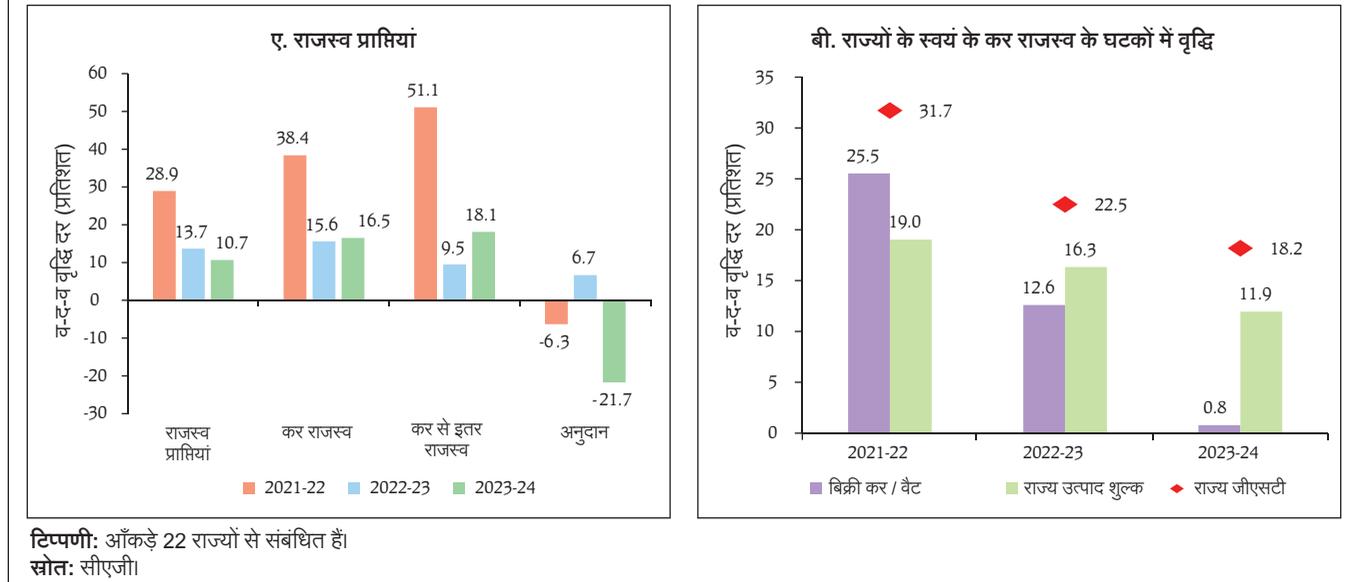


पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई (चार्ट III.18 बी)। प्राप्तियों के मोर्चे पर, उच्च हस्तांतरण के कारण राज्यों के समग्र कर राजस्व में वृद्धि हुई, जबकि स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि धीमी हो गई। गैर-कर राजस्व में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से कुछ राज्यों में भूमि मुद्रीकरण और खनन रॉयल्टी/प्रीमियम

के कारण हुई। जीएसटी मुआवजे की समाप्ति और वित्त आयोग अनुदानों में कमी के कारण केंद्र सरकार से अनुदान में कमी आई (चार्ट III.19 ए)। पूँजीगत व्यय पर राज्यों का जोर जारी रहा, राज्यों के अपने कर राजस्व में, एसजीएसटी, बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष कम हुई (चार्ट III.19बी)।



चार्ट III.19: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-फरवरी)



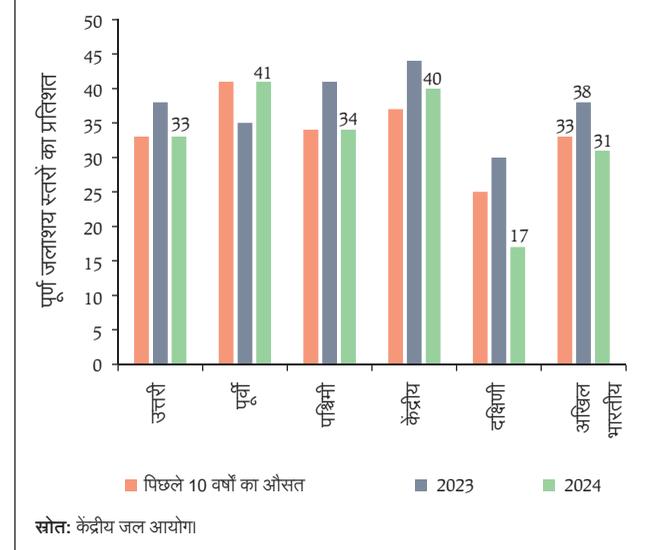
पूँजीगत व्यय में 26.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें राज्यों को पूँजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना से सहायता मिली, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2024 तक ₹95,225.77 करोड़ का वितरण किया जा चुका है।¹²

सकल आपूर्ति

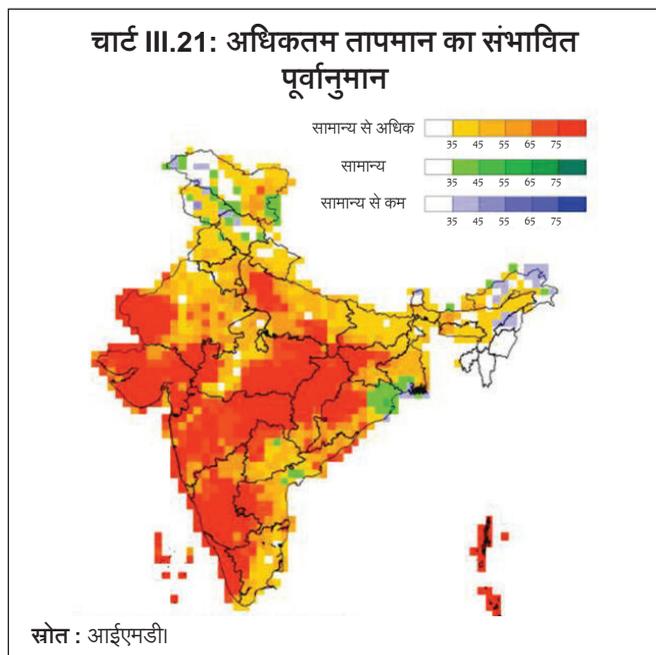
आईएमडी के सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान के बीच कृषि संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है - जून-सितंबर 2024 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में बारिश इस साल सामान्य से अधिक होने की संभावना है, जो ±5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत है। ला नीना की ओर संभावित संक्रमण, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव और उत्तरी गोलार्ध में सामान्य से कम हिमपात आमतौर पर मानसून के लिए अनुकूल होगा। यह देश के 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर की पुनःपूर्ति के लिए अच्छा संकेत है, जो 18 अप्रैल 2024 तक कुल क्षमता के 31 प्रतिशत तक कम हो गया है (चार्ट III.20)। इन जलाशयों में उपलब्ध पानी पिछले साल की तुलना में 17.0 प्रतिशत कम और दशकीय औसत से 3.6 प्रतिशत कम था।

हालांकि, गर्म मौसम के मौसम (अप्रैल से जून 2024) के लिए देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान रहने की संभावना है [चार्ट III.21]। दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी

चार्ट III.20 : जलाशय स्तर (18 अप्रैल 2024 तक)



¹² https://doe.gov.in/files/whats_new_documents/Monthly_Summary_Report_of_DoE_for_February_2024.pdf

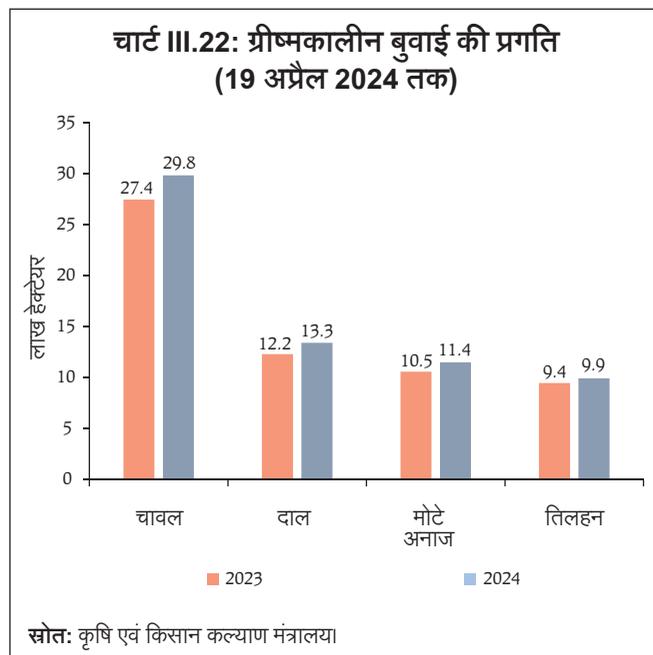


इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मार्च में शुरू होने वाली 2022 की हीटवेव की घटना के विपरीत, 2024 में हीटवेव अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, जब तक कि अधिकांश प्रमुख रबी फसलों (जैसे, गेहूं, रेपसीड, सरसों और चना) की कटाई पूरी होने की उम्मीद है।

19 अप्रैल 2024 तक, ग्रीष्मकालीन फसल क्षेत्र¹³ के 64.5 लाख हेक्टेयर (प्रारंभिक अनुमान) में बुवाई हो चुकी है, जो एक साल पहले की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चावल (8.7 प्रतिशत), दालों (9.1 प्रतिशत), मोटे अनाज (8.7 प्रतिशत) और तिलहन (4.9 प्रतिशत) के तहत अधिक रकबा हासिल किया गया है [चार्ट III.22]।

मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए खुले बाजार में बिक्री (ओएमएस) के माध्यम से गेहूं बाजार में हस्तक्षेप के

¹³ जबकि गर्मी के मौसम में कुल खाद्यान्न उत्पादन (2022-23) का लगभग 5 प्रतिशत ही होता है, यह कुछ व्यक्तिगत फसलों जैसे मूंग (50.3 प्रतिशत), बाजरा (9.5 प्रतिशत), उड़द (8.7 प्रतिशत), चावल (7.5 प्रतिशत) और मक्का (7.1 प्रतिशत) के वार्षिक उत्पादन का उच्च हिस्सा होता है। तिलहन के अंतर्गत, गर्मी के मौसम में कुल सूरजमुखी उत्पादन का 11.8 प्रतिशत हिस्सा होता है।



बाद, 2024-25 के रबी विपणन सत्र (आरएमएस) के लिए सरकारी खरीद 2024 में पहले ही शुरू हो गई है (सामान्य तिथि 01 अप्रैल है) ताकि घटते स्टॉक को फिर से भरा जा सके। इस सत्र के लिए लक्ष्य 300-320 लाख टन¹⁴ निर्धारित किया गया है; 19 अप्रैल, 2024 तक संचयी खरीद 7.1 मिलियन टन थी।

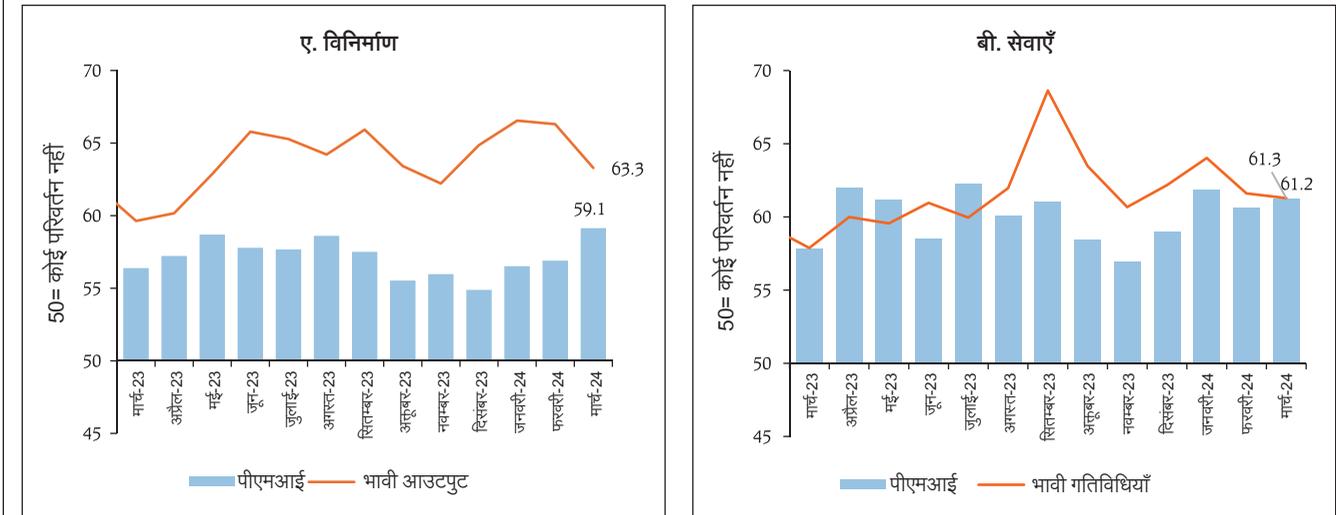
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) में अब तक (01 अक्टूबर, 2023 - 19 अप्रैल, 2024) चावल की संचयी खरीद 462.9 लाख टन रही, जो पिछले सत्र की इसी अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत कम है। 1 अप्रैल, 2024 तक चावल का सार्वजनिक स्टॉक 531.5 लाख टन (बफर मानदंडों से 3.9 गुना) था।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए हेडलाइन पीएमआई मार्च 2024 में 59.1 के 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसे नए ऑर्डर और आउटपुट का समर्थन प्राप्त हुआ (चार्ट III.23ए)। सेवाओं के लिए पीएमआई मार्च में बढ़कर 61.2 हो गया (13 वर्षों में सबसे मजबूत में से एक), जो नए व्यवसाय और रोजगार में ठोस विस्तार से प्रेरित था (चार्ट III.23बी)।

माल परिवहन के संकेतकों ने मिश्रित तस्वीर पेश की। रेलवे

¹⁴ <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2009984>

चार्ट III.23 : क्रय प्रबंधक सूचकांक



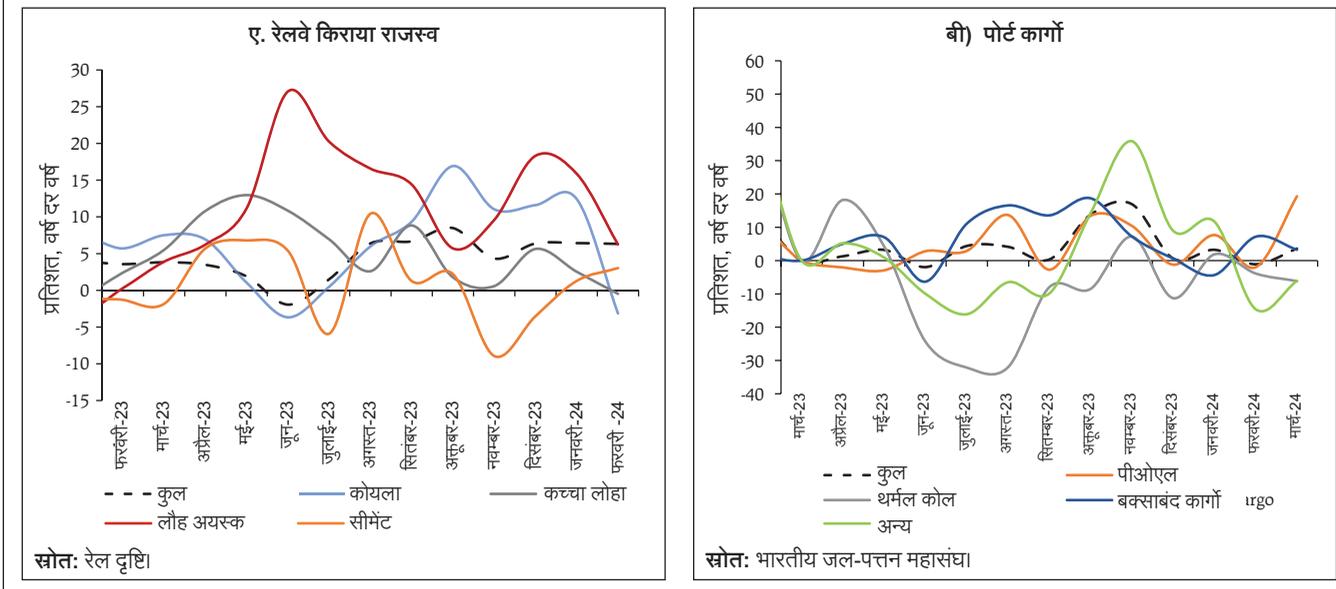
टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार और इसके विपरीत को दर्शाता है।
स्रोत: एस&पी ग्लोबला

माल ढुलाई राजस्व ने फरवरी 2024 में 6.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की, जिसमें सीमेंट की माल ढुलाई में वृद्धि का योगदान शामिल था (चार्ट III.24ए)। मार्च 2024 में पीओएल

(चार्ट III.24बी) के कारण प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

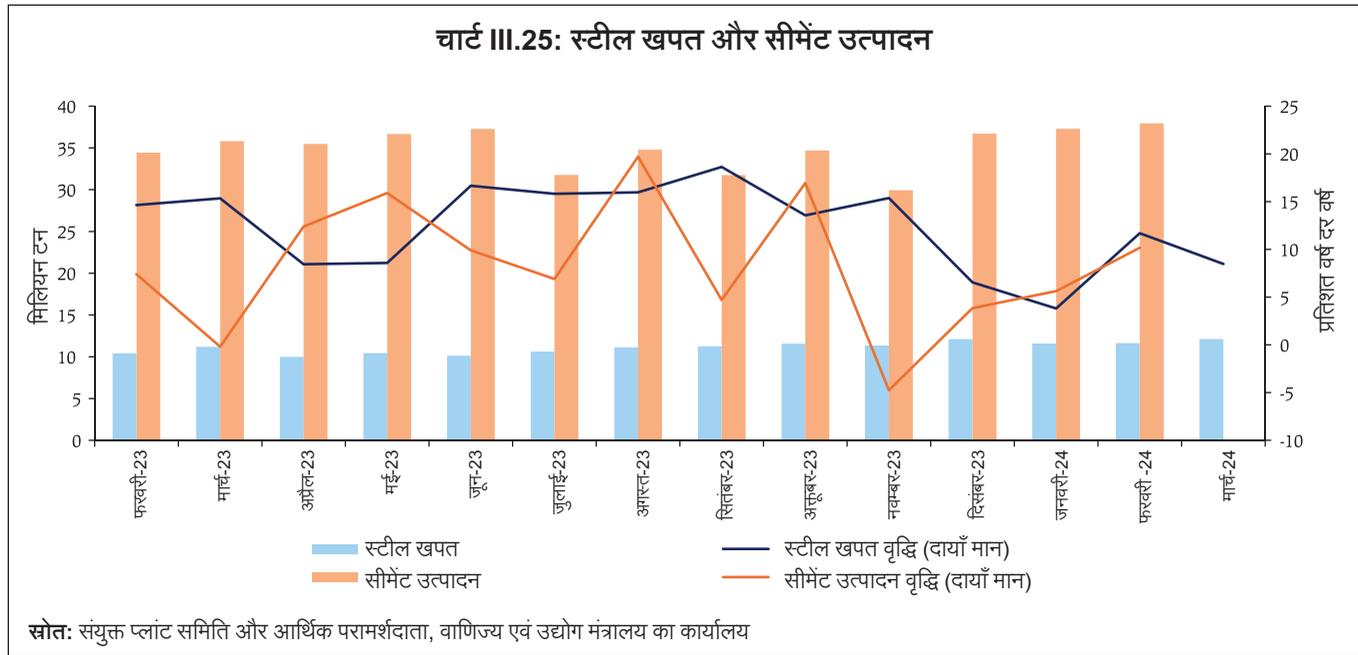
निर्माण क्षेत्र के संकेतकों ने इस्पात की खपत और सीमेंट

चार्ट III.24: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक



स्रोत: रेल दृष्टि

स्रोत: भारतीय जल-पत्तन महासंघ



उत्पादन में निरंतर वृद्धि को दर्शाया (चार्ट III.25)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक मार्च 2024 में एक आशावादी तस्वीर प्रदर्शित करते हैं (सारणी III.1)।

सारणी III.1 : उच्च आवृत्ति संकेतक सेवाएँ

		वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)											
क्षेत्र	संकेतक	मई-23	जून-23	जुलाई-23	अग-23	सित-23	अक्तू-23	नव-23	दिस-23	जन-23	फर-23	मार्च-23	
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	14.9	1.6	2.9	11.6	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	
	ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहन बिक्री	17.4	1.7	-7.2	0.6	0.8	20.1	31.3	16.0	26.2	30.0	15.3
		तीन पहिया वाहन बिक्री	70.4	98.6	78.9	68.8	47.0	42.1	30.8	30.6	9.5	4.6	4.3
		ट्रैक्टर बिक्री	1.2	4.2	6.1	1.1	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-33.0	-23.1
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-3.3		6.9			3.2			-3.8			
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	1.9	-1.9	1.5	6.4	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4	6.3		
	पोर्ट कार्गो यातायात	3.5	0.4	4.3	4.4	0.3	13.8	17.0	0.7	3.2	-1.1	3.6	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	-4.5	-5.6	-4.1	6.0	-4.5	10.6	9.0	8.7	10.0	7.6	2.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात*	2.7	2.7	1.0	7.4	2.7	15.0	4.9	12.2	19.3	25.7	15.6	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	15.7	19.2	26.3	23.6	19.3	10.7	8.7	8.1	5.0	2.2	4.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	37.2	26.5	23.6	21.5	19.6	17.5	19.8	18.1	17.0	15.2	14.6	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	19.7	15.5	16.4	19.5	9.5	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	23.0	18.8	20.8	22.6	12.4	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	14.3	9.9	9.1	14.4	4.9	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	
	होटल कमरा बुकिंग दर@	61.9	64.0	60.9	60.9	61.0	62.5	63.0	70.0				
	प्रति कमरा औसत राजस्व	15.8	14.0	14.2	13.9	18.3	14.8	15.9	12.8				
	यात्री आगमन	41.25055	24.0	13.6	22.6	17.5	19.8	16.8	7.8				
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	8.6	16.7	15.8	16.0	18.6	13.6	15.4	6.5	3.8	11.7	8.5	
	सीमेंट उत्पादन	15.9	9.9	6.9	19.7	4.7	17.0	-4.0	3.8	5.6	10.2		
पीएमआई संकेतक#	सेवाएँ	61.2	58.5	62.3	60.1	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	

<< संकुचन ----- प्रसार >>

नोट: #: स्तरों के आधार पर डेटा। *: मार्च 2024 के लिए आंकड़े दैनिक संख्या के मासिक औसत के आधार पर हैं। आंकड़े दर में हैं न कि संवृद्धि की माह दर माह दर के आधार पर। हिट मैप को जुलाई -2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतकों के लिए तैयार किया गया है।

स्रोत: सीएमआई, सीआईसी, आईएचएस मार्केट, सियाम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त संयंत्र समिति।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय सीपीआई¹⁵ में वर्ष-दर-वर्ष होने वाले बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति फरवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 4.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.26)। सूचकांक स्तरों के संदर्भ में, खाद्य और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में लगभग 0.2 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी भरपाई ईंधन की कीमतों में (-) 2.6 प्रतिशत की मासिक गिरावट से हुई।

खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी में 7.8 प्रतिशत से मार्च 2024 में 7.7 प्रतिशत तक कम हो गई क्योंकि 16 बीपीएस की सकारात्मक मूल्य गति 23 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव के कारण समायोजित थी। उप-समूहों के संदर्भ में, फलों, सब्जियों, दालों और मसालों के संबंध में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई (चार्ट III.27)। अनाज, मांस और मछली की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ी जबकि तेल और वसा में अपस्फीति की दर कम हुई।

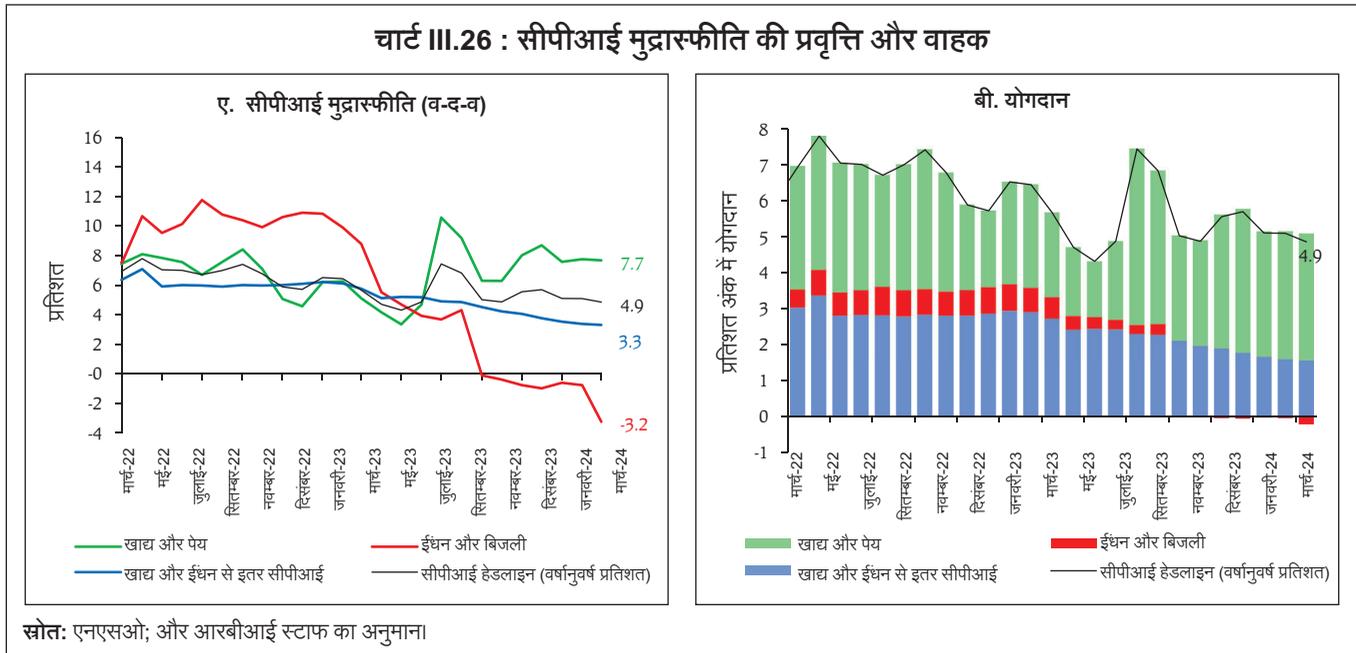
ईंधन और बिजली समूह की कीमतों में गिरावट फरवरी में (-) 0.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में (-) 3.2 प्रतिशत हो गई, जो

मार्च में एलपीजी की कीमतों में कटौती को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कीमतों में (-) 22.3 प्रतिशत की गिरावट आई। केरोसिन की कीमतों में भी (-) 2.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई।

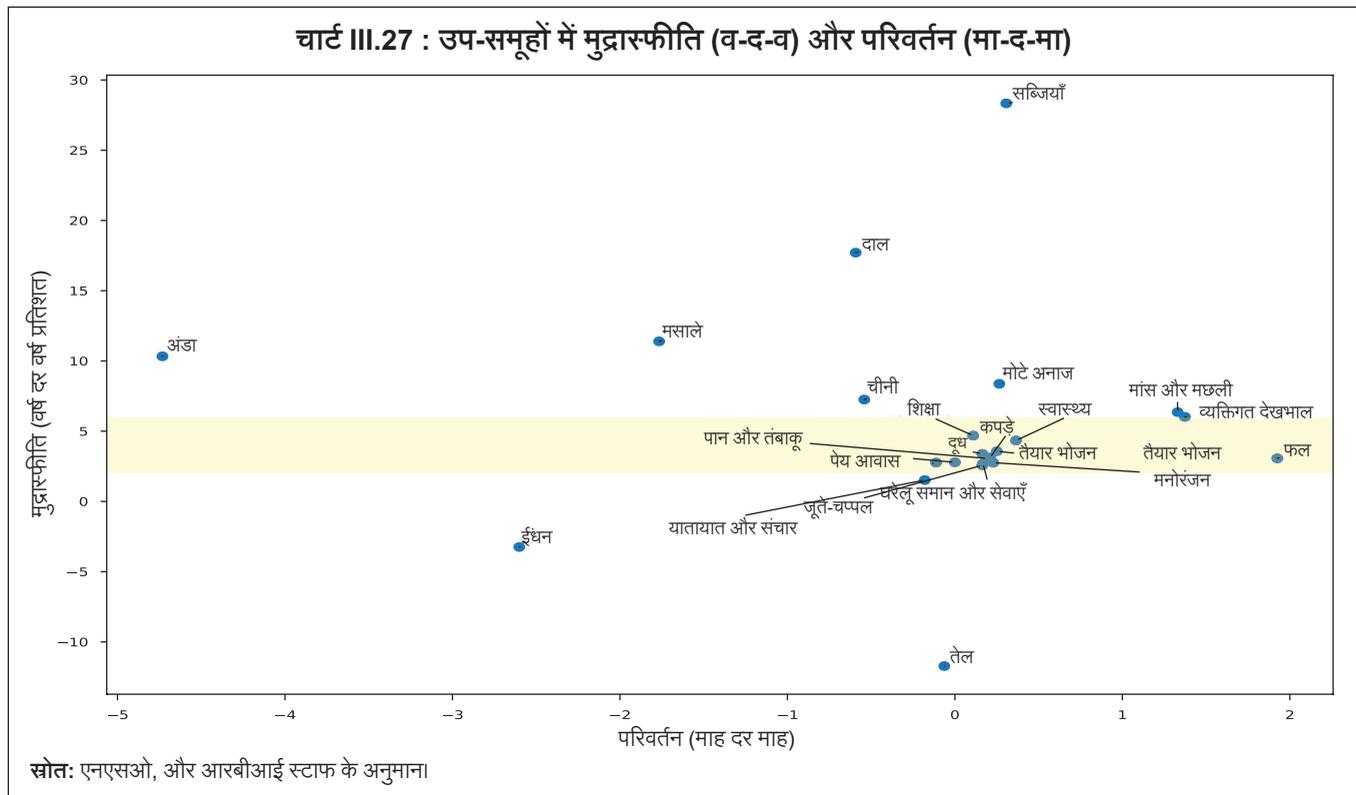
कोर मुद्रास्फीति फरवरी में 3.4 प्रतिशत से मार्च में और कम होकर 3.3 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई (2012=100) शृंखला में सबसे कम है। यह नरमी व्यापक आधार पर थी, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, तथा मनोरंजन और आमोद-प्रमोद को छोड़कर विभिन्न उप-समूहों में मुद्रास्फीति में नरमी आई (चार्ट III.28)। परिवहन और संचार मुद्रास्फीति में नरमी ने मुख्य रूप से मार्च के मध्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के प्रभाव को दर्शाया। सोने की कीमतों में तेजी के कारण व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव में मुद्रास्फीति बढ़ी।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, जबकि सीपीआई-ग्रामीण मुद्रास्फीति मार्च में लगभग 10 बीपीएस बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई, सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति 64 बीपीएस घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 4-6 प्रतिशत के दायरे में रही (चार्ट III.29)।

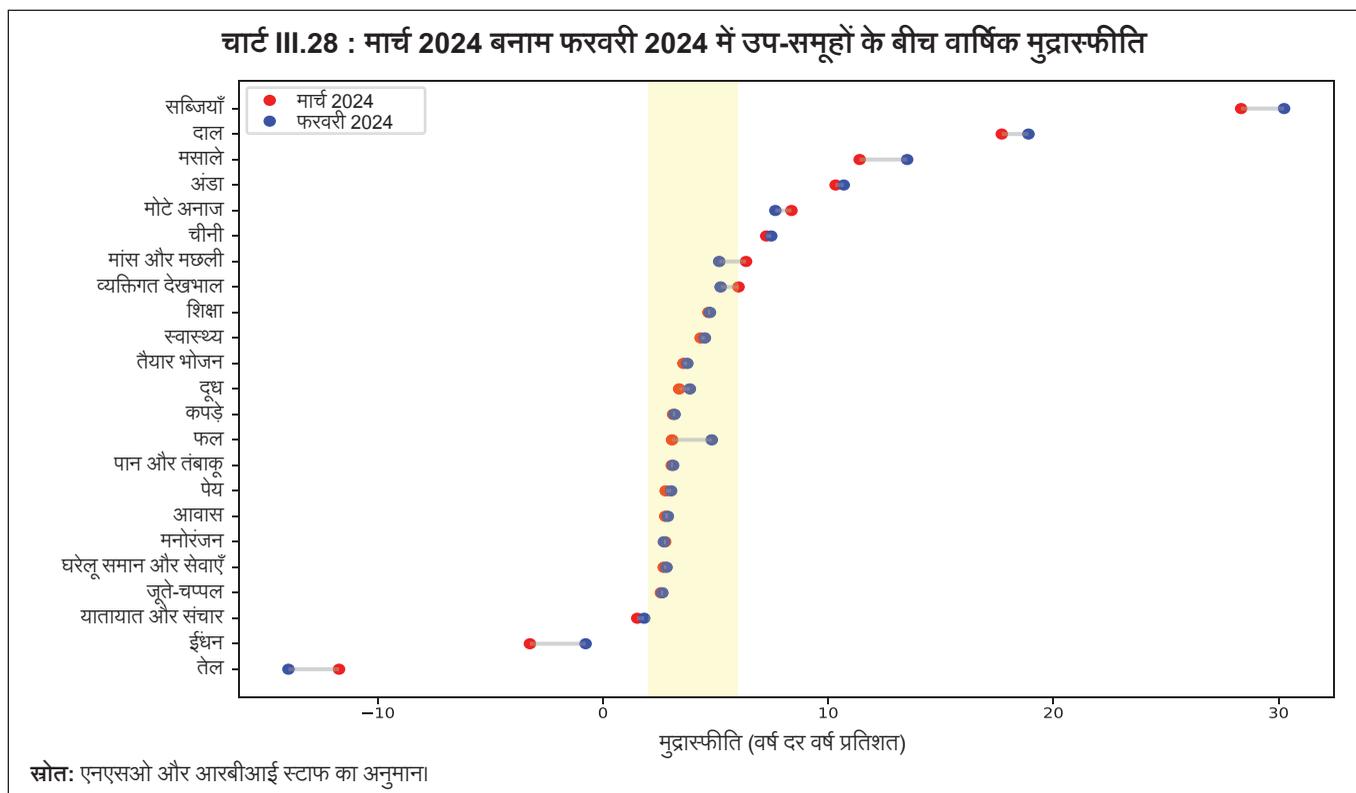
चार्ट III.26 : सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक



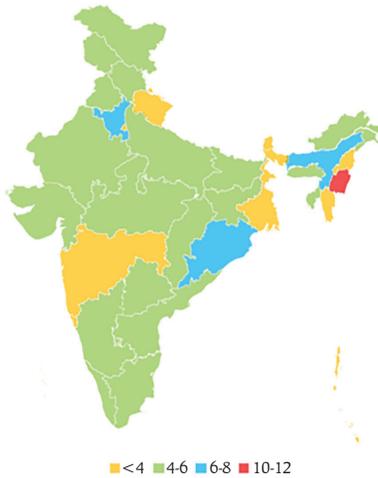
¹⁵ एनएसओ द्वारा 12 अप्रैल, 2024 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।



अप्रैल के लिए अब तक (19 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि अनाज की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि दालों की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही। दिसंबर 2022 से गिरावट की ओर अग्रसर



चार्ट III.29 : मुद्रारस्फीति मार्च 2024 का स्थानिक वितरण (सीपीआई-संयुक्त, व-द-व प्रतिशत)



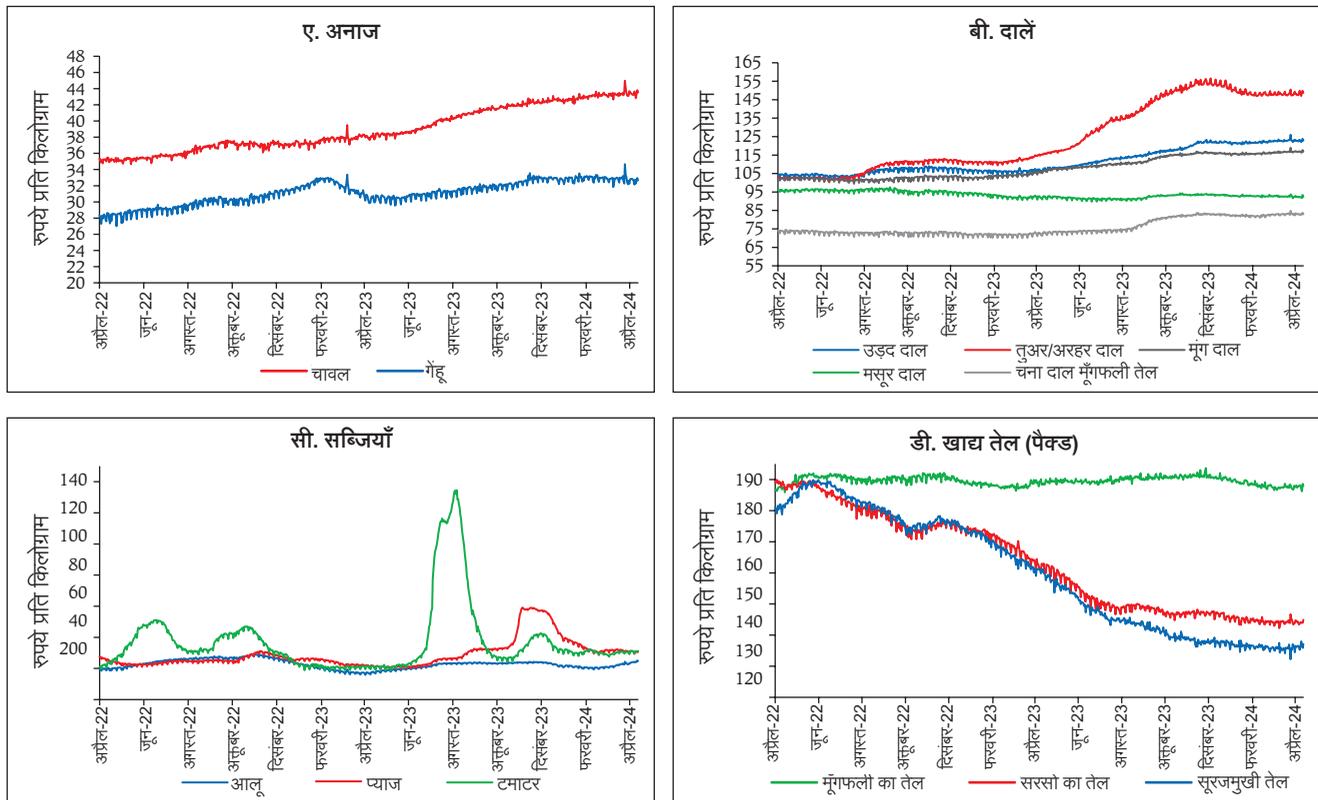
नोट: मानचित्र केवल व्याख्या के लिए है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

अप्रैल में तेजी देखी गई, वहीं प्याज की कीमतों में और वृद्धि हुई (चार्ट III.30)। प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) को निर्देश दिया है कि वे रबी की फसल के बाजार में आने के साथ ही किसानों से सीधे बफर निर्माण के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करें।

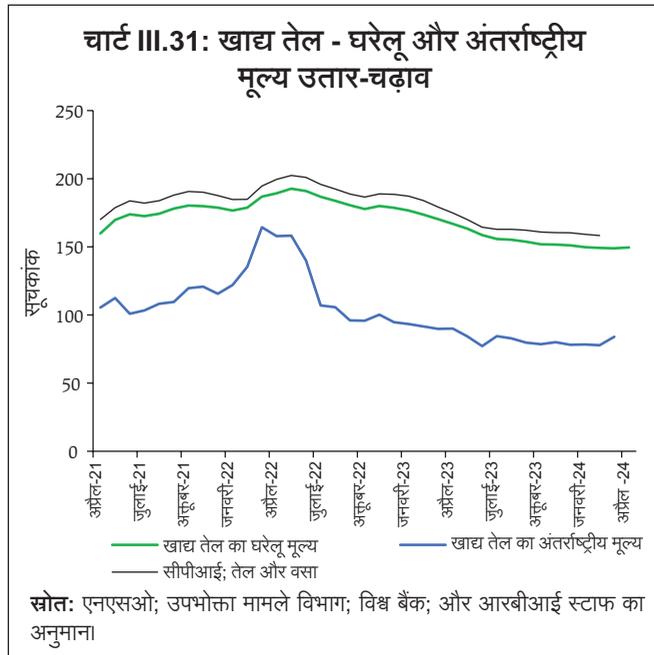
दिसंबर 2022 से खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल कीमतों में नरमी के अनुरूप कम हो रही थीं (चार्ट III.31)। हालांकि, मार्च 2024 में सभी प्रमुख खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि से आयात कीमतों में तेजी आई है। प्रमुख निर्यातकों (जैसे, इंडोनेशिया) द्वारा बायोडीजल अनिवार्यताओं के कार्यान्वयन के कारण खाद्य तेलों की स्थानीय खपत में संभावित वृद्धि से भी जोखिम बना हुआ है, जो उनके निर्यात को बाधित करेगा और वैश्विक कीमतों पर प्रभाव डालेगा।

खाद्य तेल की कीमतों में अप्रैल में व्यापक आधार पर तेजी देखी गई। प्रमुख सब्जियों में, जहां टमाटर और आलू की कीमतों में

चार्ट III.30 : डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य



स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ के आकलन



15 मार्च, 2024 से पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कमी की गई। हालांकि, मार्च में केरोसिन की कीमत में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल में अब तक (19 अप्रैल तक), जबकि केरोसिन की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.2)।

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह दर माह (प्रतिशत)	
		फर-24	मार्च-24	अप्रैल-24 [^]	मार्च-24	अप्रैल-24 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.91*	100.91	-2.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.72*	90.72	-2.2	0.0
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	49.43	49.79	49.57	0.7	-0.44
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	913.25	813.25**	813.25	-10.9	0.0

[^]: 1-19 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए। * : 15 मार्च 2024 से प्रभावी

** : 09 मार्च 2024 से प्रभावी

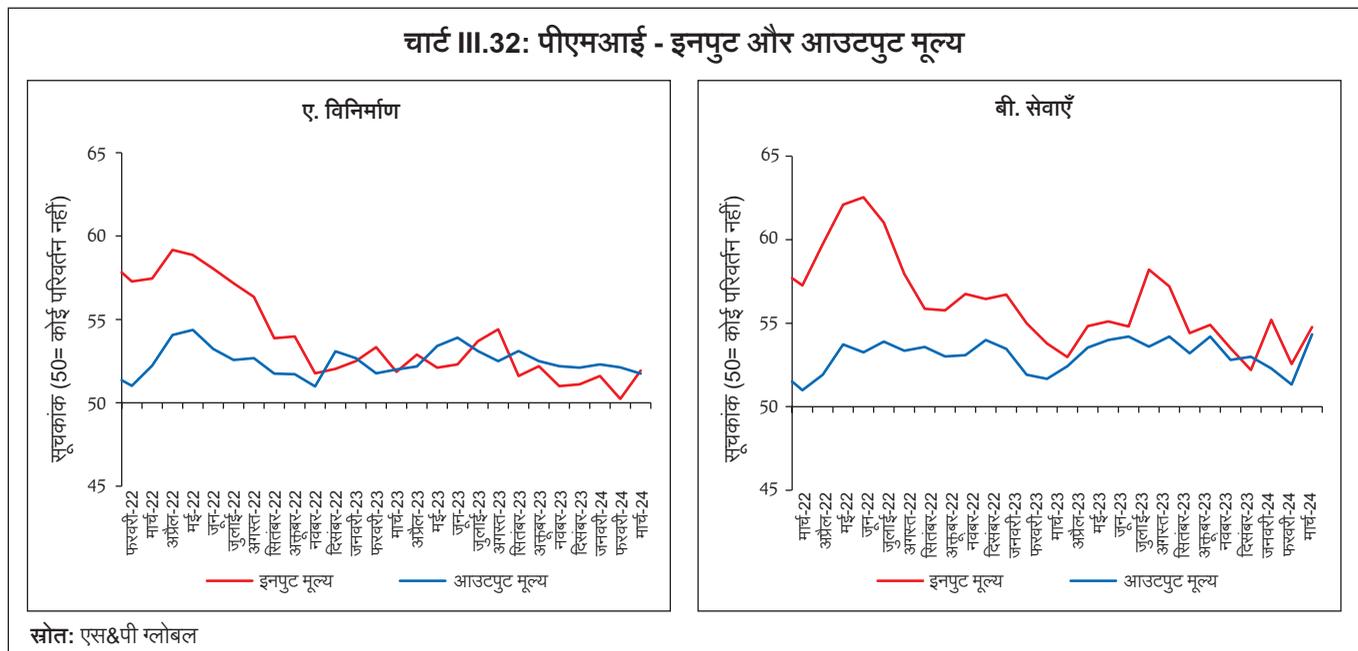
नोट: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई

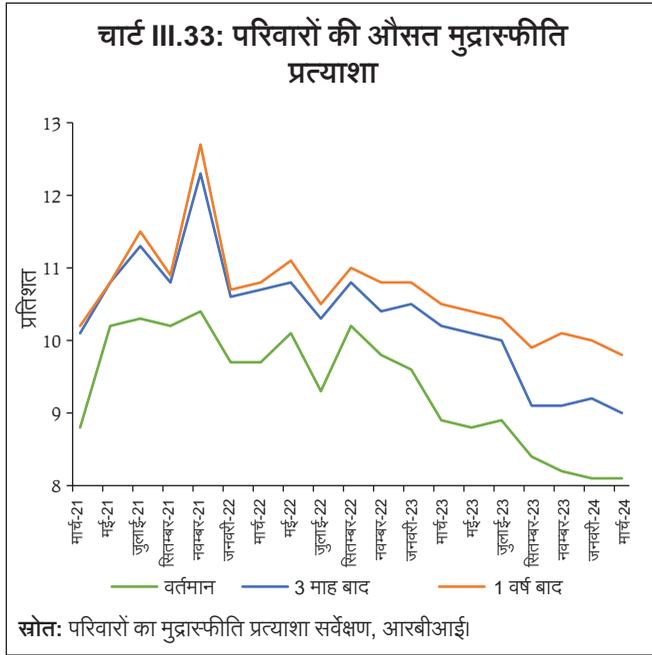
में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

मार्च 2024 के लिए पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में वृद्धि का संकेत दिया। विनिर्माण फर्मों के लिए बिक्री मूल्य वृद्धि मार्च में धीमी हो गई, जबकि सेवा फर्मों में मूल्य वृद्धि साढ़े छह साल में सबसे तेज गति से हुई (चार्ट III.32)।

आरबीआई के नवीनतम द्वि-मासिक मुद्रास्फीति सर्वेक्षण में, परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में 3 महीने और एक वर्ष आगे के लिए 20 आधार अंकों की कमी आई (चार्ट III.33)।



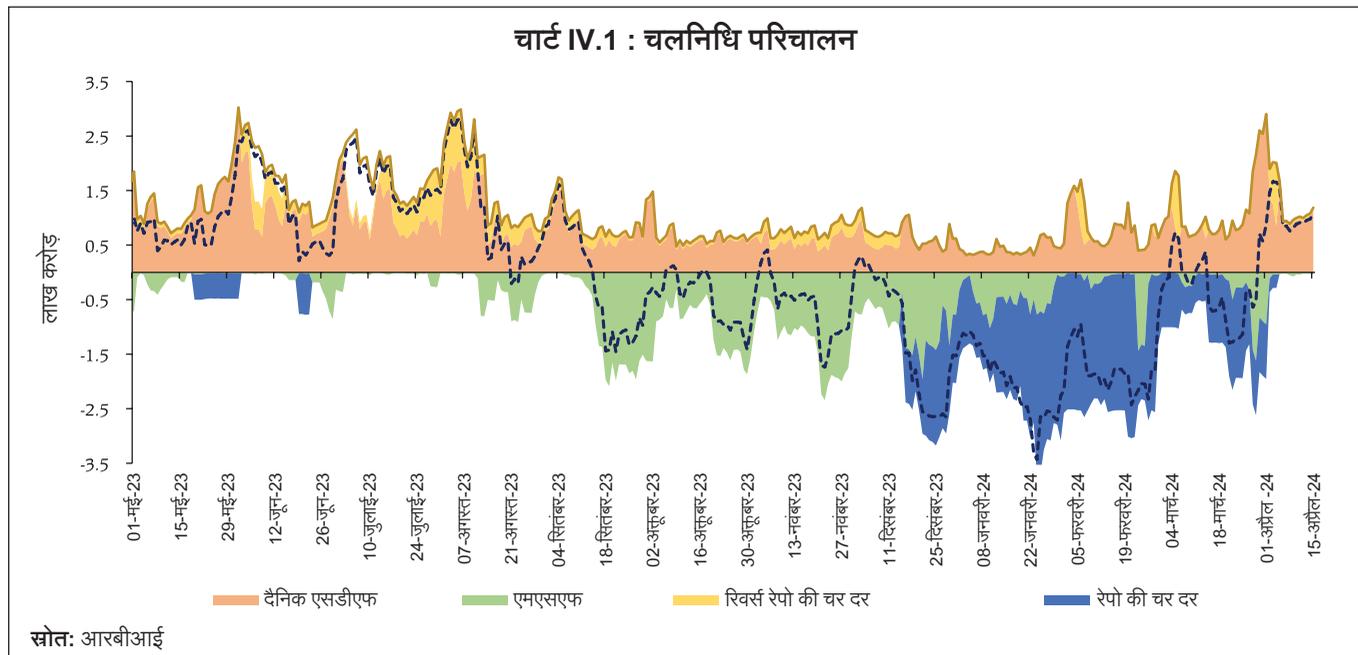


सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और आरबीआई के बाजार परिचालन ने प्रणालीगत चलनिधि को सुचारु बना दिया। जबकि जीएसटी संग्रह और अग्रिम कर भुगतान के कारण सरकारी नकदी जमाशेष ने चलनिधि को बीच-बीच में कठोर किया, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बदल गई। निवल आधार पर, एलएएफ के तहत अप्रैल 2024 (19 अप्रैल तक) के दौरान औसत अवशोषण ₹1.07 लाख करोड़ था [चार्ट IV.1]। कुल मिलाकर, रिज़र्व बैंक ने 16 मार्च - 19 अप्रैल, 2024 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में संचयी रूप से ₹4.16 लाख करोड़ अंतर्विष्ट किया। एक विशेष मामले के रूप में, अन्य पात्र प्रतिभागियों के साथ स्टैंड-अलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को भी 27 मार्च, 2024 को परिचालित ₹75,000 करोड़ की 6-दिवसीय वीआरआर नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई।

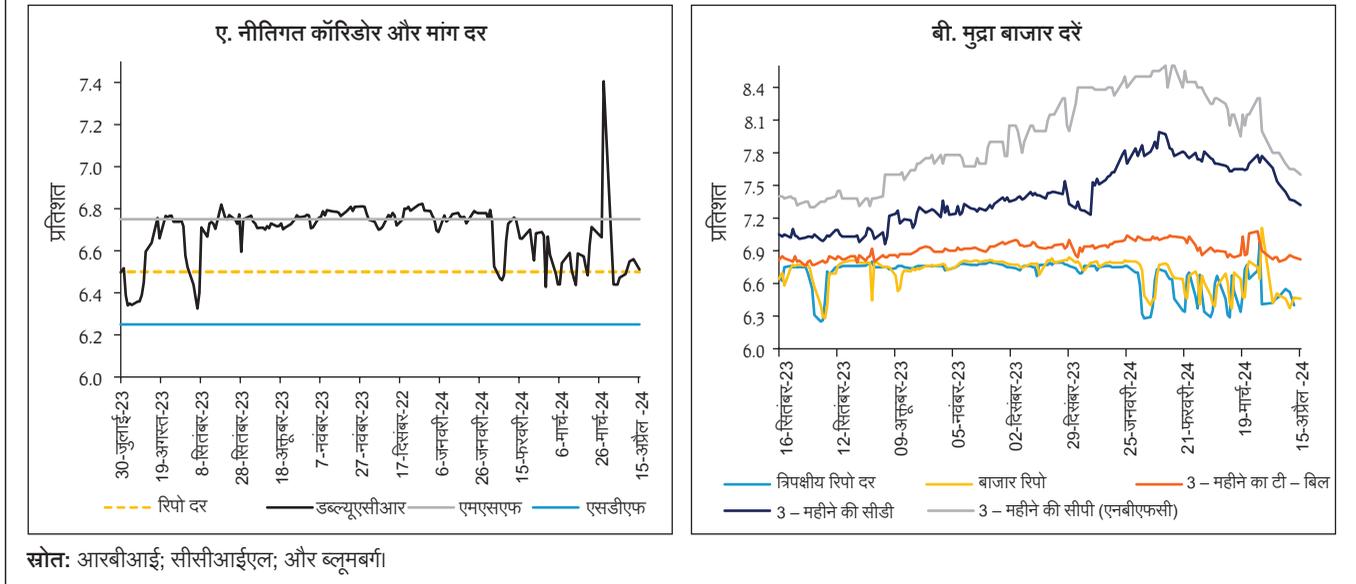
IV. वित्तीय स्थितियाँ

मार्च में चलनिधि की स्थिति अनुकूल हो गई, जिससे निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) [सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) सहित] अंतर्वेशन फरवरी 2024 में ₹1.78 लाख करोड़ से कम होकर ₹0.29 लाख करोड़ हो गया।

अप्रैल में, रिज़र्व बैंक ने 14 दिनों की परिपक्वता अवधि वाला एक मुख्य परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) और एक दिन से तीन दिनों की परिपक्वता अवधि (19 अप्रैल तक) की सात फाइन-ट्यूनिंग वीआरआरआर नीलामी आयोजित की, जिससे कुल मिलाकर ₹2.29 लाख करोड़ जुटाए गए। जैसा कि इस लेख के पिछले संस्करण में बताया गया है, बैंकों ने लंबी



चार्ट IV.2 : नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर



अवधि के वीआरआरआर के बजाय एकदिवसीय स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत धन रखना पसंद किया है। बैंकों द्वारा अधिशेष निधियों को लंबी अवधि में रखने की अनिच्छा को दर्शाते हुए, 5 अप्रैल, 2024 को आयोजित 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी को बहुत कम प्रतिक्रिया मिली (₹1.25 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले ₹0.05 लाख करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ)। मार्च के दूसरे पखवाड़े से 19 अप्रैल, 2024 तक के दौरान ₹1.29 लाख करोड़ के औसत कुल अवशोषण में से, एसडीएफ के तहत निधियों का निवेश 90 प्रतिशत (₹1.16 लाख करोड़) था, जबकि शेष वीआरआरआर परिचालनों के माध्यम से अवशोषित किया गया।

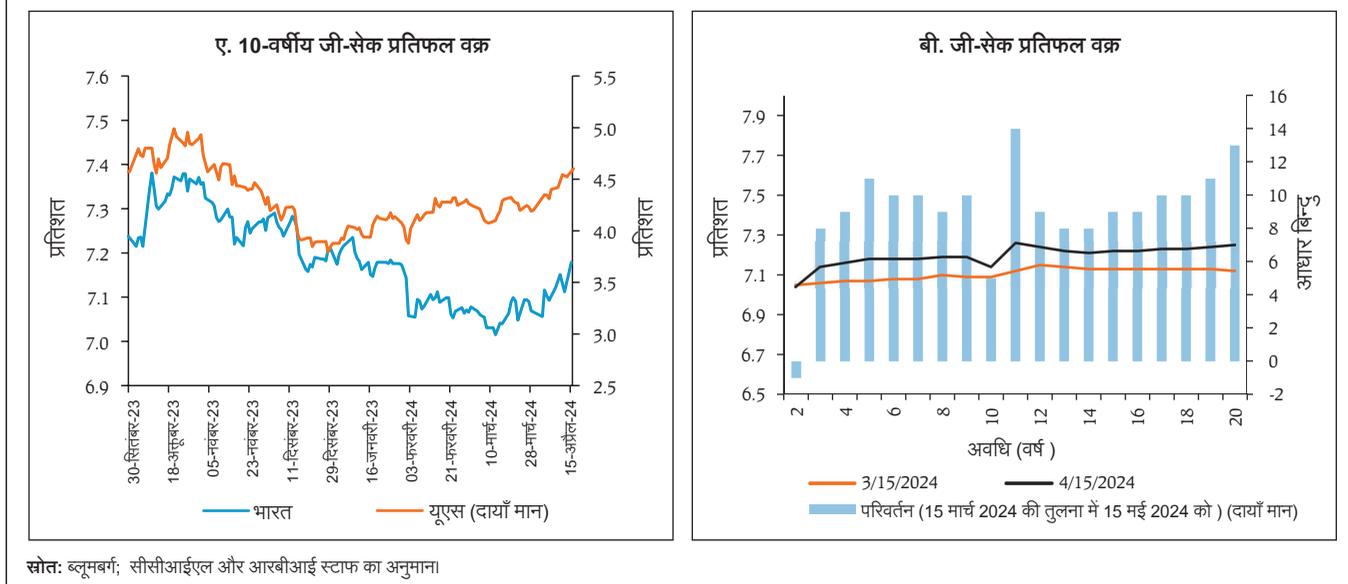
इन चलनिधि परिचालनों को दर्शाते हुए, भारत औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - फरवरी की नीति बैठक के बाद से सामान्य रूप से वर्ष के अंत में होने वाली वृद्धि को छोड़कर नीतिगत सीमा के भीतर रहा है। 16 मार्च - 19 अप्रैल, 2024 के दौरान डबल्यूएसीआर औसतन 6.58 प्रतिशत रहा, जबकि 16 फरवरी-15 मार्च, 2024 के दौरान यह 6.57 प्रतिशत था (चार्ट IV.2 ए)। संपार्श्विक खंड में दरें - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो दरें - डबल्यूएसीआर (चार्ट IV.2 b) के साथ-साथ रहीं।

सावधि मुद्रा बाजार क्षेत्र में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कम हो गया (चार्ट IV.2 बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने का सीपी माइन्स 91-दिवसीय टी-बिल) 16 फरवरी - 15 मार्च, 2024 के दौरान 141 बीपीएस से घटकर 16 मार्च - 19 अप्रैल, 2024 के दौरान 98 बीपीएस हो गया। जहाँ अल्पकालिक दरें चलनिधि परिचालनों के साथ आगे बढ़ीं, दीर्घकालिक दरें काफी हद तक स्थिर रहीं।

प्राथमिक बाजार में, सीडी जारी करने के माध्यम से संसाधन जुटाना 2023-24 के दौरान ₹8.58 लाख करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹6.74 लाख करोड़ था, क्योंकि जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से पीछे रही। 2023-24 के दौरान सीपी जारी करना ₹13.75 लाख करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.73 लाख करोड़) पर काफी हद तक स्थिर रहा।

भारतीय बेंचमार्क 10-वर्षीय जी-सेक पर प्रतिफल 15 मार्च को 7.06 प्रतिशत से बढ़कर 19 अप्रैल, 2024 को 7.23 प्रतिशत हो गई, जो कि अमेरिकी खजाना प्रतिफल में वृद्धि से

चार्ट IV.3 : सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रगति



संकेत लेती है (चार्ट IV.3 ए)। प्रतिफल वक्र ऊपर की ओर खिसक गया, लेकिन परिपक्वता अवधि संरचना के मध्य से लेकर दीर्घ अवधि तक अपेक्षाकृत सपाट रहा (चार्ट IV.3 बी)।

कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल में आम तौर पर नरमी आई और जोखिम प्रीमियम कम हुआ। बॉण्ड मार्केट में औसत जोखिम प्रीमियम (3 साल के जी-सेक प्रतिफल पर एएए-रेटेड

3-वर्षीय कॉरपोरेट बॉण्ड का प्रसार) 16 फरवरी - 15 मार्च, 2024 के दौरान 79 बीपीएस से घटकर 68 बीपीएस हो गया (सारणी IV.1)। 2023-24 (फरवरी तक) के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करके जुटाए गए निधि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान ₹6.7 लाख करोड़ की तुलना में ₹7.4 लाख करोड़ अधिक थे। वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल बनी रहीं, जैसा कि जी-सेक और बॉण्ड बाजार में कम अवधि के प्रसार में परिलक्षित होता है।

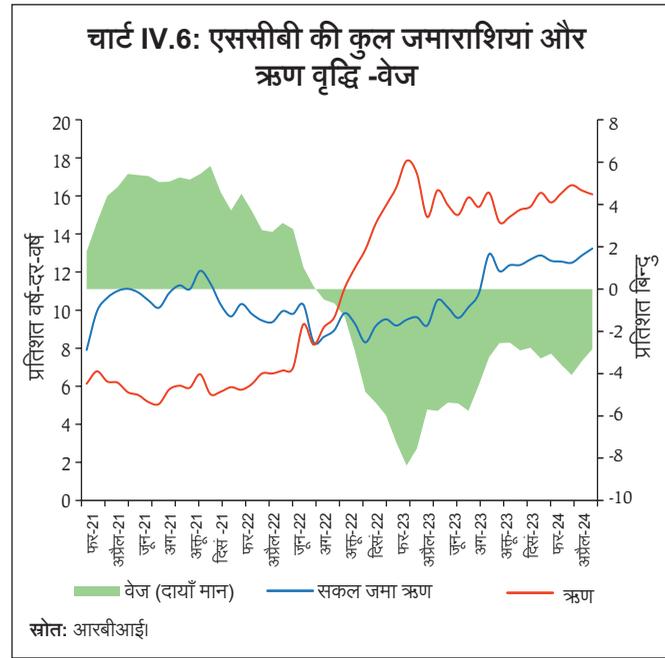
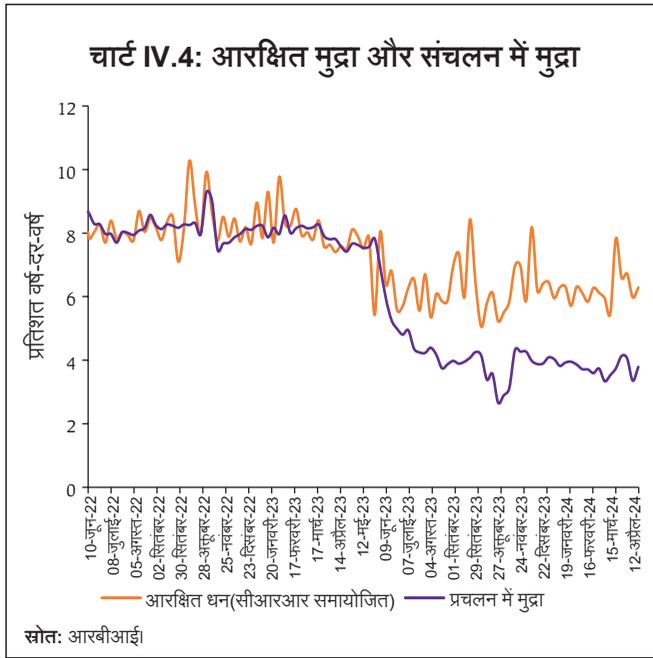
सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 फरवरी 2024 - 15 मार्च 2024	Mar 16, 2024 - Apr 19, 2024	Variation	Feb 16, 2024 - Mar 15, 2024	Mar 16, 2024 - Apr 19, 2024	भिन्नता (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	8.01	7.86	-15	79	70	-9
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.96	7.89	-7	79	68	-11
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.81	7.79	-2	63	55	-8
(iv) एए (3-वर्ष)	8.54	8.48	-6	138	126	-12
(v) बीबीबी-घटाव (3-वर्ष)	12.19	12.09	-10	502	487	-15

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमडीए और ब्लूमबर्ग।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में बदलावों के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 12 अप्रैल, 2024 तक 6.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक साल पहले 7.5 प्रतिशत) [चार्ट IV.4]। प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि, जो आरएम का सबसे बड़ा घटक है, एक साल पहले 7.4 प्रतिशत से घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई, जो ₹2000 के बैंक नोटों की 97.7 प्रतिशत तक बैंकिंग प्रणाली में वापसी¹⁶ को दर्शाती है, जिसमें ज्यादातर जमा के रूप में (29 मार्च, 2024 तक) आया है।

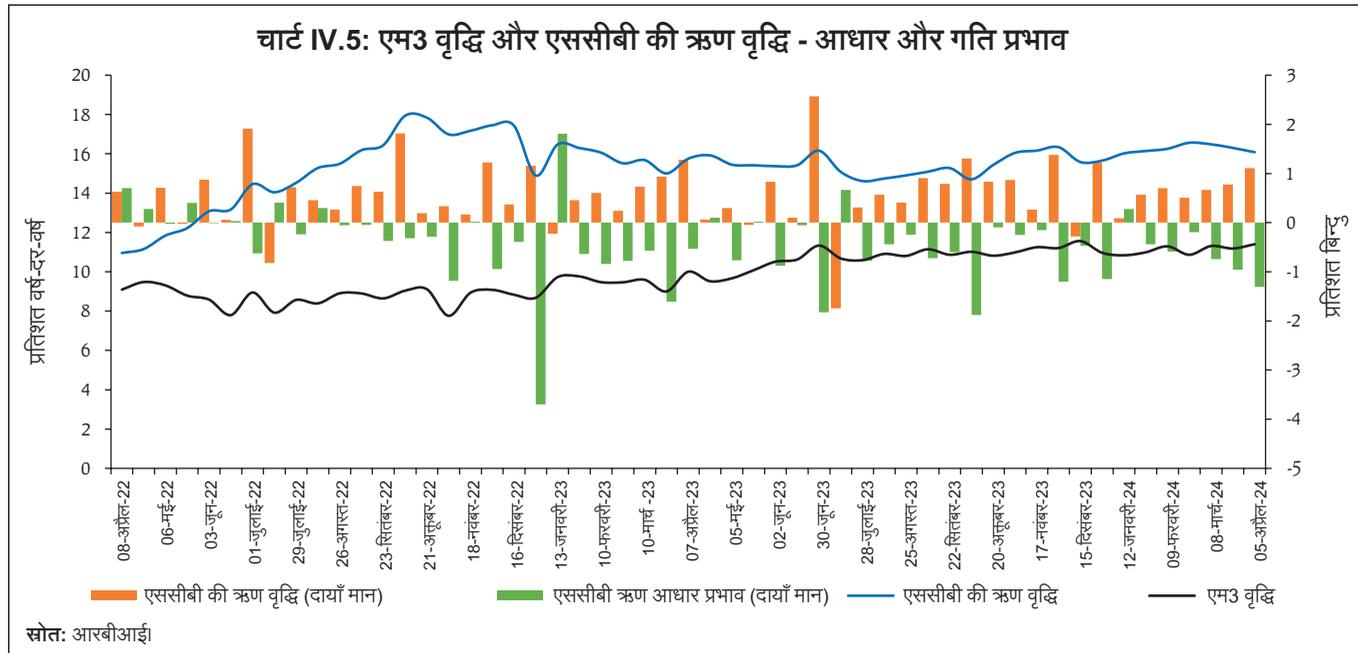
¹⁶ 19 मई 2023 को घोषित किया गया।



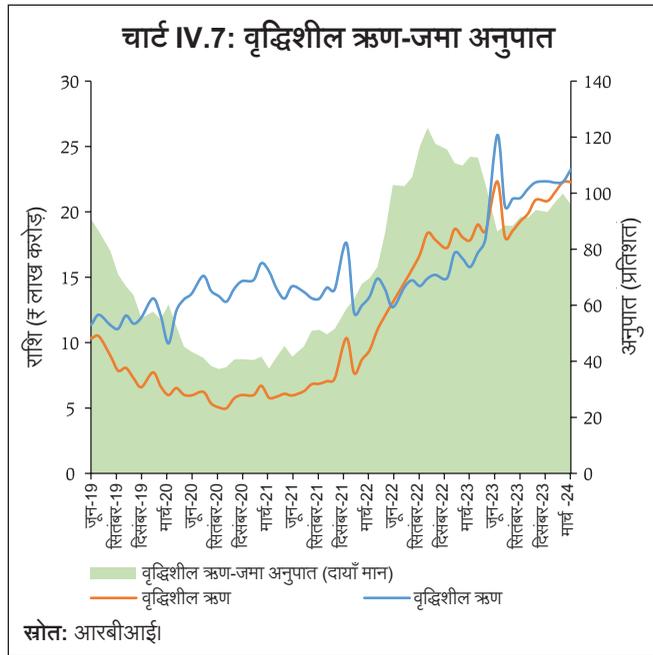
मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 11.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 10.0 प्रतिशत)।¹⁷ बैंकों के पास कुल जमा राशि, जो एम³ का सबसे बड़ा घटक है, में 12.6 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 9.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 5 अप्रैल, 2024 तक 16.1 प्रतिशत रही (एक वर्ष पहले 15.8 प्रतिशत) [चार्ट IV.5]।

मार्च 2024 में एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) दोहरे अंकों में रही (चार्ट IV.6)। 22 मार्च, 2024

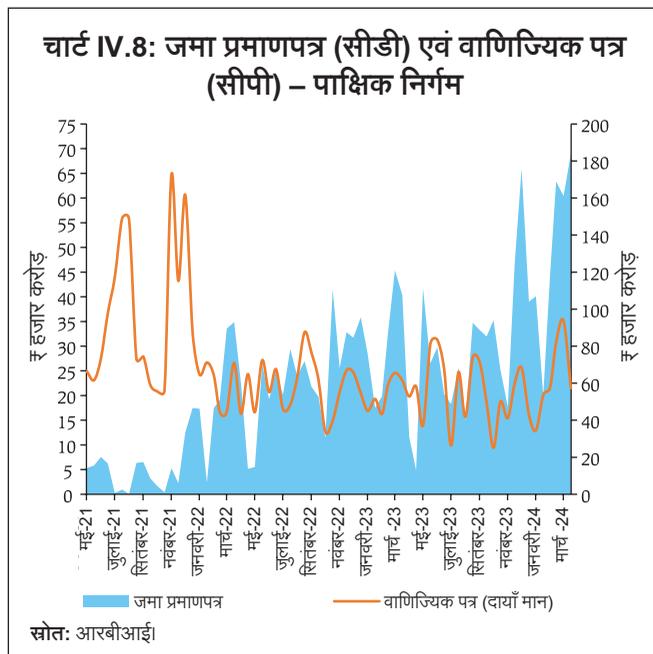


¹⁷ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)



तक, प्रणालीगत स्तर पर वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 95.9 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.7)।

सीआरआर और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होने के साथ, 31 मार्च 2024 तक ऋण विस्तार के वित्तपोषण के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास लगभग



सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार बिन्दुओं में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर (बीपीएस)	सावधि जमा दरें		उधार दरें			
		डब्ल्यूएडी टीडीआर (नया जमा)	डब्ल्यूएडी टीडीआर (बकाया जमा)	ईबीएल आर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यक)	डब्ल्यूए एलआर-नया रुपया उधार	डब्ल्यूए एलआर-बकाया रुपया उधार
ढील वाली अवधि फरवरी 2019- मार्च 2022	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्ती वाली अवधि मई -22 से फरवरी 2024	+250	241	183	250*	167*	185	111

टिप्पणियाँ: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा मार्च 2024 से संबंधित है।

डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर। डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर; एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।

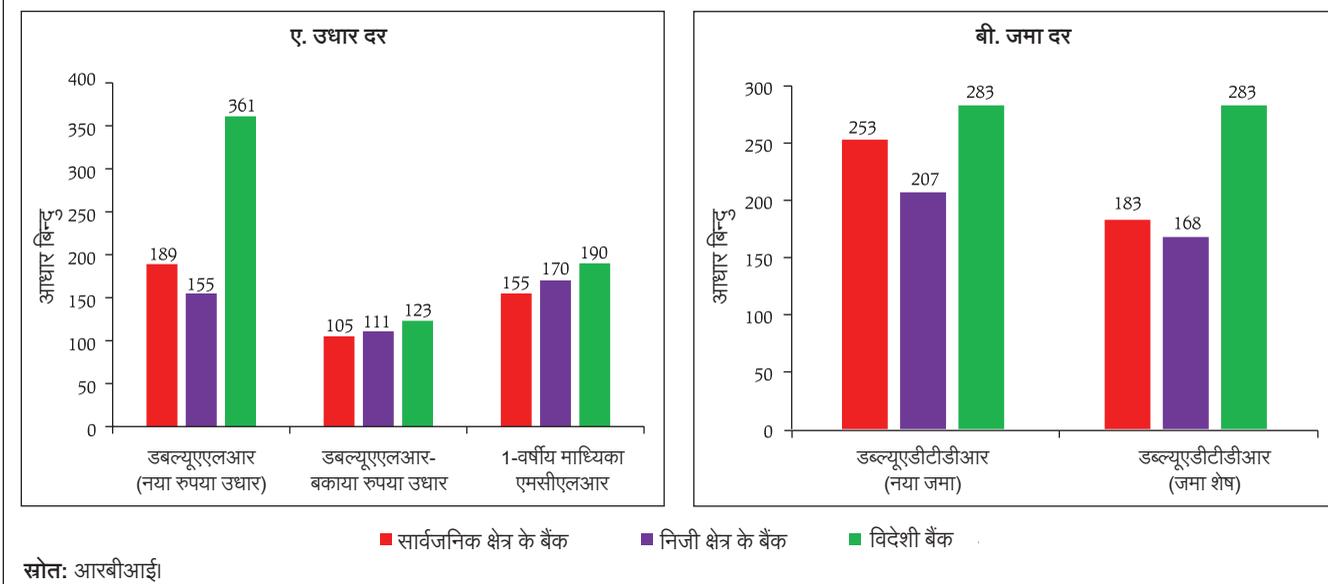
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

77 प्रतिशत जमा उपलब्ध थी। जमा आधार को सीडी जारी करके सुदृढ़ बनाया गया (चार्ट IV.8)।

नीतिगत रेपो दर में 250 बीपीएस की वृद्धि के प्रति उत्तर में, बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) में भी इसी परिमाण से वृद्धि हुई। साथ ही, मई 2022 से फरवरी 2024 के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 185 बीपीएस और 111 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा के मामले में, इसी अवधि के दौरान नए और बकाया जमा पर भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 241 बीपीएस और 183 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)। मई 2022 से मार्च 2024 के दौरान 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 167 बीपीएस की वृद्धि हुई।

बैंक समूहों में प्रसारण से संकेत मिलता है कि मई 2022 से फरवरी 2024 के दौरान बकाया ऋणों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में जमा और उधार दरों में वृद्धि अधिक थी (चार्ट IV.9)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उधार दरें निजी बैंकों की तुलना में कम बनी रहीं, जबकि उनकी जमा दरें अधिक थीं।

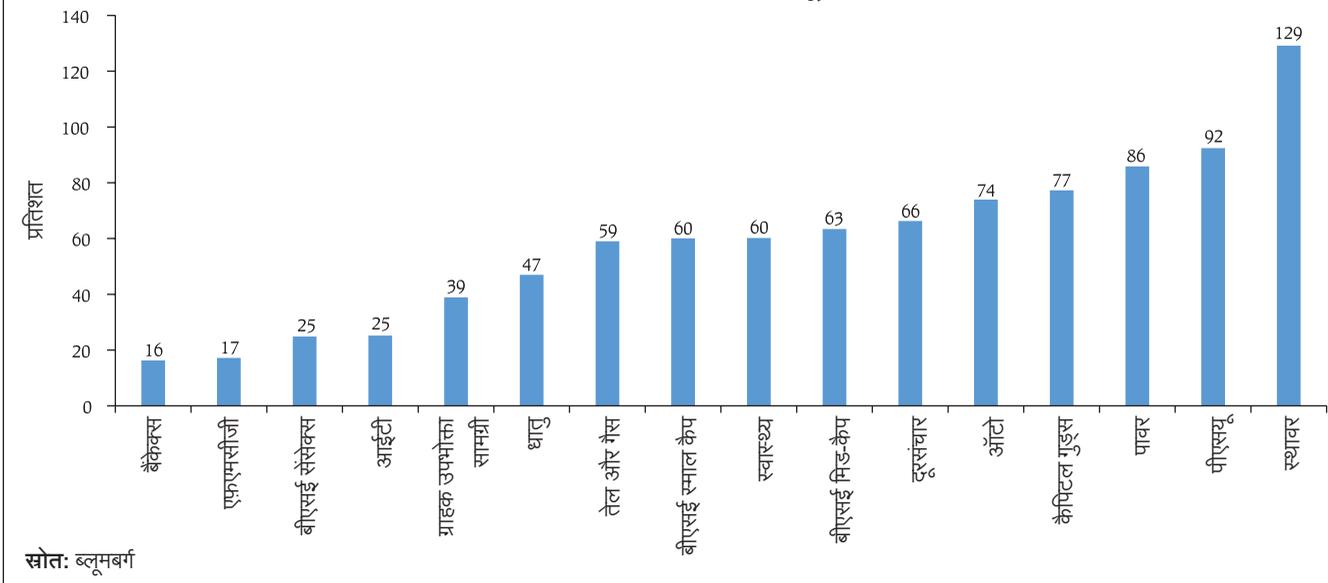
चार्ट IV.9: बैंक समूहों के बीच संचरण (मई 2022 से फरवरी 2024)



08 मार्च, 2024 को भारत सरकार ने 2024-25 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। तुलनात्मक परिपक्वता की जी-सेक प्रतिफल में कमी के आधार पर, घोषित दरें अब सूत्र-आधारित दरों के अनुरूप हैं। हालाँकि, वे सार्वजनिक भविष्य निधि और 5-वर्षीय आवर्ती जमा खातों के लिए कम रहीं।¹⁸

फेड की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले सतर्कता के बीच मार्च के दूसरे पखवाड़े में घरेलू इक्विटी बाजारों में गिरावट आई, लेकिन बाद में यूएस फेड से नरम संकेतों के बाद इसमें सुधार हुआ। इक्विटी बाजारों ने 2023-24 में सभी क्षेत्रों में शानदार बढ़त देखी, जिसमें रियल्टी और पीएसयू सूचकांकों ने अधिकतम लाभ दर्ज किया (चार्ट IV.10)। बाजारों ने नए वित्तीय वर्ष की

चार्ट IV.10: 2023-24 में इक्विटी बाजार सूचकांकों का प्रदर्शन

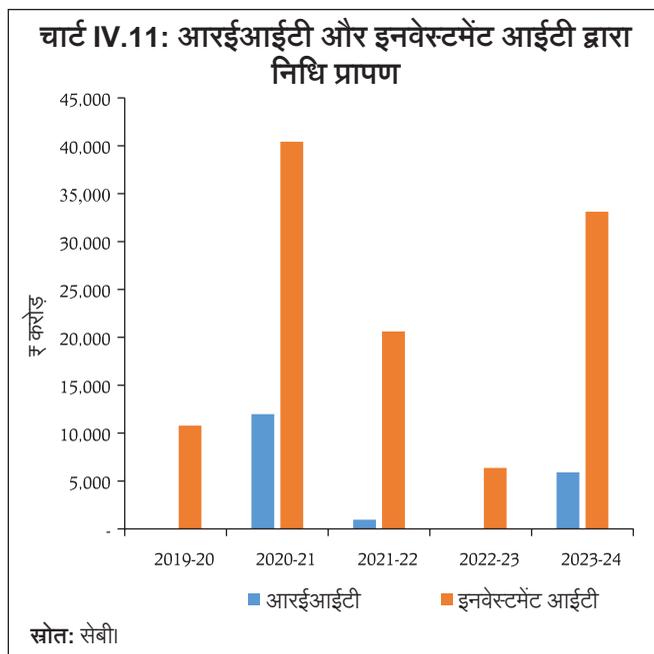


¹⁸ मौद्रिक नीति रिपोर्ट- अप्रैल 2024.

शुरुआत सकारात्मक तरीके से की और मजबूत घरेलू और वैश्विक सूक्ष्म-आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ कॉरपोरेट आय सीजन को लेकर आशावाद के बीच नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि, इसके बाद अमेरिका में उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद नकारात्मक वैश्विक संकेतों को देखते हुए बाजारों में गिरावट आई। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 15 मार्च, 2024 से 0.6 प्रतिशत बढ़कर 19 अप्रैल, 2024 को 73,088 पर बंद हुआ।

भारत स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) को अपनाने में देर कर रहा है; हालांकि, बाजार फल-फूल रहा है - आरईआईटी और इनविट ने 2019-20 (मार्च 2024 तक) से ₹1.3 लाख करोड़ जुटाए हैं [चार्ट IV.11]। मार्च में एक इनविट की लिस्टिंग हुई, जिसने विदेशी निवेशकों से पर्याप्त रुचि आकर्षित करते हुए सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से ₹2,500 करोड़ जुटाए।¹⁹

सेबी ने इन हाइब्रिड लिखतों में अधिक से अधिक खुदरा भागीदारी को सक्षम करने के लिए न्यूनतम निवेश आकार और ट्रेडिंग लॉट को क्रमिक रूप से कम किया है। इस क्षेत्र को और



¹⁹ <https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/fpis-lap-up-reits-invits-wrap-up-earlier-commitments/articleshow/108477719.cms?from=mdr>

विकसित करने के लिए, बाजार नियामक ने 8 मार्च, 2024 को छोटे और मध्यम आरईआईटी²⁰ के लिए विनियमन अधिसूचित किए। इससे एक विनियमित वित्तीय उत्पाद के रूप में स्थावर संपदा आस्तियों की एक विस्तृत शृंखला में समेकित किए गए निवेश की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत में आरईआईटी के और विकास में मदद मिलेगी।

भारत ने 28 मार्च 2024 से प्रभावी सीमित स्क्रिप के लिए नकदी इक्विटी बाजारों में मौजूदा टी+1 निपटान चक्र के अलावा, वैकल्पिक आधार पर टी+0 रोलिंग निपटान चक्र का बीटा संस्करण लाया गया है।²¹ यह वैश्विक वित्तीय बाजारों के सापेक्ष निपटान और समाशोधन समय सीमा की प्रगति में एक मील का पत्थर है, जो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (एमआईआई) के वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) द्वारा इक्विटी क्षेत्र में निवेश ने मार्च 2024 में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो इक्विटी-उन्मुख एमएफ योजनाओं में, विशेष रूप से हाल की अवधि में स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं में (चार्ट IV.12) लगातार निवल प्रवाह के कारण हुआ²²। इन योजनाओं के पोर्टफोलियो की चलनिधि प्रोफाइल के दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि मिडकैप योजनाएं अचानक मोचन दबावों का सामना करने के लिए स्मॉलकैप योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं।²³

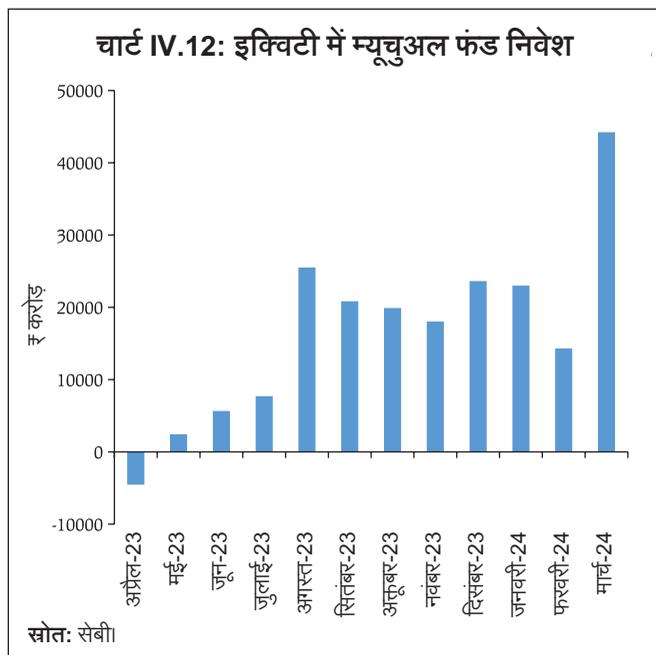
अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 65.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 66.8 बिलियन

²⁰ https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/mar-2024/securities-and-exchange-board-of-india-real-estate-investment-trusts-amendment-regulations-2024_82138.html

²¹ https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/mar-2024/introduction-of-beta-version-of-t-0-rolling-settlement-cycle-on-optional-basis-in-addition-to-the-existing-t-1-settlement-cycle-in-equity-cash-markets_82455.html

²² https://www.business-standard.com/markets/mutual-fund/mutual-funds-pump-record-rs-45-000-crore-into-domestic-stocks-in-march-124040200995_1.html

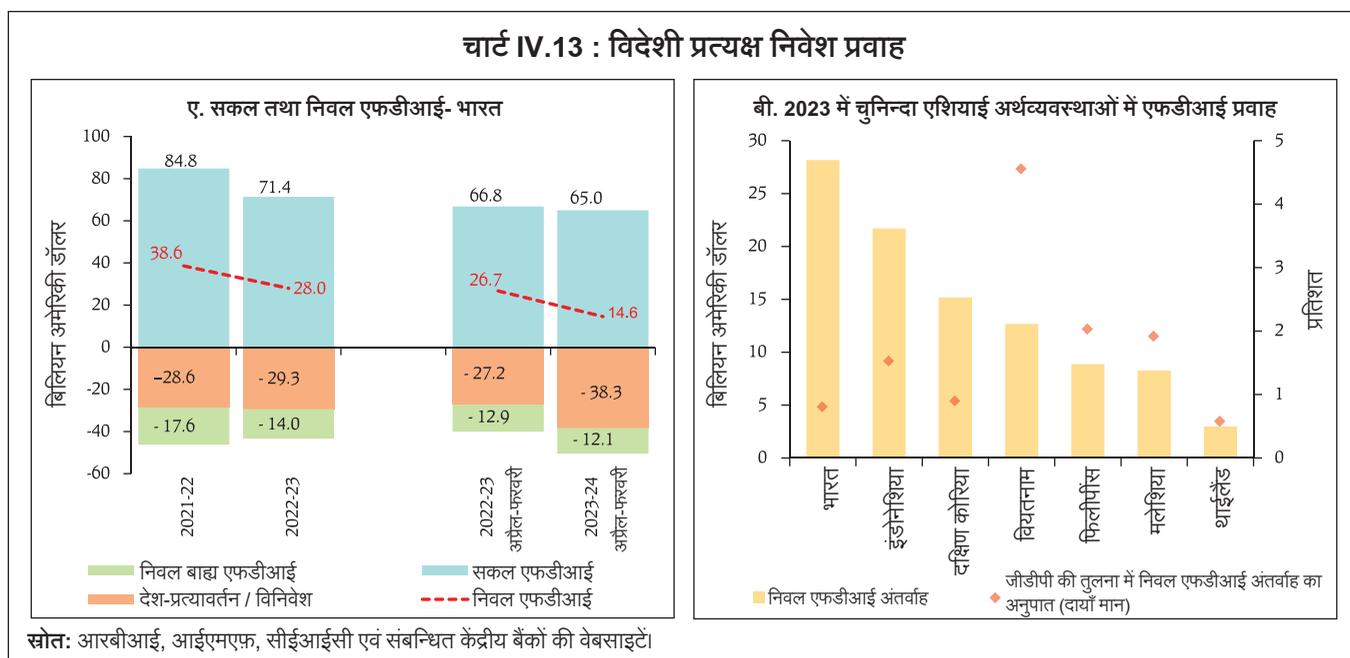
²³ <https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/stress-test-of-mutual-funds-winners-and-losers-in-round-1-12469231.html>



अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.13a)। 60 प्रतिशत से अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा, खुदरा और थोक व्यापार और वित्तीय सेवाओं का रहा है। इसके प्रमुख स्रोत देश सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका,

नीदरलैंड, जापान और यूई थे, जिनका प्रवाह लगभग 80 प्रतिशत था। अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान निवल एफडीआई 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि एक साल पहले यह 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन में वृद्धि थी।

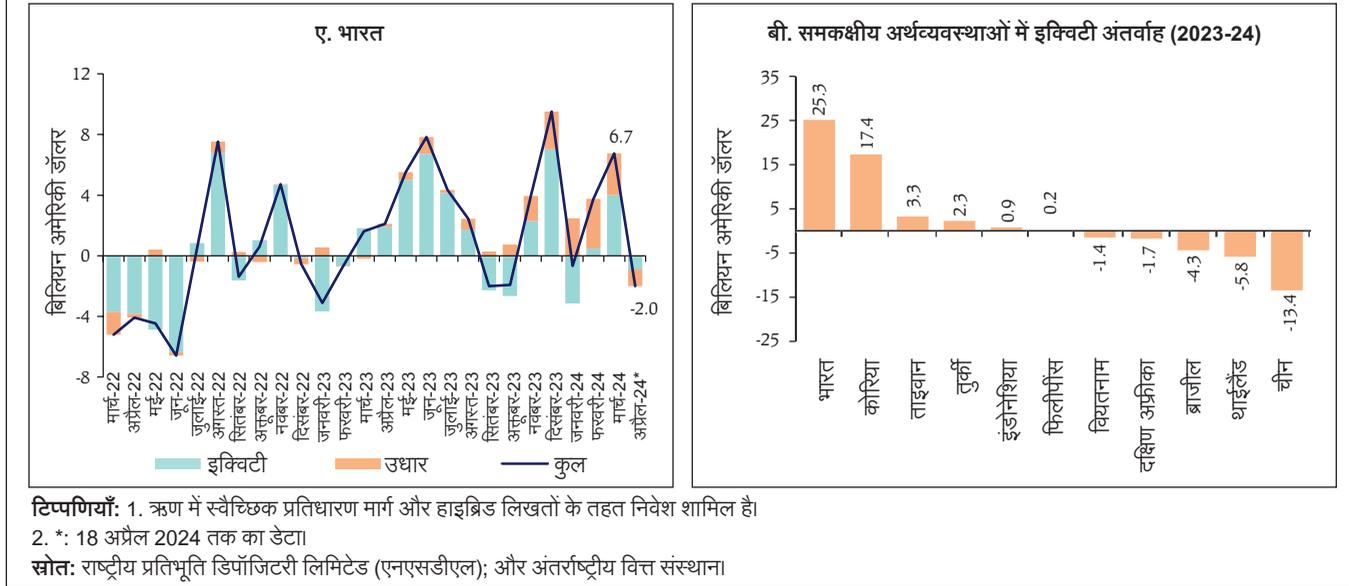
यूनसीटीएडी की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2023 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 2022 की तुलना में मामूली वृद्धि होगी, जो दो यूरोपीय देशों द्वारा संचालित होगी²⁴; हालांकि, इन देशों को छोड़कर, 2023 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में लगभग 18 प्रतिशत की गिरावट आएगी। अनिश्चित वैश्विक निवेश वातावरण के बीच, भारत ने 2023 में समकक्षीय एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक अनुकूल निवेश क्षेत्र गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी (चार्ट IV.13बी)। 2024 के एफडीआई विश्वास सूचकांक²⁵ में ईएमई के बीच भारत चौथे स्थान पर रहा, जो इसकी विकास क्षमता पर निरंतर आशावाद को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ एक व्यापार और आर्थिक



²⁴ यूएनसीटीएडी वैश्विक निवेश प्रवृत्ति निगरानी (जनवरी 2024) के अनुसार, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड सहित कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में उच्च एफडीआई प्रवाह के कारण, 2023 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2022 की तुलना में मामूली रूप से 3 प्रतिशत बढ़ा।

²⁵ कियर्नी की ग्लोबल बिजनेस पॉलिसी काउंसिल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार।

चार्ट IV.14 : निवल पोर्टफोलियो निवेश



भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें निवेश प्रतिबद्धताएं शामिल हैं¹²⁶

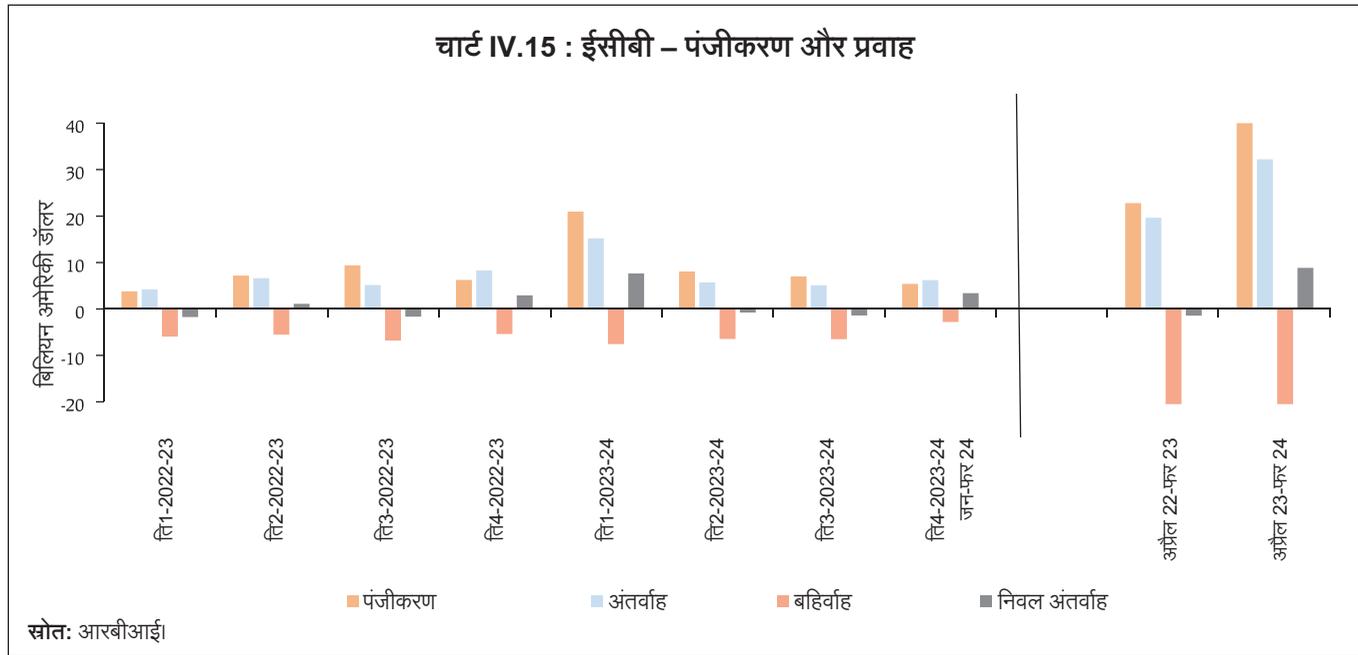
मार्च 2024 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह सकारात्मक रहा। मार्च 2024 में निवल एफपीआई अंतर्वाह 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें इक्विटी (4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और ऋण (2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दोनों क्षेत्रों में अंतर्वाह था (चार्ट IV.14ए)। संचयी रूप से, 2023-24 में निवल एफपीआई अंतर्वाह 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2015-16 के बाद से सबसे अधिक था। ऋण खंड में 2023-24 के दौरान 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो 2018-19 के बाद से सबसे अधिक है, जबकि इक्विटी खंड में निवल एफपीआई अंतर्वाह 25.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है (चार्ट IV.14बी)। वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, स्वास्थ्य सेवा और पूंजीगत सामान 2023-24 के दौरान इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे। अप्रैल 2024 में (18 अप्रैल तक), निवल एफपीआई बहिर्वाह 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।

¹²⁶ हाल ही में ईएफटीए (जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिक्टेंस्टीन और आइसलैंड शामिल हैं) के साथ हस्ताक्षरित टीईपीए में आगामी 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की प्रतिबद्धता शामिल है।

अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान अनिवासी जमाराशियों में निवल वृद्धि 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जो एक वर्ष पहले की 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि से अधिक है, जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर(बी)] खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों [एनआर(ई)ए] में निवल वृद्धि में बढ़ोतरी है।

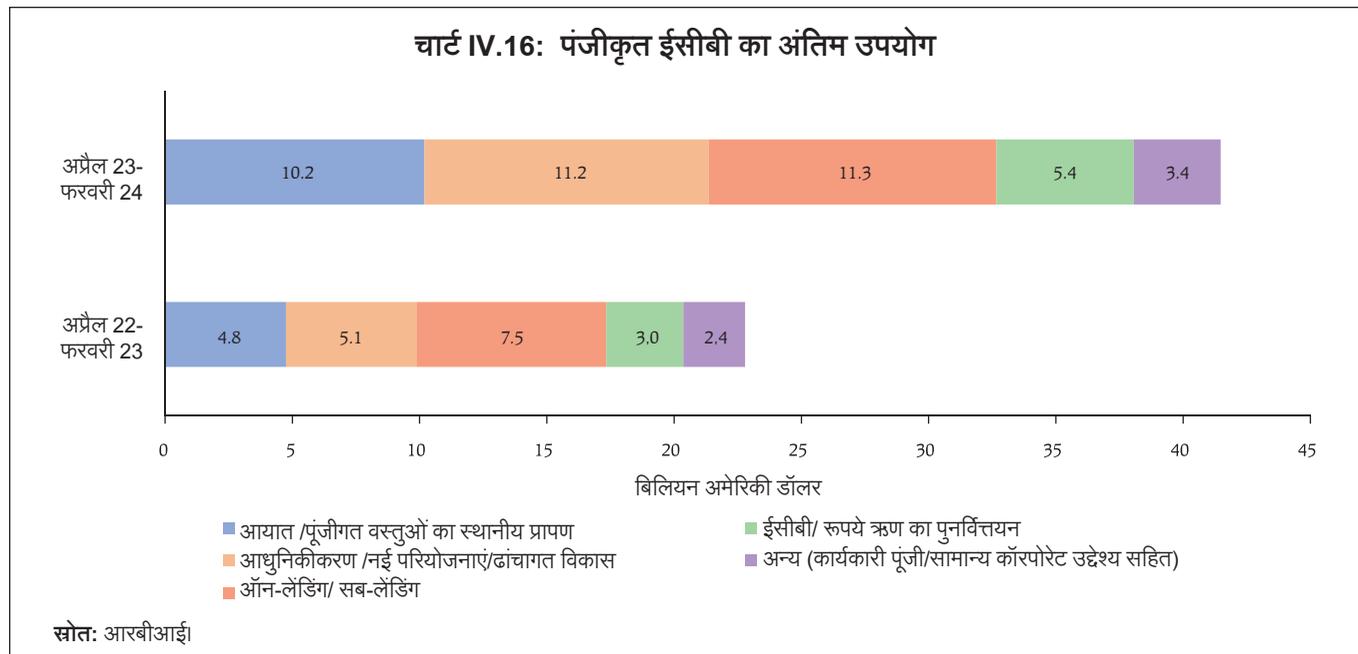
2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान अब तक (फरवरी तक), बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था और लगातार दो तिमाहियों में ऋणात्मक प्रवाह के बाद निवल ईसीबी धनात्मक हो गया। संचयी आधार पर, 2023-24 के पहले ग्यारह महीनों के दौरान ईसीबी पंजीकरण (41.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और सकल संवितरण (32.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे। निवल आधार पर, ईसीबी प्रवाह 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में निवल बहिर्वाह 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.15)।

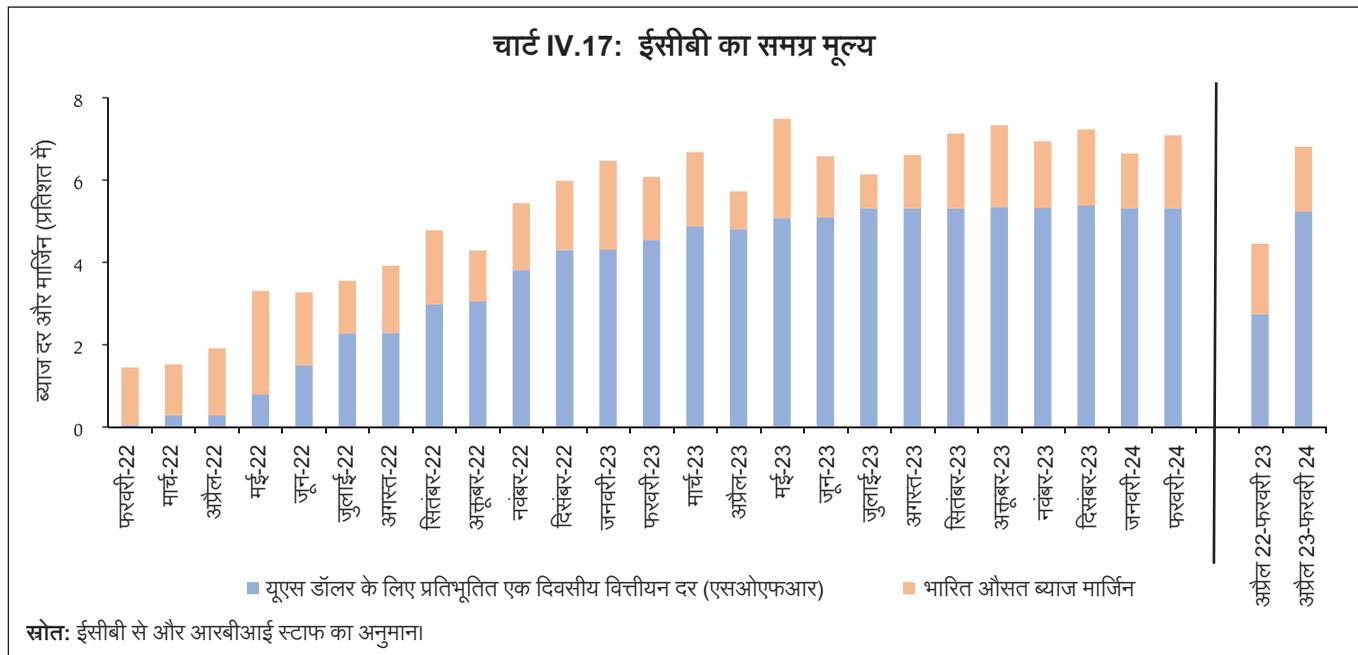
अप्रैल 2023 - फरवरी 2024 के दौरान पंजीकृत कुल ईसीबी में से लगभग 80 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (उधार और उप-उधार सहित) से संबंधित थे [चार्ट IV.16]।



वैश्विक बेंचमार्क दरें जैसे कि प्रतिभूतिकृत एक दिवसीय वित्तीय दर (एसओएफआर) स्थिर हो गई हैं, हालांकि वे ऊंचे स्तर पर हैं। हालांकि, बेंचमार्क दरों पर मासिक भारित औसत ब्याज मार्जिन (डबल्यूएआईएम) बेंचमार्क दरों के सापेक्ष जुलाई 2023 से 0.83-1.98 प्रतिशत की व्यापक सीमा में चला गया है (चार्ट IV.17)।

भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि के कारण अक्तूबर-दिसंबर 2023 के दौरान भारत का निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर (-) 370.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट IV.18)। परिणामस्वरूप, भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय देयताओं से अनुपात दिसंबर 2023 में

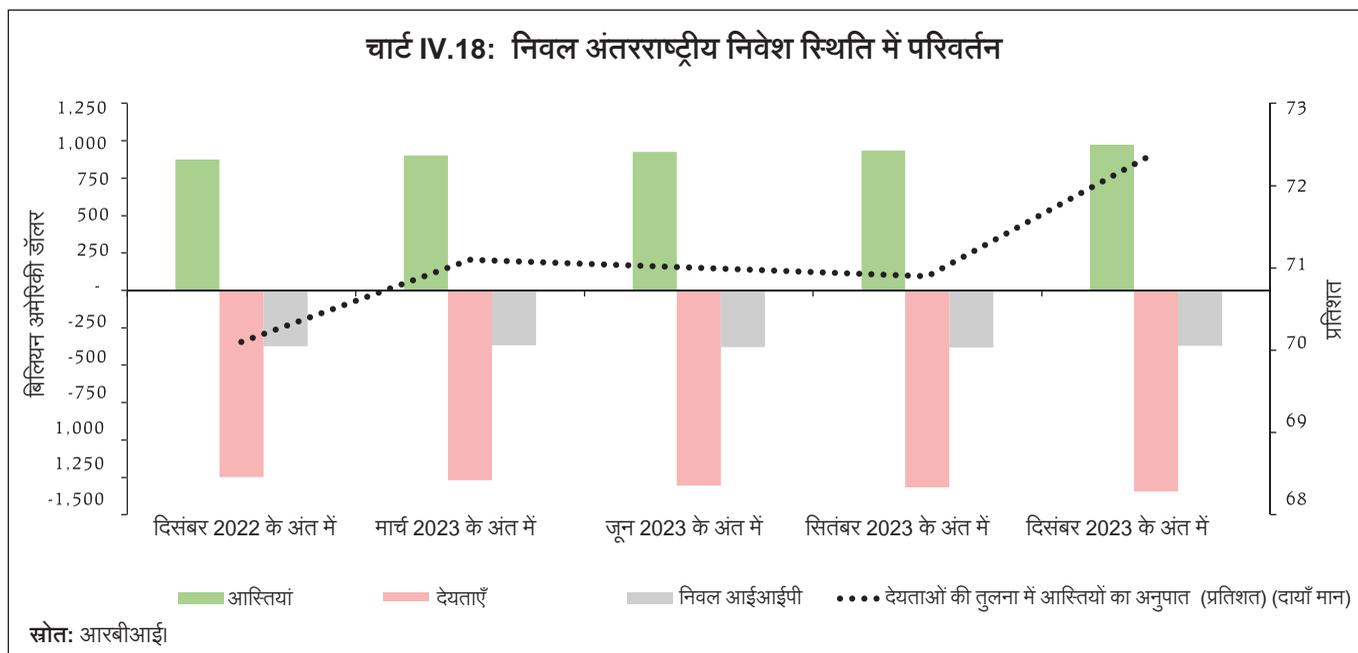




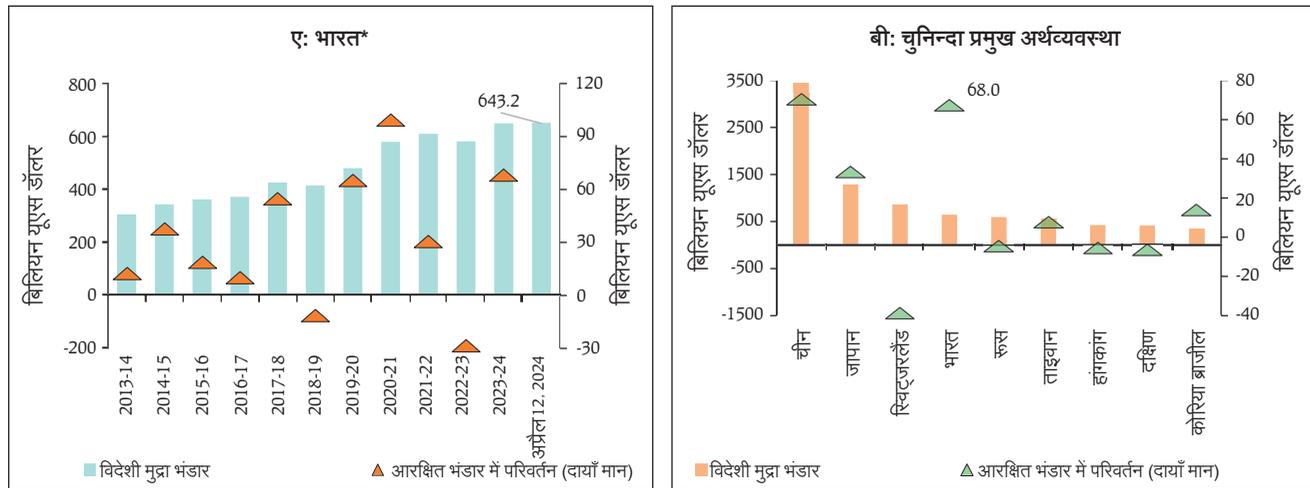
72.4 प्रतिशत हो गया, जो एक तिमाही पहले 70.9 प्रतिशत था। 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान आरक्षित आस्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि (34.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दर्ज की गई और दिसंबर 2023 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों में इनका हिस्सा 63.9 प्रतिशत रहा।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अप्रैल, 2024 को 648.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच

गया। 12 अप्रैल, 2024 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 643.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो दिसंबर 2023 के अंत में बकाया कुल विदेशी ऋण के 99 प्रतिशत को कवर करने के लिए पर्याप्त है। (चार्ट IV.19ए)। 2023-24 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 68.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो प्रमुख विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है (चार्ट IV.19बी)।



चार्ट IV.19: विदेशी मुद्रा भंडार



टिप्पणियाँ: 1. *: वित्तीय वर्ष का डेटा मार्च के अंत का है।
 2. *: भारत और रूस के लिए डेटा अप्रैल, 2024 के लिए है, स्विट्जरलैंड और हांगकांग के लिए 12 फरवरी के अंत और शेष देशों के लिए मार्च के अंत के लिए है।
स्रोत: आरबीआई; और संबंधित केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

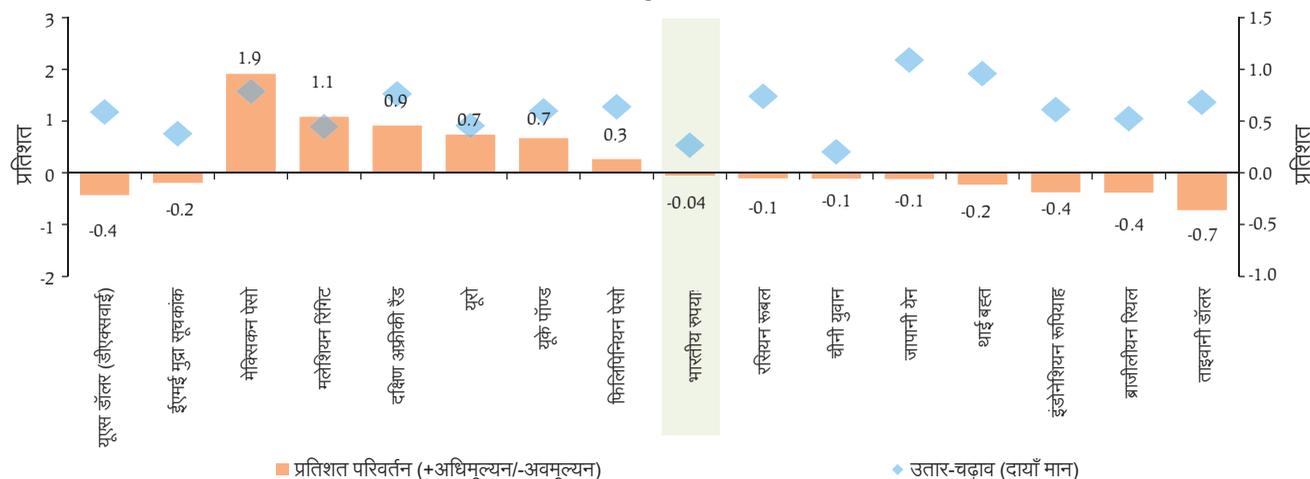
मार्च 2024 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया (आईएनआर) में 0.04 प्रतिशत (मासिक) की मामूली गिरावट आई, जबकि यह सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक बनी रही (चार्ट IV.20)।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) की तुलना में भारतीय रुपये में 0.3 प्रतिशत (मासिक) की गिरावट

आई है क्योंकि ऋणात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर ने मार्च 2024 में नाममात्र प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये की वृद्धि को ऑफसेट कर दिया है (चार्ट IV.21)।

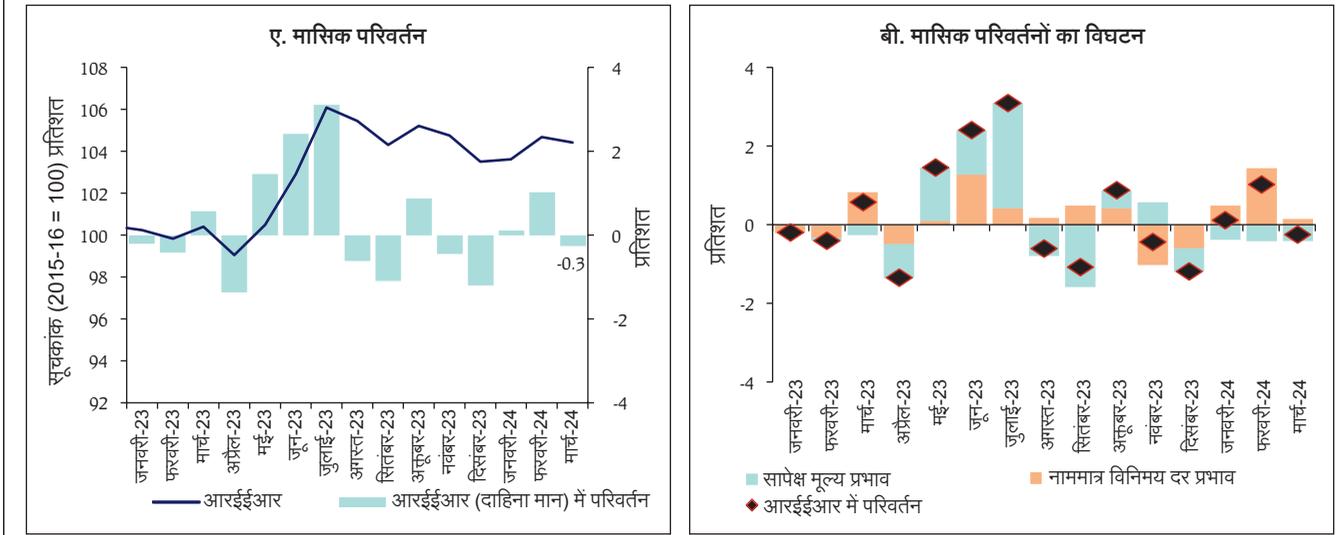
भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो 2023-24 की दूसरी तिमाही में 1.3 प्रतिशत और 2022-23

चार्ट IV.20: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (फरवरी 2024 की तुलना में मार्च 2024 में)



टिप्पण: अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) की एक टोकरी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव को मापता है।
स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट IV.21 : 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वियोजन

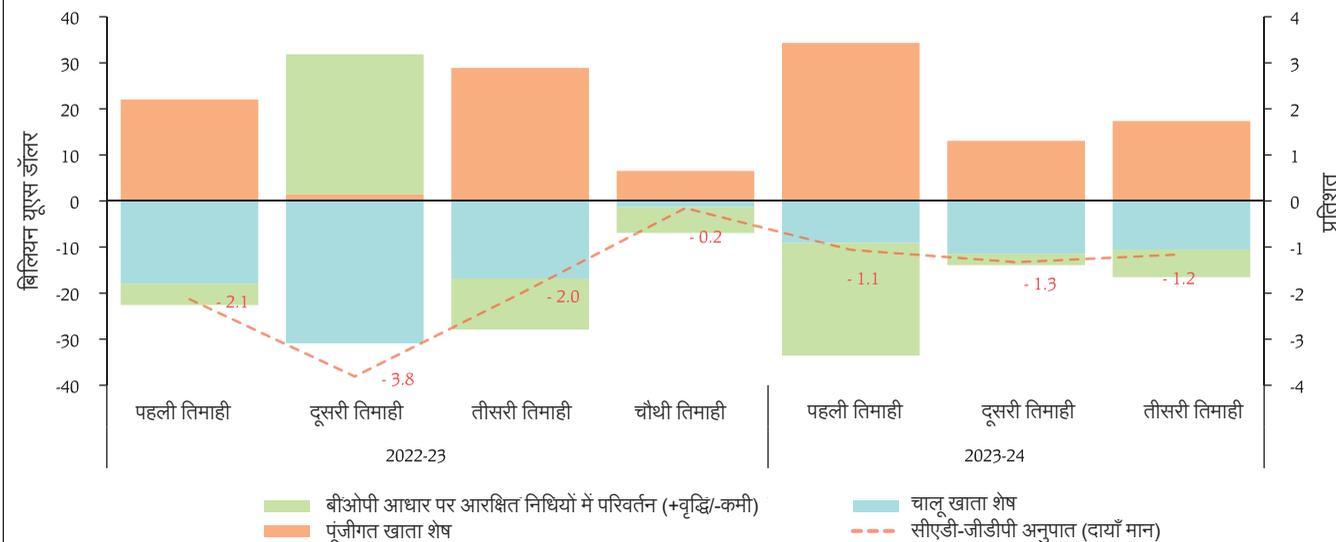


स्रोत: आरबीआई

की तीसरी तिमाही में 2.0 प्रतिशत था। मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत विप्रेषण प्राप्तियों ने 2023-24 की तीसरी तिमाही में चालू खाते पर माल आयात दबाव को कम किया। निवल पूंजी प्रवाह सीएडी से अधिक हो गया, जिसे मजबूत एफपीआई और बैंकिंग पूंजी का समर्थन प्राप्त था, जिससे तिमाही के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 6.0 बिलियन की वृद्धि हुई (चार्ट IV.22)।

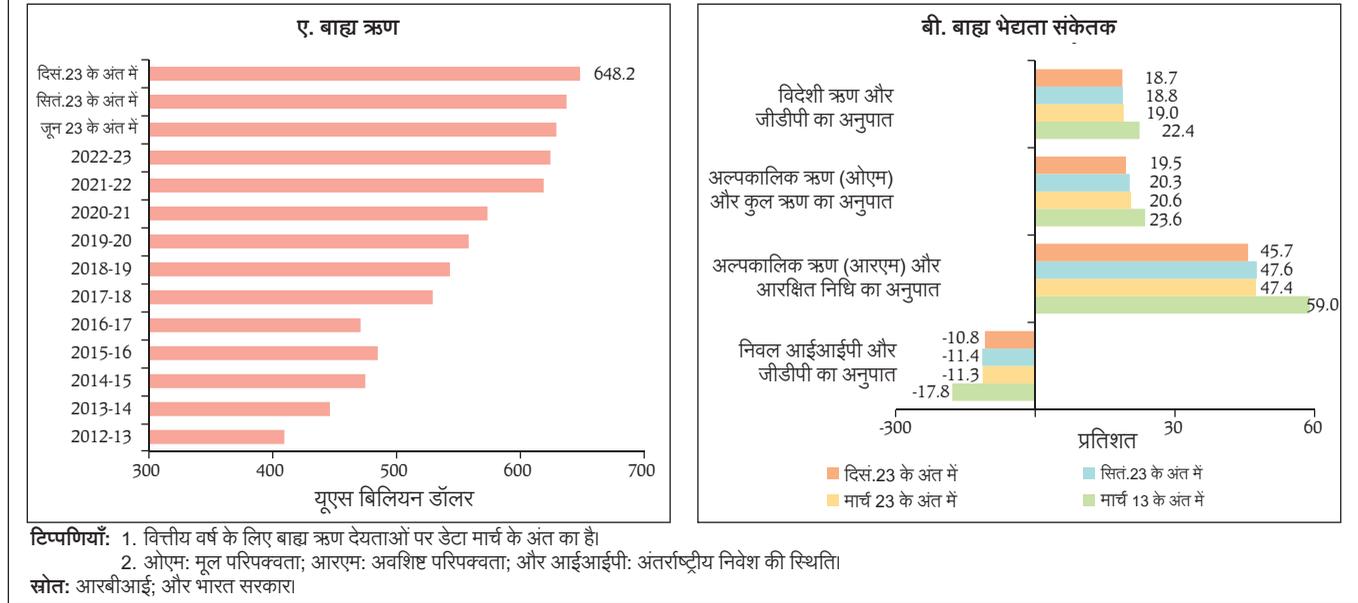
दिसंबर 2023 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण 648.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.23ए); दिसंबर 2023 के अंत में विदेशी ऋण से जीडीपी अनुपात घटकर 18.7 प्रतिशत हो गया (सितंबर 2023 के अंत में यह 18.8 प्रतिशत था)। भारत के बाहरी क्षेत्र ने सुदृढ़ता प्रदर्शित किया, जो दिसंबर 2023 के अंत में प्रमुख भेद्यता संकेतकों के स्थायी स्तरों द्वारा दर्शाया गया है (चार्ट IV.23बी)।

चार्ट IV.22 : भारत का भुगतान शेष



स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.23 : बाह्य क्षेत्रक दुर्बलता संकेतक: भारत



भुगतान प्रणालियाँ

मार्च 2024 में विभिन्न भुगतान माध्यम में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई, जिसकी अगुवाई एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) [सारणी IV.3] के माध्यम से खुदरा लेनदेन ने की। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बड़े मूल्य के लेनदेन ने मात्रा और मूल्य के दृष्टिकोण से त्वरित वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दिखाई। यूपीआई ने मार्च 2024 में 13.4 बिलियन लेनदेन का महत्वपूर्ण पड़ाव

पार किया, जिससे इसकी संख्या में एक और बिलियन जुड़ गया। खुदरा क्षेत्र में मोबाइल लेनदेन में लगातार वृद्धि का देखा गया, जो व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन से प्रेरित था, जो एक साल पहले 55.6 प्रतिशत की तुलना में कुल मात्रा का 61.7 प्रतिशत था। यह उछाल ₹500 तक की लेन-देन श्रेणी में आया, जिससे औसत यूपीआई लेन-देन के आकार में गिरावट आई।²⁷ इससे छोटे व्यापारी आउटलेट्स पर डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि का संकेत मिला। बीबीपीएस के तहत, लेन-देन के लिए औसत टिकट आकार मार्च 2024 में 45.7 प्रतिशत

सारणी 7 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्ष दर वर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा				लेनदेन मूल्य			
	फर -23	फर -24	मार्च-23	मार्च-24	फर -23	फर -24	मार्च-23	मार्च-24
आरटीजीएस	11.2	18.8	7.8	12.3	16.7	21.2	11.5	12.4
एनईएफटी	28.7	47.3	26.8	45.2	12.1	25.1	7.4	15.2
यूपीआई	66.4	60.6	60.0	55.3	49.5	47.9	46.3	40.8
आईएमपीएस	6.4	19.4	1.0	16.8	21.9	21.2	18.2	16.2
एनएसीएच	67.3	13.1	22.2	22.8	35.2	15.6	35.0	15.8
एनईटीसी	18.4	12.1	13.3	10.6	29.0	19.2	23.7	17.2
बीबीपीएस	54.1	29.8	56.5	25.4	63.4	85.8	61.6	82.8

नोट: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा; एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई।

²⁷ मार्च 2024 में औसत टिकट आकार में 9.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की गिरावट आई।

बढ़ा, जो लेन-देन के मूल्य में तेज वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) के कारण हुआ। फरवरी 2024 में, क्रेडिट कार्ड लेन-देन की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 34.0 प्रतिशत और 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एससीबी के बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या फरवरी 2024 में 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई (एससीबी के कुल क्रेडिट खातों की संख्या के 26.6 प्रतिशत के बराबर²⁸)। 2023-24 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, व्यक्तिगत ऋणों में लगभग 14.6 प्रतिशत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) क्रेडिट कार्ड पर लेन-देन (मूल्य के संदर्भ में) के कारण रही है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड (एनआईपीएल) ने नेपाल की फोनपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में अब दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई को चालू कर दिया है। इससे भारतीय उपभोक्ता क्यूआर कोड के माध्यम से नेपाल में कई व्यापारिक स्थानों पर पी2एम भुगतान कर सकेंगे।

2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से नकद जमा की सुविधा देने और तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) तक यूपीआई की पहुँच बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों को उपयोगकर्ता पहुँच बढ़ाने और विविधता लाने तथा सीबीडीसी प्लेटफॉर्म की लोचनीयता जाँचने के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) वॉलेट प्रदान करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव रखा।

V. निष्कर्ष

इस पृष्ठभूमि में, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 3-5 अप्रैल, 2024 के दौरान बैठक की और समायोजन वापस लेने के रुख के साथ नीति दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए मतदान किया। उम्मीद है कि सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून कृषि गतिविधि को बढ़ावा देगा, जबकि विनिर्माण लाभप्रदता को बनाए रखेगा और सेवा गतिविधि

²⁸ दिसंबर 2023 तक, बैंकिंग सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर-1)।

संभवतः महामारी-पूर्व प्रवृत्ति से ऊपर बढ़ेगी। मांग की स्थितियों के संबंध में, एमपीसी ने उम्मीद जताई कि ग्रामीण गतिविधि में और तेजी आने और उपभोक्ता विश्वास में सुधार के साथ स्थिर शहरी मांग से निजी खपत में तेजी आएगी। समिति ने महसूस किया कि व्यावसायिक आशावाद, स्वस्थ कॉरपोरेट और बैंक तुलन पत्र, मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय और निजी पूंजीगत व्यय चक्र में तेजी के संकेतों के साथ निश्चित निवेश की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। नकारात्मक पक्ष पर, इसने भू-राजनीतिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, भू-आर्थिक विखंडन, लाल सागर में बढ़ते व्यवधान और कठोरतम मौसम की घटनाओं से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों पर ध्यान दिया। यह अनुमान लगाते हुए कि जोखिम समान रूप से संतुलित हैं, एमपीसी ने 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया और इसके संभावित विकास के लिए एक तिमाही मार्ग निर्धारित किया। इसके अलावा, अपने आकलन में, खाद्य मूल्य अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण पर दबाव डालना जारी रखती हैं, साथ ही जलवायु आघातों की बढ़ती घटनाएं खाद्य कीमतों के लिए एक प्रमुख जोखिम हैं। इसने कहा कि सामान्य मानसून के शुरुआती संकेत खरीफ मौसम के लिए अच्छे हैं। दूसरी ओर, फर्मों द्वारा सामना किए जाने वाले लागत दबाव में वृद्धि देखी जा रही है और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से मुद्रास्फीति के आगे बढ़ने का जोखिम बढ़ रहा है। तदनुसार, एमपीसी ने 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.5 प्रतिशत पर जोखिम के साथ संतुलित करने का अनुमान लगाया।

एमपीसी के अनुसार, मजबूत निवेश मांग और उत्साहित व्यापार और उपभोक्ता भावनाओं के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधि सुदृढ़ बनी हुई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर के शिखर से नीचे आ गई है; हालांकि, खाद्य मूल्य दबाव जारी अवस्फीति प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, जबकि प्रतिकूल जलवायु घटनाओं और भू-राजनीतिक दबावों से उत्पन्न आघातों ने दृष्टिकोण में अनिश्चितताएं जोड़ दी हैं। इस माहौल में, एमपीसी ने संकल्प लिया कि मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचने तक मुद्रास्फीति के अवस्फीति के मार्ग को बनाए रखने की

आवश्यकता है। मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने के लिए मौद्रिक नीति को सक्रिय रूप से अपस्फीतिकारक बने रहना चाहिए क्योंकि मूल्य स्थिरता विकास की नींव रखती है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के शब्दों में, "अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में यह आवश्यक है कि सीपीआई मुद्रास्फीति निरंतर कम होती

रहे और टिकाऊ आधार पर लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, हमारा कार्य अधूरा है... हमारा प्रयास स्थायी आधार पर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे उच्च विकास की निरंतर अवधि का मार्ग प्रशस्त हो... हमारा लक्ष्य दृष्टि में है और हमें सतर्क रहना चाहिए"।²⁹

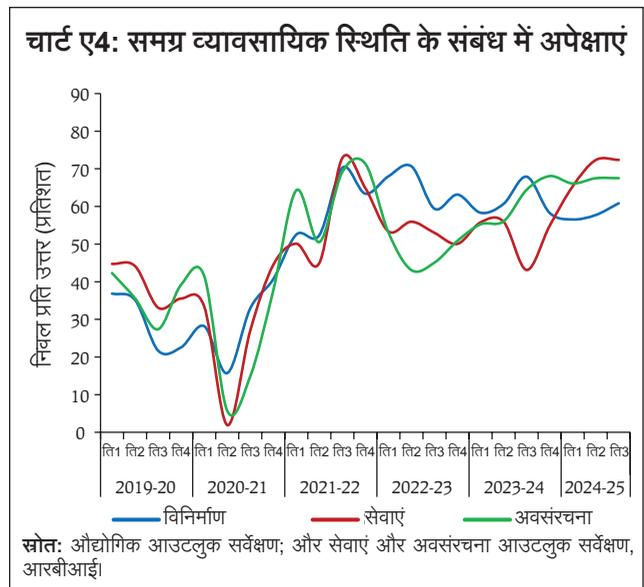
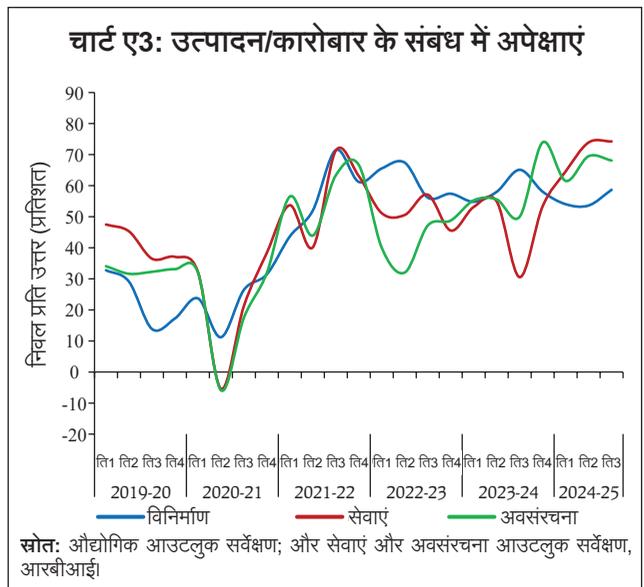
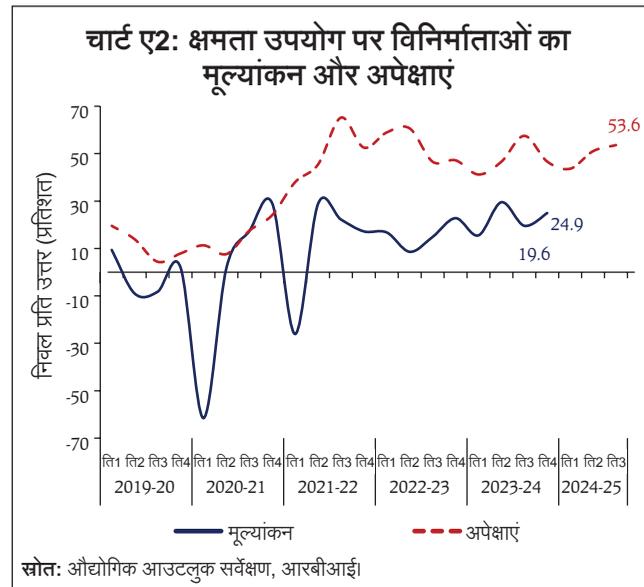
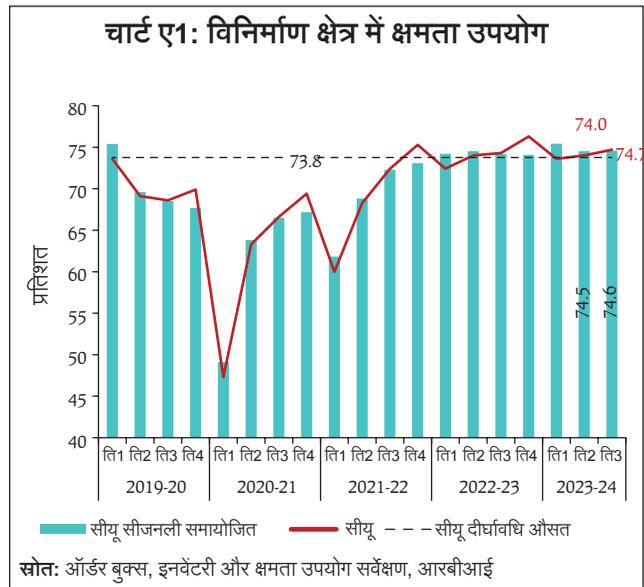
²⁹ गवर्नर का वक्तव्य: 5 अप्रैल, 2024, द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2024-2025।

अनुलग्नक 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षणों से प्रमुख निष्कर्ष

वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान आयोजित रिज़र्व बैंक के तिमाही उद्यम सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) 2023-24 की दूसरी तिमाही के 74.0 प्रतिशत के स्तर से 2023-24 की तीसरी तिमाही में 74.7 प्रतिशत हो गया, जिसमें मौसमी रूप से समायोजित सीयू 10 बीपीएस बढ़कर 74.6 प्रतिशत हो गया।
- विनिर्माताओं ने आगामी तिमाहियों में सी.यू. पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है (चार्ट ए1 और चार्ट ए2)।

- विनिर्माण फर्मों को उम्मीद है कि 2024-25 की पहली तिमाही में मौसमी नरमी के बाद 2024-25 की तीसरी तिमाही में उत्पादन आशावाद में सुधार होने का अनुमान है।
- अगली तीन तिमाहियों में सेवा कंपनियों के टर्नओवर का पूर्वानुमान अत्यधिक सकारात्मक है (चार्ट A3)।
- सेवा क्षेत्र की कंपनियों के बीच समग्र कारोबारी भावनाएं 2024 के अंत तक अत्यधिक आशावादी बनी रहेंगी (चार्ट A4)।



(Contd..)

अनुलग्नक 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षणों से प्रमुख निष्कर्ष

